(1100/NK/KMR)

1102 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

"श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र" ट्रस्ट के निर्माण के संबंध में घोषणा संबंधी वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष : माननीय प्रधान मंत्री जी।

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके बीच, देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विषय पर जानकारी देने के लिए विशेष तौर पर उपस्थित हूं। यह विषय करोड़ों देशवासियों की तरह ही मेरे हृदय के भी करीब है और इस पर बात करना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। यह विषय श्रीराम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। यह विषय अयोध्या में श्रीराम जन्मस्थली पर भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 नवम्बर, 2019 को मैं करतरपुर साहब कॉरिडोर के लोकार्पण हेतु पंजाब में था। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व था, बहुत ही पवित्र वातावरण था। उसी दिव्य वातावरण में मुझे देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा श्रीराम जन्मभूमि विषय पर दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बारे में पता चला था। इस फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि श्रीराम जन्मभूमि के विवादित स्थल के भीतरी और बाहरी आंगन पर रामलला विराजमन का ही स्वामित्व है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि केन्द्र और राज्य सरकार आपस में परामर्श करके सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन आबंटित करें।

(1105/SK/SNT)

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आज इस सदन को, पूरे देश को यह बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्रीराम जन्मस्थली पर भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए, और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' इसका नाम होगा। 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्रीराम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्रीराम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सर्वोच्च अदालत के आदेशानुसार गहन विचार-विमर्श और संवाद के बाद अयोध्या में पांच एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आबंटित करने का अनुरोध उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया। इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

माननीय अध्यक्ष जी, भारत की प्राण वायु में, भारत के आदर्शों में, भारत की मर्यादाओं में, भगवान श्रीराम की महत्ता और अयोध्या की ऐतिहासिकता से, अयोध्या धाम की पवित्रता से हम सभी भली भांति परिचित हैं।

अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण, वर्तमान और भविष्य में राम लला के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या, और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मेरी सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या में कानून के तहत अधिग्रहित सम्पूर्ण भूमि जो लगभग 67.703 एकड़ है, और जिसमें भीतरी और बाहरी आंगन भी सम्मिलित है, उसे नवगठित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 नवंबर को राम जन्मभूमि पर फैसला आने के बाद सभी देशवासियों ने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर पूर्ण विश्वास जताते हुए बहुत ही परिपक्वता का उदाहरण दिया था। मैं आज सदन में देशवासियों के इस परिपक्व व्यवहार की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमें वसुधैव कुटुम्बकम् और सर्वे भवन्तु सुखिन: का दर्शन देती हैं और इसी भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं।

(1110/MK/GM)

हिन्दुस्तान में हर पंथ के लोग चाहे वह हिन्दू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध, पारसी और जैन हों, हम सभी एक बृहत् परिवार के ही सदस्य हैं। इस परिवार के हर सदस्य का विकास हो, वे सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध बनें, देश का विकास हो, इसी भावना के साथ मेरी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र पर चल रही है।

आइए, इस ऐतिहासिक क्षण में, हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में श्रीराम धाम के जीर्णोद्धार के लिए, भव्य राम मन्दिर के निर्माण के लिए एक स्वर में अपना समर्थन दें।

.....

(प्रश्न 41)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल, प्रश्न संख्या 41

श्री टी.आर.बालू जी – उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी।

…(व्यवधान)

श्री कोडिकुन्निल सुरेश (मावेलीक्करा): स्पीकर सर, मेरा एडजर्नमेंट मोशन है।

माननीय अध्यक्ष: मैं सभी एडजर्नमेंट मोशन शून्य काल में बुलाऊंगा। मैंने आपको बोल दिया न।

…(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, झारखंड में आदिवासियों की हत्या हुई है और कांग्रेस चुप है। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आप सभी को शून्य काल में बोलने का मौका दूंगा। प्लीज, मैंने आपको बोल दिया कि शून्य काल में मौका दूंगा। प्लीज बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। मैं आपको शून्य काल में मौका दूंगा। बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वैश्चेन माननीय मंत्री जी से यह है कि ई-डिजिटल अर्थव्यवस्था के कारण जिन लोगों के डेबिट कार्ड और एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं, जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, क्या ऐसे लोगों की सब्सिडी या किसी अन्य माध्यम से इनके पैसे रिटर्न करने की सरकार की कोई व्यवस्था है?

श्री पीयूष गोयल: वैसे तो यह प्रश्न वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, लेकिन फ्रॉड की अपनी-अपनी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। अगर कोई फ्रॉड कुछ समय के अंदर पकड़ा जाता है तो उसको डेबिट-क्रेडिट कार्ड कंपनी नार्मली रिवर्स करती हैं। लेकिन, इसमें सरकार दखलअंदाजी करे, ऐसी किसी व्यवस्था की संभावना नहीं है।

(इति)

(प्रश्न 42)

श्री लल्लू सिंह (फैजाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या भारत और अमेरिका के बीच पूर्व में भी इस प्रकार के औद्योगिक सुरक्षा समझौता हुआ है? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और पूर्व में हुए समझौते तथा अब हुए समझौते में क्या अंतर है?

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Hon. Speaker Sir, this agreement was signed on 18th December, 2019. The hon. Member seems to ask if there have been any such agreements earlier too. Before this, in 2002, the General Security of Military Information Agreement was signed. That was for classified defence-related information to be shared between governments. As per this agreement, information can now be shared with others also, but exactly through the medium of Government only.

(1115/YSH/RK)

श्री लल्लू सिंह (फैजाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भारत और अमेरिका के बीच में हुए इस समझौते से तकनीकी हस्तांतरण और ज्यादा सक्षम होगा, जिससे यह प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और भारत में बचाव और राहत के कार्यों में मदद करेगा। यदि हाँ तो इसका विवरण क्या है? इस समझौते से दोनों देशों के सैन्य संगठनों के बीच और अधिक समन्वय होगा तथा निर्बाध संचार होगा, यदि हाँ तो इसका विवरण क्या है? आप इसे बताने का कष्ट करें।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, sharing of information is aimed at better coordination between the two countries, particularly on materials which are fairly classified in nature, and as a result there can be better coordination in terms of the Make in India initiatives. That is why this Agreement has more relevance towards sharing of such technology, which will not only boost India's Make in India Programme, but also fulfils the Prime Minister's wish to include Defence as one of the major components of the Make in India programme so that India can also see export of Defence equipment.

(ends)

(प्रश्न 43)

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): सर, धन्यवाद। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत विस्तृत उत्तर दिया है।

माननीय अध्यक्ष : चलिए, फिर तो आगे बढ़ते हैं। आपका जवाब तो हो गया।

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): नहीं सर, मेरा उनसे क्वेश्चन यह है कि एसडीजी में जो गोल 2 है तो हमारे देश के गोल 2 में हंगर फ्री अचीव करने का टारगेट है। इसमें पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, जो पोषण अभियान में भाग नहीं ले रहे हैं तो क्या इससे सरकार को एसडीजी के गोल को अचीव करने में परेशानी हो रही है? अगर परेशानी हो रही है तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई दूसरा उपाय सोचा है, जिससे हम इस लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें?

श्री राव इंद्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, गोल नम्बर 2-जीरो हंगर में न केवल पश्चिम बंगाल, बल्कि देश के अन्दर भी थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। हमने कुल मिलाकर 0 से लेकर 100 नम्बर तक दिए हैं। सबसे कमजोर प्रांत को ज़ीरो मिलता है और जो सबसे अच्छा प्रांत है, उसको 100 नम्बर मिलते हैं। 100 नम्बर का मतलब यह है कि उसने पूरा काम कर लिया है। कुल मिलाकर हिन्दुस्तान की वर्ल्ड रैंकिग 1 से 162 मुल्कों में से 115वीं है। हिन्दुस्तान का इंडेक्स स्कोर 100 में से 61 है, यानी सिर्फ 40 पॉइन्ट लेकर हिन्दुस्तान इसको पूरा कर देता है, जो हमने युनाइटेड नेशन के अन्दर वर्ष 2015 में कमिटमेंट किया था कि सस्टेनेबल गोल को हम वर्ष 2030 तक पूरा कर देंगे। हमने जो इंडेक्स बनाया है, उसमें हर एक प्रांत के लिए भी अलग से सिलसिलेवार जिक्र किया है। हमारा मुल्क विश्व के अन्दर पहला ऐसा मुल्क है, जिसमें न केवल नेशनल लेवल के ऊपर, बल्कि सबनेशनल लेवल के ऊपर भी प्रांतों के मार्फत इस इंडेक्स को तैयार करवाया गया है, जिसके अन्दर काम्पिटैटिव फैडरेलिज्म का जिक्र है और हम काम्पिटिशन के माध्यम से सोचते हैं कि एक दूसरे की देख-रेख करके सभी प्रांतों का स्कोर बेहतरीन बन जाएगा। अगर पश्चिम बंगाल उसके अन्दर शामिल नहीं होता है तो हम उसको सुझाव दे सकते हैं। हम उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं। हमारे बाकी जितने भी प्रांत हैं, यूनियन टैरेटरीज हैं, वे सभी इसके अन्दर भाग ले रही हैं। मुझे विश्वास है कि हिन्दुस्तान आने वाले 10 सालों के अन्दर अपनी कमिटमेंट को वर्ष 2030 तक पूरा कर लेगा।

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा वे बोल रहे है कि उसको सुझाव दे सकते हैं तो इससे हमारे देश में एसडीजी का जो टारगेट है, वह अचीव करने में परेशानी हो रही है। क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बारे में मंत्री जी का कोई प्लान है? सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि अलग राज्य भी हैं, जो सेन्ट्रल प्रोजेक्ट्स को लागू नहीं कर रहे हैं। इनको लागू कौन कर रहा है और राज्यों को जो फंड मिलता है, उसमें अंतर करने का सुझाव क्या केंद्र सरकार के पास है?

श्री राव इंद्रजीत सिंह: भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने 14th फाइनेंस कमीशन की रिकम्नडेशन को सम्पूर्ण रूप से मान लिया था।

(1120/RPS/PS)

उसके माध्यम से प्रान्तों को सेंट्रली डिविजबल पूल ऑफ टैक्सेस में बढ़ोत्तरी करते हुए 32 फीसदी से 42 फीसदी कर दी थी। आज के दिन सेंट्रल डिविजबल पूल ऑफ टैक्सेस में से 42 प्रतिशत पैसा प्रान्तों को वितरित होने लग रहा है, उसके अंदर अभी कोई तरमीम करने के बारे में मैं नहीं समझता हूं कि सरकार ने अभी कुछ सोचा है। अभी तक वही चल रहा है और उस पैसे को ठीक ढंग से खर्च करना प्रान्तों की खुद की जिम्मेदारी है।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा जो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सूचकांक का निर्माण किया गया है, उससे विश्व में अपनी रैंकिंग सुधारने में हम लोगों को सहायता मिलेगी। मंत्रालय द्वारा तीन श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें एक से लेकर 100 प्वाइंट्स हैं। एक से लेकर 49 प्वाइंट्स तक एक श्रेणी है, 50 से लेकर 64 प्वाइंट्स तक दूसरी श्रेणी और 65 से लेकर 100 प्वाइंट्स तक तीसरी श्रेणी है।

मैं माननीय मंत्री जी से दो चीजें जानना चाहता हूं। जो एक से लेकर 49 प्वाइंट्स तक की श्रेणी है, उसमें कितने राज्य हैं, 50 से लेकर 64 प्वाइंट्स तक की श्रेणी में कितने राज्य हैं और 65 से लेकर 100 प्वाइंट्स तक तीसरी श्रेणी में कितने राज्य हैं? मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और बहुत जरूरी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब तक प्रदेश अपने यहां जिलों में इस लक्ष्य को बढ़ाने के लिए, इस लक्ष्य को प्रोत्साहित करने के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक न तो प्रदेश इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, न देश प्राप्त कर पाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेशों को भी ऐसा सूचकांक बनाने के लिए कोई प्रस्ताव किया गया है?

श्री राव इंद्रजीत सिंह: सर, पहले प्रश्न का जवाब यह है कि आठ प्रान्त ऐसे हैं, जो 65 प्वाइंट्स से ऊपर चले गए। पिछले साल जब हमने इसे शुरू किया था, तब केवल तीन प्रान्त ऐसे थे, जो 50 प्वाइंट्स से कम थे, लेकिन 2019 में जब हमने इस इंडेक्स को रिवाइज करके पब्लिश किया, ये तीन प्रान्त भी 50 प्वाइंट्स से ऊपर आ गए हैं, लेकिन 65 प्वाइंट्स से नीचे रह गए हैं। कुल मिलाकर, हमने जो कलर कोडिंग की है, रेड कलर, जिसके अंदर एस्पिरेंट प्रान्त हुआ करते थे, पिछले साल उनकी संख्या तीन थी, इस साल इसमें एक भी नहीं है। जो परफॉर्मर्स हैं, जो यलो कलर में आ गए हैं, अब ज्यादातर प्रान्त यलो कलर में हैं। जैसा मैंने पहले बताया है, सिर्फ आठ प्रान्त ऐसे हैं, जो फ्रण्ट रनर्स यानी ग्रीन कलर कोडिंग के नीचे आते हैं। यह पहले सवाल का जवाब है।

माननीय सदस्य ने जो दूसरा सवाल पूछा है कि क्या हम प्रान्तों को भी यह सुझा सकते हैं कि वे भी इस तरह का इंडेक्स अपने यहां डिस्ट्रिक्टवाइज बनाएं। नीति आयोग के मार्फत से यह प्रयास चल रहा है कि उनको डिस्ट्रिक्टवाइज इंडेक्स बनाने के लिए तैयार किया जाए। अभी तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो पाया है, कोई अमल नहीं हो पाया है, लेकिन प्रयास जारी है। फिर भी, यह तीसरा कदम होगा। हमने जो दूसरा कदम लिया है कि विश्व में हमारा देश पहला ऐसा मुल्क है, जिसने फेडरल स्ट्रक्चर के तहत न केवल नेशनल लेवल पर एक इंडेक्स बनाया है, स्टेट लेवल पर भी ऐसे इंडेक्स का हमने जिक्र नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के अंदर किया है। भारत विश्व का सबसे पहला देश है, जिसने फेडरलिज्म का ध्यान रखते हुए सब-नेशनल लेवल पर भी यह काम किया है।

अगर हम इसी रफ्तार से चलते गए तो हम उम्मीद करते हैं कि एक-दो साल के अंदर हम स्टेट्स के अंदर भी इसके ऊपर डिस्ट्रिक्टवाइज अमल करने के लिए हम उनको मना लेंगे।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, पहले यह मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था, उसके बाद इसे बदलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाया गया। मंत्री जी कह रहे थे कि हम ज़ीरो हंगर की दिशा में चल रहे हैं, लेकिन शायद आपको पता होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, दुनिया के 117 देशों में हमारा 102वां स्थान है। वर्ष 2014 में हमारा स्थान 54वां था, अभी 54 से घटकर यह 102वें स्थान पर आ गया है। इसका मतलब है कि हम हंगर इंडेक्स का पालन नहीं कर सके और गिरते रहे। आपने यहां बताया है कि आपने 2030 तक, 60 परसेंट स्केल बना लिए हैं, उसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी था।

(1125/RAJ/RC)

उस समय हंगर इन्डेक्स के 54वें स्थान से घट कर अभी यह 102वां स्थान पर आ गया है। यह आकलन कैसे होगा?

नम्बर टू, आप कह रहे हैं कि वर्ष 2023 तक 40 प्रतिशत बना लेंगे, आपका इस साल के लिए भी कोई टारगेट है, जैसे कि एसडीजी-2, एसडीजी-3, एसडीजी-6 और एसडीजी-8, ये चार जो आपके टारगेट्स हैं, आपने इसमें वादा किया था कि वर्ष 2020 में हम यह कर लेंगे। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि you have one of the Goals which says by 2020, half the number of deaths and injuries from road traffic accidents. आप यह नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सामने इसकी कोई स्पष्ट छवि नहीं है। जैसे मैंने एक छोटा-सा मुद्दा, ग्लोबल हंगर इन्डेक्स के बारे में बताया है कि अभी हमारी हालत बिगड़ती जा रही है।...(व्यवधान) यह इंफ्लेक्सेबल नहीं हो सकता है, यह फ्लेक्सेबल है। आप आगे कैसे जाएंगे?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं फिर आग्रह करूंगा कि हमें प्रश्न संख्या की सूची पूरी करनी है तो आप संक्षिप्त में प्रश्न पूछे और माननीय मंत्री जी भी शॉर्ट में आंसर दें।

श्री राव इंद्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही माना है कि जो गोल नम्बर-दो, जीरो हंगर है, हमें उसमें काम करने की आवश्यकता है। प्रांतों को भी काम करने की आवश्यकता है और इसकी कामयाबी केवल देश की सरकार के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि प्रांतों को भी एसडीजी गोल्स के लिए बराबर की हिस्सेदारी करनी होगी, तभी कुल मिला कर हमारा हंगर वाला इन्डेक्स दुरुस्त होगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं।

दूसरा, हम भारत सरकार की तरफ से क्या काम कर चुके हैं, मैं मोटे तौर पर उसका जिक्र कर सकता हूं कि हम ने हंगर घटाने के लिए टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्वच्छ भारत, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम्स, प्रधान मंत्री आवास योजना इत्यादि, आज अनेक स्कीम्स भारत सरकार की तरफ से चल रही हैं, जो हंगर, पावर्टी को घटाने के लिए प्रयासरत हैं। इसमें ज्यादातर काम प्रान्तों को करना होता है। हमें हर प्रान्त का भी सहयोग चाहिए, तभी हम इसमें कामयाब हो पाएंगे।

SHRI ACHYUTANANDA SAMANTA (KANDHAMAL): Sir, I want to know from the hon. Minister whether the Government has provided adequate funds to the State of Odisha to achieve SDG. If yes, the amount provided in the last year.

RAO INDERJIT SINGH: We are not providing any funds under the Sustainable Development Goals. What we have resorted to is to ensure that there is competitiveness amongst States. Competitive federalism is the motto of NITI Aayog and through them we are ensuring that States see each other, have a healthy rivalry, spend funds on these goals, and hopefully compete with the other States to better their progress.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I would like to ask a specific question from the Minister. I appreciate the competitive federalism that the hon. Minister is talking about, but what specific intervention are you doing?

In the UPA-II, there was a Malnutrition Eradication Programme specifically run pan India. There was a huge campaign led by the hon. Prime Minister, Shri Manmohan Singh. I see from all the four replies that you have made that the Central Government is sort of shrinking away. Most of the Departments are withdrawing support on the recommendations of the Finance Commission. They are withdrawing support with moneys whereas most of the States in India are under absolute debt.

So, if the Central Government's approach, especially to hunger is going to be that the States have to do everything plus vis-à-vis competitive federalism, I think it is not going to help. Hunger is a very serious issue. Malnutrition is one of the challenging issues of this country. What specific intervention is this Government going to do to eradicate poverty and malnutrition in the children of India today?

RAO INDERJIT SINGH: There is not one specific scheme which is targeted towards hunger. But there are social schemes which are targeted to alleviating poverty of India so that people can provide for themselves and have enough food.

Under the social protection schemes, I would like to mention the National Social Assistance Programme involving an amount of Rs.9975 crore. Then, there are Ayushman Bharat and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana.

(1130/SRG/VB)

I would like to say that nutrition itself is something that is better addressed to the Women and Child Development Ministry. I think that is a subject that is handled by them. So, if this question could be addressed to them, it may be better answered.

(ends)

(प्रश्न 44)

श्री सुनील बाबूराव मेंढे (भन्डारा-गोंदिया): मेरा प्रश्न यह है कि whether the Government has any policy to link the social media users with their Aadhaar card, जिसका माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम लोग कोई सोशल मीडिया रेगुलेशन पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से एंटी सोशल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज में सोशल मीडिया का यूज़ होता है और कश्मीर में इसको बैन करना पड़ता है। क्या इससे संबंधित रेगुलेशन बनाने के लिए कोई समयबद्ध सूची बनाई गई है?

दूसरा, यदि हम लोग यह करने जा रहे हैं या सोशल मीडिया यूजर्स की लायबिलिटी बढ़ाने की जो बात हो रही थी, तो क्या उसमें हम कोई कड़ा कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री संजय धोत्रे : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। जब कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, तो उसी समय उसका दुरुपयोग करने वाले, उसको क्रैक करने वाले लोग भी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद उसके लिए अलग-अलग कानून बनते हैं।

इसके लिए आई.टी. एक्ट, 2000 बना हुआ है। हमने वर्ष 2011 में इससे संबंधित एक इंटरमिडियरी नोटिफिकेशन भी निकाला है। अगर सोशल मीडिया में कोई फेक न्यूज या कुछ गलत न्यूज चलती है, जिससे लॉ एंड आर्डर मेनटेन करने में परेशानी होती है, तो उसको ब्लॉक करने का भी प्रोविजन है। अभी एक नया बिल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का है, जिस पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से आने पर चर्चा होगी।

माननीय सदस्य द्वारा दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह पूछी गई कि क्या इसके लिए कोई अवेयरनेस कैम्पेन चलाई गई है। मैं कहना चाहूँगा कि स्कूल्स एवं कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई विभाग भी इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और आई.टी. डिपार्टमेंट के भी कई इंस्टिट्यूट्स हैं, जैसे सी-डैक है, जो इसके बारे में बहुत-से पब्लिक कैम्पेन्स भी करता रहता है और वह बार-बार उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी शामिल करता है।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): I would like to ask the Government, through you, whether any mechanism has been formulated by the Central Government throughout the day to find out if any fake news is being published, printed and especially pornography and child pornography. If so, how many cases have been detected and how many culprits have been punished? There is an answer here that the Ministry of Electronics & Information Technology and Ministry of Home Affairs are in regular touch with various social media platforms. With great respect, this is a very vague answer. I need a definite answer whether it has been done or not.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): The concern of the hon. Member regarding pornography, particularly child pornography is a serious menace. The global body has already taken a call that all countries need to work together. In the case of child pornography and abuse of social media for its propagation, we are also taking a lot of measures.

(1135/RU/PC)

The Central Government, the State Governments, the Ministry of Home Affairs and the State Police are taking measures.

As regards the specific issue of number is concerned, I will ensure that it is provided to you. But I would like to convey one thing to this House because a very significant question has been raised. The entire country also needs to understand this menace. It is not only in this area. Revenge porn is rising in the country. Boy friend and girl friend have been good friends, they split up and then we are hearing another disturbing phenomenon of seeking to defame young girls. These are issues on which the society, the country, the polity, and the Parliament have to work together. This is how we are working on it.

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मैं यह कह रहा हूं कि इस विषय पर बड़ी गंभीर चर्चा होनी चाहिए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं। इस पर अगले सत्र में आधे घंटे की चर्चा होनी ही चाहिए।

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, in the last Session also, we wanted a discussion on water related issues. Till now, the discussion is not being held.

माननीय अध्यक्ष: अब उस पर चर्चा होगी।

…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सर, अगर कोई नोटिस आएगा और आपकी अनुमति होगी तो सरकार तैयार है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मैं आपकी इस राय से बिलकुल सहमत हूं। दूसरे सदन में आज से एक साल पहले इस पर चर्चा हुई थी। मैंने विस्तार से उत्तर दिया था। मैं भी इस सदन की भावना, विचार और आपके निर्देश को सुनना चाहूंगा। आज देश में एक कॉम्पीटिंग इन्ट्रेस्ट चल रहा है कि हमें बोलने का निर्बाधित अधिकार है, जब कि संविधान में उसकी सीमाएं हैं। हम सोशल मीडिया का पूरा सम्मान करते हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों का भी सम्मान करते हैं। …(व्यवधान) इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसके बारे में सदन में चर्चा होनी चाहिए। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। …(व्यवधान)

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Sir, part 'c' of the Question is like this.

"What are the measures taken by the Government to keep a check on the spread of fake news, pornographic and anti-national content on the social media?"

The answer given at point No. 4 is:

"The Ministry and the Ministry of Home Affairs and the Police are in regular touch with various social media platforms to address the issues of removing this content."

मेरा प्रश्न यह है कि मिनिस्ट्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश देती है कि अगर आपको ऐसा कोई भी हेटफुल कन्टेन्ट, इल्लीगल कन्टेन्ट, क्रिमिनल कन्टेन्ट मिले, आपको उसे हटा देना चाहिए। जामिया में जो पहला शूटर गोपाल था, वह अपनी पूरी मंशा फेसबुक पर लिख चुका था। उसके द्वारा पूरे फेसबुक पर इस प्रकार का हेट कन्टेन्ट लिखने के बाद भी आपकी मिनिस्ट्री ने फेसबुक को क्यों इन्सट्रक्शन्स नहीं दिए कि इस कन्टेट को हटाया जाए? …(व्यवधान) यह आदमी फेसबुक लाइव भी कर रहा था, पर आपकी मिनिस्ट्री से कोई जांच, कोई निर्देश नहीं दिया गया। यह चूक क्यों हुई? …(व्यवधान) इस हेट से बहुत लोगों का मन डिस्टर्ब भी हुआ और यह साफ-साफ इल्लीगल है। …(व्यवधान)

Second of all, many countries across the world are passing a law where their Governments are penalising social media companies for not removing contents which disturb communal harmony and imposing fine if they do not remove the content within a stipulated time frame. Will the Government of India also consider such a similar law?

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): मंत्री जी, आम आदमी पार्टी का क्यों हटाया, यह भी बताइए। …(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मैं माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न के पक्ष को पहले रख दूं। माननीय उच्चतम न्यायलय के निर्देश के अनुसार इस पूरी गाइडलाइन पर एक विचार चल रहा है। इस पर मंथन के बाद हम इसको भी लाएंगे। आपकी जानकारी के लिए, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जो सलेक्ट कमेटी के सामने है, जैसा हमारे माननीय राज्य मंत्री ने बताया, उसमें इस संदर्भ में पनिशमेन्ट, फाइन, वॉइलेंट्री आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल मीडिया प्लेयर्स, इन सभी का विस्तार से विवरण है। जब आप सदन के सामने आएंगे तो आपको यह लगेगा और अगर आपको लगता है कि उसमें और सुधार की गुंजाइश है तो हमारी व्यापक सलेक्ट कमेटी के विद्वान सदस्यगण उसे देखेंगे।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): माफ कीजिएगा, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में यह नहीं है। …(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद: हमने भी उसको थोड़ा पढ़ा है, हमने उसको बनाया है। …(व्यवधान) जब आप मुझसे सदन में बहस करेंगे, तब मैं उत्तर दूंगा। अभी उस पर बहस नहीं हो रही है। उस पर सलेक्ट कमेटी काम कर रही है। सलेक्ट कमेटी उसमें जोड़ भी सकती है। …(व्यवधान)

सर, अब जो पहला सवाल है, जो चीज़ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, वह कर रही है, फिर एक ही क्यों, दोनों प्लेयर्स की बात आएगी। पुलिस के अनुसंधान के बाद जो विषय आएगा, मैं उसे रखूंगा। अनुसंधान के बीच में इस पर कोई टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं है।

(1140/NKL/SPS)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Hon. Speaker Sir, my question to the hon. Minister is specific to Part C. The Government has taken steps and the Courts have also ordered banning of all the porn sites and also banning of all the child pornography sites. You are doing a good job of banning it but you are aware that it is available to every Indian through VPN service, through fake VPN services, through proxy servers, which are still continuing. In fact, this ban is not being followed by anyone because this VPN service allows the end user to bypass all your security protocol and access it, whereas, the countries like UAE and China ensure that VPN services are banned when it comes to pornographic sites. Are you going to take steps or will you take steps to ensure that these VPN services are also regulated or banned in India?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I wish to assure this House that I have got the data of the last day. Under Section 69A of the Information Technology Act, the total number of blockings done is 9,063. We keep on taking steps from time to time. The hon. Member is absolutely right that child pornography must be dealt with in a very hard manner, and there is a global consensus. But as far as adult pornography is concerned, there are competing interests. Some people say that it is their right to see it in the privacy of their house. …(*Interruptions*) Therefore, we do take action as well. I told you the number of instances. I do not wish to join issue with you on any specific platform. That will not be fair for me as the Minister of this Department. …(*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, by using Virtual Private Network, they are bypassing your system. …(*Interruptions*)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I am telling you. …(*Interruptions*) सर, हमने बताया कि हजारों चैनल्स को ब्लॉक किया है। कई बार हम यहां ब्लॉक कर देते हैं तो विदेशों में दूसरे चैनल्स पर आते हैं और उस पर चर्चा होती है। यह समस्या दुनिया की है। I would gently like to remind Mr. Maran, with great respect, that India should not be compared with

China and some Middle-East countries. Ours is also a democracy. …(*Interruptions*)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मिनिस्टर का रिप्लाई ठीक नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: दादा, मैंने इस विषय पर चर्चा करने के लिए आदेश दे दिए हैं। अब इस पर दोबारा डिबेट नहीं करेंगे।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, making these kinds of sweeping comments against me is not fair. I do not want to join issue with you at all.

But Sir, there is another view that this VPN is also being used for a lot of good purposes. We all know it. I do not want to go into that debate. But it is being said that it is not being fair – that will not be a correct comment. When a full-scale debate arises, we will explain everything.

(ends)

(प्रश्न 45)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। देश में 62 छावनियां हैं। इन 62 छावनियों में रहने वाले लोगों और बाहर जो लोग रहते हैं, उनको मिलने जाने वाले लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के लिए 2017 में उस समय के रक्षा मंत्री साहब ने तीन बार इसकी बैठक ली और रास्ता निकालने की कोशिश की। बहुत सारी समस्याएं सुलझ गईं, लेकिन मेरा अनस्टार्ड क्वेश्चंस नंबर 2734, जो 4 फरवरी, 2019 को लगा था, उसमें यह कहा गया था कि यह समस्या सुलझाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। उस कमेटी का गठन किया भी गया है, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई है। यह रिपोर्ट कब पब्लिश करेंगे और उस पर आप कब इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं?

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, माननीय सदस्य ने सही प्रश्न उठाया है। यह भी सच है कि एक कमेटी बनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट भी सबमिट हो चुकी है। मंत्रालय उसके ऊपर विस्तार से चिंता कर रहा है। उसकी रिकमेंडेशन के अनुसार आगे बढ़ने की भी कोशिश हो रही है और कंटोनमेंट में जिनकी एप्लीकेशन रेगुलराइजेशन और कन्वर्जन के लिए पेंडिंग हैं, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, फिर भी इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को भी सीरियसली लिया जा रहा है।

(1145/MM/KSP)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): धन्यवाद महोदय, मैडम, रिकमण्डेशन जल्दी पब्लिश हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। पब्लिश ही नहीं हो रहा है, एक साल हो गया है। मैडम, आप कब पब्लिश करेंगी?

महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि फ्री होल्डिंग के लिए सिविल क्षेत्र के पट्टेदारों/एचओआर से 391 आवेदन (253 ओल्ड ग्रैंड सम्पत्तियां एवं 138 पट्टायुक्त सम्पत्तियां) प्राप्त हुए हैं, जिनमें भूमि की कीमत की 25 प्रतिशत राशि छावनियों में जमा की गयी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें कितनी कुल राशि जमा हुई है और इन आवेदनों की वर्तमान स्थिति क्याा है?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the hon. Member is right that for 636 cases, sanction for freeholding of properties in cantonments has already been accorded by the Ministry. But from among these 636 cases, 526 are in respect of old grand bungalows and the remaining 110 are on lease properties of the civil area. The payment structure is such that at the time of application, you give only 25 per cent and after that, the STR (Standard Table of Rates) based calculation is determined and when the sanction is made, the remaining 75 per cent has to be paid.

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट (पुणे): महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश में 62 केंटोनमेंट्स हैं, उसमें से 6 महाराष्ट्र में है और 3 मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। जिस तरह से सिविलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से ब्रिगेडियर से परमिशन लेना मुश्किल हो गया है और जो मैंटेनंस फण्ड है, जहां स्कूल होना चाहिए, ग्राउण्ड होना चाहिए, रोड बनाने में दिक्कत है, उसके लिए पैसा नहीं मिलता

है और जो पैसा सेन्टर से आता है, उसका डिस्ट्रिब्यूशन नहीं होता है। लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। केंटोंमेंट के बारे में जो रिपोर्ट आयी है, उसमें जो सुझाव दिए गए हैं, क्या उन पर इम्प्लीमेंटेशन होगा? अगर नहीं, तो ग्राम पंचायत में तो पंचायत बना दीजिए, क्योंकि ब्रिटिश जमाने से मिलिट्री का एरिया जितना था, उतना ही है। गांव के लोगों को श्मशान भूमि तक जाने के लिए भी अलाऊ नहीं करते हैं। इस तरह की बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं। स्कूल की बिल्डिंग के लिए भी अलाऊ नहीं करते हैं। बिल्डिंग की परमिशन के लिए 6-6 महीने रुकना पड़ता है। ब्रिटिश जमाने तक तो ठीक था, लेकिन अब सब भारतीय लोग हैं और उनको बहुत तकलीफ हो रही है। मेरी आपसे विनती है कि इस पर ध्यान देकर कोई न कोई सॉल्यूशन अवश्य निकालें।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the hon. Member has brought in various issues into this question.

The Member said that in the cantonment area, money does not reach the Cantonment Boards for providing civic amenities for which the Cantonment Board should be undertaking the expenditure. This is a larger issue of how monies are devolved and how every State Government shall further devolve it to give monies to the local bodies, one of which is also a cantonment body. So, that is a larger issue in which the Finance Commission will also have to come into the picture. However, when the monies are given to the State Government, it is up to the State Government also to further devolve it down so that those people living in the cantonment areas are also benefited from the grants of local bodies which should reach them. That is one side of the question.

The other one is, of course, a question of the time taken for clearance in these kinds of applications. Yes, it is taking a long time and the process itself goes through different stages from the local military authority up to the competent authority which is the Ministry of Defence. However, based on the recommendations of the Sumit Bose Committee, which has already submitted its Report, I am sure this period of processing of applications will be condensed and it should not be taking so long.

(ends)

(1150/KKD/SJN)

(Q. 46)

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): Hon. Speaker, Sir, about 25 Defence Canteen Stores were given notices in December saying that the 31st December was going to be the last date, and one of it is in my Parliamentary Constituency Eluru. There are about 4,000 Ex-Servicemen in my district, and they are put to hardship. They were in a panicky mode. When I requested, they postponed the closure.

So, I just want an assurance from the Government that if they are closing them down, are they making alternative arrangements or what is their plan?

SHRIMATI NIRMALA SEETHARAMAN: Sir, generally, closure does not happen of Canteen Stores Department. There can be a rationalisation of its locations because if the number of people dependent on the Canteen Stores Department is lesser, and if there are nearby other provisions, then they would try to do it. But normally closure does not happen. The numbers are very determined about those servicemen, who are living in the area or Ex-Servicemen, who are living in the area, for whose benefit Canteen Stores Departments are run. So, normally, there is no closure; sometimes, there is rationalisation. In your particular case, I am sure, the Minister will be able to respond.

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): So, I was hoping that the Government can start an online service for Defence Canteen Stores as well, at least, for the unrestricted routes.

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, I represent a Constituency, which is an Aspirational District, and Madam Minister had also visited Virudhunagar many times. It has many Ex-Servicemen, who are living there; and it also has CSD. Now, there are reports that the CSD there is going to be closed. The Government takes the Aspirational Districts in an important way. So, would the hon. Minister assure that the CSD in Virudhunagar will not be closed.

SHRIMATI NIRMALA SEETHARAMAN: Sir, as I said in my previous reply also, closures do not normally happen. I am not sure about the specific instance where the hon. Member is referring the Aspirational Districts – one of the two in Tamil Nadu, Virudhunagar. I will have to certainly go back to the specific issue of Virudhunagar and Canteen Stores Department there, and see under what consideration it is. But as it is, closures normally do not happen. But about Virudhunagar, I will come back on it.

(ends)

(Q. 47)

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Sir, I would like to know: how many companies have requested for compulsory licence for patent drugs? What are the brands and in the international non-propriety, names of these drugs? How many compulsory licences were granted?

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, his question is completely unrelated to the original question.

Sir, I would like to request you to kindly have a look at it. The question is asking for details of every patented molecule for the last 15 years. Now, all of this is already there on the website. The Department has to sit and work it out.

I am just wondering what is the essence of the question that has been asked. It is about just the details, which are available on the websites. This question is completely unrelated …(*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): It is not a fair answer. Everything is available on the website, then what is the need for asking a question in the Parliament!

SHRI PIYUSH GOYAL: Gentleman, look at the question. Kindly read the question. It talks about the details of the patented molecule along with the date of patent application, date of the patent grant, patent application number, patent number, name of the patentee. Now, I wonder, how this question is at all related to the one about what he has just asked …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, आप सवाल पूछ लीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the Minister is bound to reply …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट रुकिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। लेकिन आप पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए कि कितने आवेदन आए थे, कब आवेदन आए थे। मैं टी. एन. प्रथापन जी से यह कहना चाहता हूं कि आप प्रश्न पूछिए।

…(व्यवधान)

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Sir …(*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The question has already been permitted by the hon. Speaker. Now, it becomes the property of the House. When a question has been introduced, it is the constitutional responsibility of the hon. Minister to further furnish all the details. It is the privilege of the Member. (1155/RP/GG)

If everything is available on the website, we need not come to the Parliament, we will go to the website. …(*Interruptions*)

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Speaker, Sir, why is he interfering? …(*Interruptions*)

THE MINISTER OF RAILWAYS AND MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, I have said whatever was asked is all answered over here. …(*Interruptions*) Now, he is asking about something totally unrelated to the Question. That is what my submission is. …(*Interruptions*) All this information is already submitted. Whatever has been asked, the additional information he is asking is not in the Question altogether. …(*Interruptions*)

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Sir, the first answer is very unhappy. My second question is this. Since the prices of patent medicines are very high, has the Government taken any steps to control these prices?

SHRI PIYUSH GOYAL: I am very happy to inform the hon. House – I am sorry we are campaigning in the elections – through you, Sir, that all the costs of the patent office have been revised, particularly, for women entrepreneurs, MSMEs and for start-ups. We are giving significant concessions. At times, up to 80 per cent of the patent application costs to support such sections.

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, it is purely a technical question. I am not aware of the subject even.

(ends)

(प्रश्न 48)

श्री अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं देश के प्रधान मंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि जहां घास पकड़ कर चार धाम जाते थे, वहां अब रेल दौड़ेगी। मान्यवर, अभी 16 हजार 216 करोड़ रुपये की लागत से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक प्रथम फेज़ में जो रेल लाइन जा रही थी, उसकी कीमत अब 22 हजार 42 करोड़ लगभग हो गई है। 126 किलोमीटर का यह रास्ता है। 16 सुरंगे इसमें खुद रही हैं और 16 पुल इसमें लगेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो पूर्व में धनराशि दी गई थी, वह धनराशि लगभग समाप्त हो गई है। आने वाले दिनों में पूरी तरह से रेल कर्णप्रयाग तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, इसके लिए आगामी धनराशि कब तक वितरित की जाएगी। दूसरा, कर्ण प्रयाग से आगे चारधाम हेतु परियोजना का सर्वे, फाइनल लोकेशन लगभग पूरा हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि इस कर्णप्रयाग से आगे चारों धाम तक रेल लाइन जोड़ने हेतु सरकार की क्या योजना है?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH CHANNABASAPPA ANGADI): Sir, the hon. Member has asked a very important question. We have spent more than Rs. 2,000 crore till date. The work is under progress. Further, in future, as the Member has asked about *char dham*, the details will be taken from the department concerned. It is not connected to this question. We will take the information from the department concerned and supply the same to the hon. Member.

श्री अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): माननीय अध्यक्ष जी, अपने प्रश्न में मैंने जो दूसरी रेल लाइन के बारे में पूछा है, वह टनकपुर से बागेशवर रेल लाइन है। उसमें सरकार की तरफ से जवाब आया है कि इस रेल लाइन की फिज़िबिलिटी नहीं पाई गई है, इसलिए इसमें दोबारा से सर्वे हो रहा है। मेरा यह प्रश्न है कि सर्वेक्षण पूर्ण करने की कोई समय-सीमा टनकपुर-बागेशवर रेल लाइन के लिए रखी गई है? दूसरा, रामनगर-चौखुटिया-गैरसेंण, गैरसेंण हमारी राजधानी बनने वाली है, इसके बारे में भी सरकार की तरफ से उत्तर आया है कि इसका सर्वे पूरा हो गया है। यदि सर्वे पूरा हो गया है तो उस पर कार्य कब तब प्रारंभ कर दिया जाएगा?

SHRI SURESH CHANNABASAPPA ANGADI: Sir, the hon. Member is interested in the Tanakpur-Bageshwar railway line. It is having a stretch of 155 kilometers. It was found unviable earlier. Now, a fresh survey has been conducted once again. The project report is under preparation. Once the project report is prepared, the details will be shared with the hon. Member taking into consideration the viability of the project.

(1200/RCP/KN)

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, Kerala is having the least per capita railway lines in India and there is overworked and overutilized railway

(Page 20-30)

infrastructure in the State. This is affecting huge volume of goods traffic. To enhance connectivity within the State, there is a need to have a third line between Mangaluru and Trivandrum Section *via* Alleppey. I would like to know from the hon. Minister what steps will be taken to examine and introduce a third line between these two stations.

SHRI SURESH CHANNABASAPPA ANGADI: Sir, I also come from South India and he also comes from Kerala. You know very well, the Kerala Government is not at all cooperating for providing lands etc. Whenever the projects are taken up, 50 per cent cost sharing will be given by the State Government. But Kerala is not cooperating with the Central Government and the Railways. He is saying that we are not supporting.

You please talk to the Kerala Government. If they provide all the land and other facility and if the request comes from the Kerala Government, the hon. Prime Minister is definitely having a motto of "Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas''. You know how our Prime Minister works. But since Kerala is not at all cooperating in maintaining law and order, including Railways, and in any development work, please ask the hon. Member to take care.

Thank you.

(ends)

QUESTION HOUR OVER

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर 2- श्री रवि शंकर प्रसाद।

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): सर, मैं आपकी अनुमति से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2019 जो 22 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3786(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY DHOTRE): On behalf of Shri Dharmendra Pradhan, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2020-2021.

(ii) Output Outcome Framework of the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2020-2021.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री प्रहलाद जोशी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) वर्ष 2020-2021 के लिए खान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) वर्ष 2020-2021 के लिए कोयला मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगे।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING (RAO INDERJIT SINGH): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Labour Economics Research and Development, Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of National Institute of Labour Economics Research and Development, Delhi, for the year 2018-2019.

(2) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Planning for the year 2020-2021.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, श्री श्रीपाद येसो नाईक की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of Shri Hardeep Singh Puri, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Basic Chemicals Cosmetics and Dyes Export Promotion Council (CHEMEXCIL), Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Basic Chemicals Cosmetics and Dyes Export Promotion Council (CHEMEXCIL), Mumbai, for the year 2018-2019.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Plastics Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Plastics Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2018-2019.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Shellac and Forest Products Export Promotion Council (formerly Shellac Export Promotion Council), Kolkata, for the year 2018-2019.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Shellac and Forest Products Export Promotion Council (formerly Shellac Export Promotion Council), Kolkata, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Shellac and Forest Products Export Promotion Council (formerly Shellac Export Promotion Council), Kolkata, for the year 2018-2019.

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 19 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992:-

(i) S.O.2092(E) published in Gazette of India dated 25th June, 2019, regarding amendment in import policy of seeds of Peas.

(ii) S.O.3112(E) published in Gazette of India dated 28th August, 2019, regarding amendment of import policy of polymethyl methacrylate under Exim code 39169032 of ITC (HS) 2017-Schedule-I (Import Policy).

(iii) S.O.3111(E) published in Gazette of India dated 28th August, 2019, regarding Insertion of a new policy condition under Chapter 87 of ITC (HS), 2017-Schedule-I (Import Policy).

(iv) S.O.3156(E) published in Gazette of India dated 31st August, 2019, regarding amendment of import policy of "Agarbatti" and other odoriferous preparations which operate by burning under Exim code 33074100 and 33074900 of ITC (HS) 2017-Schedule-I (Import Policy).

(v) S.O.3214(E) published in Gazette of India dated 5th September, 2019, regarding amendment in import policy of Iron & Steel and incorporation of policy condition in Chapters 72, 73 and 86 of ITC (HS), 2017, Schedule-I (Import Policy).

(vi) S.O.3213(E) published in Gazette of India dated 5th September, 2019, regarding amendment in import policy of Chlorotrifluoroethene (CTFE) under HS Code 2903 77 90 of Chapter 29 of ITC (HS), 2017 – Schedule-I (Import Policy).

(vii) S.O.3492(E) published in Gazette of India dated 26th September, 2019, regarding amendment in import policy electronic cigarettes.

(viii) S.O.3684(E) published in Gazette of India dated 11th October, 2019, regarding amendment in Import Policy Condition of Urea under Exim Code 31021000 in the ITC (HS) 2017, Schedule-I (Import Policy).

(ix) S.O.3685(E) published in Gazette of India dated 11th October, 2019, regarding amendment in import policy of Indian National Flag.

(x) S.O.3841(E) published in Gazette of India dated 24th October, 2019, regarding amendment in import policy condition No. 2 of Chapter 39 of ITC (HS), 2017, Schedule-I (Import Policy).

(xi) S.O.4066(E) published in Gazette of India dated 8th November, 2019, regarding amendment in Policy Condition No. 3 of Chapter

88 and incorporation of Policy Condition No. 3 in Chapter 95 of ITC (HS) 2017, Schedule-I (Import Policy).

(xii) S.O.4096(E) published in Gazette of India dated 13th November, 2019, regarding amendment in import policy of Iron & Steel and incorporation of policy condition in chapter 72, 73 and 86 of ITC (HS), 2017, Schedule-I (Import Policy).

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Diamond Institute, Surat, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Diamond Institute, Surat, for the year 2018-2019.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY DHOTRE): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Broadband Network Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Bharat Broadband Network Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Sanchar Nigam Limited, New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Bharat Sanchar Nigam Limited, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 37 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997:-

(i) The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Fifteenth Amendment) Regulations, 2019 (10 of 2019) published in

Notification No. F. No. 6-14/2019-BB&PA in Gazette of India dated 17th December, 2019.

(ii) The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Second Amendment) Regulations, 2020 (1 of 2020) published in Notification No. F. No. 21-5/2019-B&CS in Gazette of India dated 1st January, 2020.

(iii) The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) (Third Amendment) Regulations, 2020 (2 of 2020) published in Notification No. F. No. 21-4/2018-B&CS in Gazette of India dated 1st January, 2020.

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Electronics and Information Technology for the year 2020-2021.

(ii) Output Outcome Monitoring Framework for Central Sector Schemes of the Ministry of Electronics and Information Technology for the year 2020-2021.

(iii) Detailed Demands for Grants of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, for the year 2020-2021.

(iv) Output Outcome Monitoring Framework for Schemes of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, for the year 2020-2021.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH CHANNABASAPPA ANGADI): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rail Land Development Authority, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rail Land Development Authority, New Delhi, for the year 2018-2019.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987:-

(i) The Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.941(E) in Gazette of India dated 20th December, 2019.

(ii) The Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2020 published in Notification No. G.S.R.21(E) in Gazette of India dated 10th January, 2020.

(4) A copy of the Rail Land Development Authority (Constitution) Amendment Rules, 2020 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.32(E) in Gazette of India dated 14th January, 2020 under Section 199 of the Railways Act, 1989.

(5) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Railways for the year 2020-2021.

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
Action Taken Statement

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD WEST): I beg to lay on the Table the Final Action Taken Statement (Hindi and English versions) of the Government on the recommendations contained in Chapter I of Twenty-third Report (16th Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes regarding Action Taken by the Government on the Thirty-first Report (15th Lok Sabha) on 'Reservation for and Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Ordnance Factory Board (OFB)' pertaining to the Ministry of Defence (Department of Defence Production).

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति
दूसरा प्रतिवेदन

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित 'केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों/राष्ट्रीय सैन्य स्कूलों में प्रवेश और नियोजन में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

---

*यह प्रतिवेदन लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 30 दिसम्बर, 2019 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किया गया था। माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की अनुमति दी है।

(1205/SMN/CS)

Direct Tax Vivad Se Vishwas Bill

1205 hours

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for resolution of disputed tax and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि विवादित कर के समाधान तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Under Rule 72 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I do oppose the introduction of the Bill on the grounds that first of all, this is the first time we are observing the unique nomenclature, that is, Direct Tax Vivad Se Vishwas Bill. महोदय, हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि विवाद से विश्वास, आइदर ये इंग्लिश में होते हैं या हिन्दी में होते हैं।

सर, हमारा देश मल्टी लिंग्वल देश है। हमारी 1652 लैंग्वेजेज हैं, उसमें 63 नॉन इंडियन लैंग्वेज भी हैं। हमारे हिन्दुस्तान में सिर्फ 43 परसेंट लोग हिन्दी भाषा बोलते हैं। मैं हिन्दी के बारे में दिलचस्पी रखता हूँ, फिर भी हमारे देश में 43 परसेंट हिन्दी भाषी हैं, वे भी भोजपुरी को लेकर हैं। मुझे लगता है कि बाकी लोगों के ऊपर, in a subtle way, the Government has been imposing Hindi in other parts of the country. Otherwise, I have never seen this kind of nomenclature.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, यह अंग्रेजी में है।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): यह 'विवाद' कौन समझेगा।...(व्यवधान) साउथ इंडिया में 'विवाद' की बात कौन समझेगा।...(व्यवधान) हम कहते हैं कि सीतारमण जी आपके देश में 'विवाद से विश्वास' किसको पता चलेगा।...(व्यवधान) आपको इसके अंदर यह रखना चाहिए कि यह डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई बिल है।...(व्यवधान)

सर, मैं आपको दिखाता हूँ।...(व्यवधान) डॉ. दुर्गादास बसु कान्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने भी यह कहा है कि :

> "(1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, until Parliament by law otherwise provides-
>
> (a) all proceedings in the Supreme Court and in every High Court,
>
> (b) the authoritative texts-

(i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State,

(ii) of all Acts passed by Parliament or the Legislature of a State and of Ordinances promulgated by the President or the Governor of a State, and

(iii) of all orders, rules, regulations and bye-laws issued under this Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of a State,

shall be in the English language."

मुझे लगता है कि आपने इस बिल का इस तरीके का जो टाइटल दिया है, जो नोमन्क्लेचर दिया है, यह टाइटल गलत है। मैं यह बात जरूर कहूँगा कि आप इसे सुधार लीजिए।

दूसरी बात यह है कि one issue with this Bill is that it gives amnesty to those who deposited unexplained amounts after demonetisation and were put under the tax canard. For instance, if a jeweller reported a turnover of rupees one crore in the previous year but then deposited rupees ten crore after demonetisation, he can pay tax and move on. There is no need to pay a penalty and interest on this.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक मिनट रुकिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मेरा एक पॉइंट है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं थोड़ा आग्रह कर देता हूँ। जो माननीय सदस्यगण बिल इंट्रोडक्शन का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने जो नोटिस दिया है, वे केवल उसी विषय पर बोलें।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हम वही तो बोल रहे हैं।…(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): He has quoted Rule 72.

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : हमने पढ़ लिया है।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री प्रहलाद जोशी : सर, मैं एक चीज बता रहा हूँ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री जी, सारी चीजें नियम-कानून से नहीं चलती हैं।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): वित्त मंत्री जी कुछ नहीं बोलती हैं, आप बीच में खड़े हो जाते हैं।…(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : वित्त मंत्री बोल रही हैं। इतना डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं है।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): वित्त मंत्री कोई डिटेल नहीं बोलती हैं।...(व्यवधान) मैं कोई डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ।...(व्यवधान) It is essentially stated that a signal to the honest taxpayer was given that their commitment to honestly paying taxes was pointless. यह बैक डोर से सुविधा मुहैया कराई जाती है, मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। Another issue is that it gives a clean chit to tax officials who had engaged in tax-terrorism. For instance, if a tax official had issued a high tax demand which was not warranted, there will be no corrective action.

You may say that this is a fair thing for tax payer. But it will hit tax collections of the Government at a time when fiscal deficit targets are not being met. The fiscal deficit target of 3.3 per cent for financial year 2020 was revised to 3.8 per cent.

(1210/MMN/RV)

The Government cannot afford a move like this. Nearly 43 per cent of the personal income tax collection target of Rs.2,42,000 crore for this year needs to be collected in the last three months of this financial year. This is for your suggestion. This is for your convenience. I am flagging your attention to the lacunae in this Bill.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Mr. Speaker, in addition to the points made by my learned colleague, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, which I will not repeat, I do want to have two additional grounds for opposing the introduction of this Bill. First, the Bill endorses the idea of exempting the defaulting taxpayers of their penalty and interest on the aggregate amount and getting away with the payment of the disputed tax alone. This violates the fundamental right to equality since it is arbitrary and treats equals unequally which leads to an unreasonable classification. So, the honest taxpayer and the dishonest taxpayer are being treated equally and that is not reasonable.

And, the second point is that it is beyond the legislative competence of this House to enact a legislation that severely encroaches upon the rights conferred by Part-III of the Constitution, including, of course, the right to equality. For these reasons, I think the Government needs to withdraw this Bill. Thank you.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, first of all, we are trying to seek your permission to introduce it. Two hon. Members have raised objections. Shri Adhir Ranjan Chowdhury Ji, I am afraid, is talking about the contents of the Bill about

which, I am sure, hon. Speaker, you will allow him to speak during the discussion on the Bill.

The other issue is about the name. In my Budget speech, I have very clearly used two different expressions. One was in English. I did say that this relates to no dispute but only trust, and while drafting the Bill, of course, they have used the Hindi name. But that does not mean that there is an imposition of Hindi. …(*Interruptions*) Sir, I must be allowed to speak. I have heard this hon. Member. I am also trying to respond to him. But I would appeal to him, through you, Sir, not to interrupt me so that my flow of thought is not obstructed because of the interruptions. I have heard him clearly and I am responding to him. I can take his suggestion as a suggestion but my thought is what I am putting before him.

The other hon. Member, Dr. Shashi Tharoor Ji has said that this takes away the right, and we are treating all taxpayers equally, both honest and dishonest. He may not have used that word but with all of them, there is a dispute. If I can say at this stage only, I can say about how many such cases are pending, all of them are pending for unduly a long time, nearly 4,83,000 cases are pending about which I mentioned in my Budget speech, and approximately Rs.9.32 lakh crore is the amount which is pending for over a year.

Many of these cases are not disposed of that easily. Stages by stages, they go in appeal and at the end of the day, both, for the Government and for the taxpayer, it becomes a sort of big money-spending exercise where people are spending money in the court defending their case or we are arguing for our case. So, at the end of the day, both the parties end up losing money. The Government does not gain. The taxpayer does not gain. All that we are trying to do is to not change the amount which is being disputed. The tax claim remains intact and that is where lies the sovereign right of the Government to remain firm on the amount which has been levied. Or, the incidence of tax does not change at all.

Then, to tell me that no, it is beyond the competence, I am sorry, hon. Member Dr. Shashi Tharoor will probably have to see what is in this Bill before he concludes it is beyond our legislative competence. So, having said this, I appeal to all the Members, through you, Sir, to allow this, so that once and for all, the people, who are now suffering because of constantly going to the court

to defend, are given a very structured and formula-based solution for settling the dispute. There is no discretion in this.

(1215/VR/MY)

There is no discretion in this. At least, these many number of people who have a choice to come into this scheme will get relief from having to defend the case. So, this formula-based approach is going to help the taxpayer and also the Government to be able to get the money.

Lastly, the reason why I have to place it today is because by 31st March, the set of people whoever wants to come in can come in. It benefits the Government to get revenues without having to worry them any further. Further extension is given only till June. It is not an open-ended scheme.

So, I would appeal to all the Members to see the point with which we have come. There is nothing more to this. I would appeal to all the Members to allow the introduction of the Bill.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि विवादित कर के समाधान तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I introduce the Bill.

विशेष उल्लेख

1217 बजे

माननीय अध्यक्ष: अब शून्य काल होगा। शून्य काल सबका काल है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब आप सभी एक साथ बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सभी एक साथ बोलेंगे या एक-एक कर बोलेंगे?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, यह बड़ी चिंता और दुख की बात है कि 18,000 से 22,000 फीट ऊँचा हमारा जो सियाचीन ग्लेशियर है, वहां हमारे जांबाज फौजी तैनात हैं। उन लोगों का रख-रखाव हम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। यह बात कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कहती है, बल्कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट यह बताती है कि सियाचीन ग्लेशियर में हमारे जांबाज फौजियों के लिए सही ढंग से हम सारा सामान उनको मुहैया नहीं कराते हैं।

Sir, it is a place where eggs and tomatoes turn into stones. जब राजीव गांधी जी थे, वर्ष 1984 में सियाचीन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। सियाचीन ग्लेशियर पर पाकिस्तान और चीन कब्जा करना चाहते थे। उसी समय ऑपरेशन मेघदूत चलाकर हमारी फौज ने सियाचीन ग्लेशियर पर कब्जा किया था। इसके चलते आज चीन और पाकिस्तान की तरफ से जो थ्रेट है, उससे हम बचकर रहते हैं।

सर, आज तक करीब 900 से ज्यादा हमारे फौज के जवान वहां इसलिए मर चुके हैं, क्योंकि वहां का जो वेदर है, वह इन्क्लिमेन्ट तथा इन्हास्पिटेबल है। उसमें तरह-तरह के रोग होते हैं- hypothermia, hypoxia, frostbite, white-out जैसे बहुत सारे रोग होते हैं।

सर, आपको भी यह देखने में बुरा लगेगा। सी.ए.जी. की रिपोर्ट क्या कहती है?

It says:

> "There is acute shortage of essential clothing and equipment items. There was critical shortage in snow goggles ranging from 62 per cent to 98 per cent. The troops were not issued multi-purpose boots from November 2015 to September 2016 and had to resort to recycling of available boots.
>
> Further, old versions of items such as face masks, jackets and sleeping bags were procured which deprived the troops from the benefits of using improved products. Lack of research and development by the Defence laboratory led to continued dependence on import."

सर, जो स्पेशल राशन है, वह भी नहीं दिया जाता है।

> "This compromised the calorie intake of the troops by as high as 82 per cent. At Leh station, in one instance, it was noticed that the special ration items were shown as issued to troops for consumption without their actual receipt."

सर, आज वहां क्या हो रहा है? …(व्यवधान) यह हिन्दुस्तान की सरकार ने 6,000 करोड़ रुपये सरकार के ऐड्वर्टाइज्मेन्ट के लिए खर्च किए हैं और हमारे फौज के जवानों के लिए कपड़े नहीं हैं। …(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): सर, जिस विषय को लेकर सरकार को लगातार बदनाम करने कोशिश की जा रही थी, वहां पता चला कि शाहीन बाग के पीछे जो लोग शामिल हैं, कल गोली मारने की जो कोशिश की गई और जो तथ्य सामने आया, वह कोई और नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी का एक मेम्बर था। उस मेम्बर की तस्वीर पाई गई। यह पूरा का पूरा मामला आम आदमी पार्टी की स्पान्सर्ड कार्रवाई है और वहां षड्यंत्र चल रहा है।

(1220/CP/SAN)

पूरी दुनिया के आगे सरकार को बदनाम करना, देश के खिलाफ कार्रवाई करना, इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। यह खास तौर पर चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूरी स्पांसर्ड, प्रायोजित रणनीति है। हमने इलेक्शन कमीशन को भी यह बात कही है कि इन सबका खर्च आम आदमी पार्टी के खर्च में डालें, क्योंकि उप मुख्य मंत्री खुद कहते हैं कि हम शाहीन बाग वालों के साथ हैं।…(व्यवधान) साथ में उनके मुख्य मंत्री भी यह कहते हैं।…(व्यवधान) चुनाव के समय पर भले ही हनुमान चालीसा का पाठ करें।…(व्यवधान) यहां बैठे हुए लोग भी वह हैं, जो जनेऊ कोट के ऊपर पहनते हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. संजय जायसवाल, डॉ. निशिकांत दुबे, श्री एस.सी. उदासी, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री विष्णु दयाल राम, श्री बिद्युत बरन महतो, कुमारी शोभा कारान्दलाजे, श्री जयंत सिन्हा और श्री देवजी एम. पटेल को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : श्री निशिकांत दुबे।

…(<u>व्यवधान</u>)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं, क्योंकि आदिवासियों के सम्मान में आज झारखंड के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और शेड्यूल ट्राइब्स थे, वे सभी आज महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने थे।…(व्यवधान) जब से यह यूपीए की सरकार आई है, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई है, एक गांव है बुरुगुलिकेड़ा, जहां वैस्ट सिंहभूम में 7 आदिवासियों की नृशंस हत्या कर दी गई।…(व्यवधान) आज तक उस सरकार ने या कांग्रेस ने उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा।…(व्यवधान) उसके पीछे कारण यह है, मैं आपको बताता हूं कि विकास विरोधी ताकत और जो अफीम पैदा करने वाले लोग थे, उन्होंने वर्ष 2016 से एक पथलगढ़ी मूवमेंट

स्टार्ट किया। उन्होंने 11 प्वाइंट का चार्टर दिया। इसके हिसाब से उन्होंने कहा, यह बहुत इंपोर्टेंट है कि इस देश का कोई कानून उस गांव में लागू नहीं होगा। उसके आधार पर वहां की सरकार ने, वहां की पुलिस ने उस वक्त उन लोगों के ऊपर केस किया। लेकिन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार आ गई, तो उन्होंने नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया।...(व्यवधान) उस केस को खत्म कर दिया।...(व्यवधान) उस केस का नतीजा यह हुआ कि...(व्यवधान) आदिवासियों की नृशंस हत्या हो गई। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप कनक्लूड करिए।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस और जेएमएम की सरकार को बर्खास्त करिए।...(व्यवधान) एक जुडीशियल कमीशन बनाइए और वहां राष्ट्रपति शासन लगाइए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री देवजी एम. पटेल, श्री एस.सी. उदासी, डॉ. संजय जायसवाल, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा, श्री विष्णु दयाल राम, श्री बिद्युत बरन महतो और श्री जयंत सिन्हा को डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Mr. Speaker, Sir, I thank you very much.

I wish to draw the attention of the hon. Minister for Fisheries towards the continuing neglect of the catastrophic implications of the unfortunate cyclonic storm Ockhi that caused havoc and left a trail of destruction in the coastal fishing villages in my constituency - mostly in Valiathura, Poonthura, Beemapally, Panathura and Veniyam in Thiruvananthapuram - on November 30, 2017. It is unfortunate that even after two years, the struggle for the survivors and for most of the families of the 143 persons whose lives were lost is yet not over as they continue to desperately seek rehabilitation measures and financial support from the State Government. While some have received aids like satellite phones and so on, many other distressed victims are still waiting for basic monetary assistance for fishing nets and boats, restoration of their homes, employment for their dependents, injured and widowed women folk.

I urge the hon. Minister to please provide additional relief and to oblige the State Government to expedite the compensation and other assistance to the fisher-folk and to promote disaster preparedness so that we do not have these tragedies in future.

Thank you.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Mr. Speaker, Sir, today six months are completing since the abrogation of Article 370 concerning Jammu and Kashmir.

माननीय अध्यक्ष : क्या उस पर बधाई देना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Speaker, Sir, you are the guardian and custodian of the House. No doubt, you are the supreme of this House. You have a moral duty and obligation to ensure the well-being of the Members of this House.

Sir, you are aware that since August 5, 2019, political establishment in Kashmir has been suspended and its mandate is held under suspension. The MPs, MLAs and other representatives of people are under detention.

Sir, I would remind you that our fellow Member of the Lok Sabha, Dr. Farooq Abdullah, a senior Member of this House, and also a former Chief Minister of Jammu and Kashmir, is unable to attend the House for the last three Sessions. Dr. Farooq Abdullah is not present in the House for the last six months and the House has a moral responsibility to ensure his welfare and his right to attend this House and participate in the crucial Budget Session, exercise his right to vote, his right to dissent and his right to express his views that will reflect …(*Interruptions*) his voters in the constituency and take part …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(<u>व्यवधान</u>)

(1225/RBN/NK)

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रतापराव जाधव – उपस्थित नहीं।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी (कैराना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षैत्र कैराना के अंतर्गत आने वाले विधान सभा नाकुड़ के अंतर्गत सहारनपुर में सरसावां से हापुड़ जाने वाली रोड पर …(व्यवधान)।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Dr. Farooq Abdullah is not attending this House. He could not vote in this House. He could not express his views. He could not voice the concerns of the people of his constituency who have elected him. He must come here and express his views. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बोल चुके हैं।

1227 hours

(*At this stage, Shri Gaurav Gogoi and some other hon. Members came and stood near the Table.*)

श्री प्रदीप कुमार चौधरी (कैराना): माननीय अध्यक्ष जी, संख्या 93 सी सरसावां से शाहपुर को जाने वाली रोड इब्राहिमपुर पड़ता है।…(व्यवधान) हमारा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, जब भारी बरसात होती है तो भयंकर बाढ़ आती है …(व्यवधान) उसके पास अन्य जो फाटक हैं, उन सभी फाटकों पर अंडरपास बनाए जा रहे हैं।

आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि उस फाटक पर अंडरपास की जगह ओवरब्रिज बनाया जाए। …(व्यवधान) उस फाटक पर पुल बनाया जाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जो अंडरपास बने हुए हैं, …(व्यवधान) वहां पानी न भरे और पुल के माध्यम से लोगों का आवागमन सुलभ और सुगम तरीके से बना रहे, यही मेरी सरकार से मांग है।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री प्रदीप कुमार चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रम्या हरिदास – उपस्थित नहीं।

SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY (BHONGIR): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me an opportunity to raise an important issue.

About four lakh handloom weavers in my parliamentary constituency are facing many challenges due to technology upgradation, product diversification, lack of design development to suit the current market trends, lack of modern dyeing facilities, etc. because of which most of the weavers are moving away from their profession.

There is a need to protect the ancient, historical and artistic skills of weavers and they need the Government's support to preserve handloom heritage. At present, in my constituency, 7,318 handloom weavers and 14,636 handloom ancillary workers are dependent on handloom weaving profession for their livelihood.

My request to the hon. Minister, through you, is to consider providing suitable livelihood to handloom weavers and preserve the handloom heritage in this area. Thank you. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री कोमती रेड्डी वेंकेट रेड्डी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष : श्री राहुल कस्वां-उपस्थित नहीं।

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे।

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे (नासिक): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए एमएसएमई बहुत अह्म भूमिका निभाती है। …(व्यवधान) देश की जीडीपी में एमएसएमई का हिस्सा 24.63 परसेंट है। …(व्यवधान) एमएसएमई मंत्रालय की जिम्मेदारी जब से आदरणीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को सौंपी गई है तब से छोटे उद्योगों को बड़ी व्याप्ति देने का काम वहां हो रहा है।…(व्यवधान) एमएसएमई में लगभग चालीस सेक्टर और पांच सौ अधिक छोटे कोर्सेज अंतर्भूत हैं। इन सभी कोर्सेज के लिए एक ही छत के नीचे ट्रेनिंग सेंटर या सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का होना जरूरी है, जिससे हमारा युवक जिस क्षेत्र में भी उसको रुचि है …(व्यवधान) उसका प्रशिक्षण लेकर एक सक्षम और कुशल युवक बनकर खुद का उद्योग शुरू कर सके। खादी ग्रामोद्योग एमएसएमई के अंतर्गत आता है। …(व्यवधान) खादी ग्रामोद्योग की देश में सबसे बड़ी 265 एकड़ जमीन नासिक में है। इससे पहले 2016-17 में इस जगह पर डीम्ड स्किल यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव को खादी ग्रामोद्योग काउन्सिल ने मान्यता दी है। …(व्यवधान)

(1230/SK/SM)

इस प्रस्ताव में इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलपमेंट, होस्टल, वोकेशनल ट्रेनिंग्स, इंडस्ट्री में लगने वाले कुशल रोजगार कोर्सिस, उद्योग में उपयुक्त कोर्सिस, टेक्नोलॉजी इन्क्युबेशन सैंटर आदि हर क्षेत्र में भारत के नवयुवक आगे रहें, ऐसे कोर्सिस का समावेश किया गया है, परंतु यह प्रस्ताव प्रलंबित है। …(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय से विनती करता हूं कि भारत के हर क्षेत्र में कुशल युवकों को आगे बढ़ने के लिए नासिक खादीग्राम उद्योग की जगह पर एमएसएमई ट्रेनिंग सैंटर को मान्यता दी जाए। धन्यवाद।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): माननीय अध्यक्ष जी, जब से देश में नागरिकता कानून लागू हुआ है, तब से लगातार विश्वविद्यालयों में, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी में पुलिस का अत्याचार बढ़ गया है। छात्र शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जबरदस्ती लाइब्रेरी में घुसकर पुलिस ने छात्र-छात्राओं पर हमला किया।…(व्यवधान) उसकी फुटेज अगर दुनिया के सामने आ जाएगी तो पूरा देश शर्मसार हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से अपील है कि उस फुटेज को आप अपनी कस्टडी में लें।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री गिरीश चन्द्र, श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री मलूक नागर को कुंवर दानिश अली द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): माननीय अध्यक्ष जी, मैं महत्वपूर्ण सवाल की तरफ संसद का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये लोग हल्ला कर रहे हैं।…(व्यवधान) जनता और समाज के पैसे से सारे शिक्षण संस्थान चलते हैं। जब जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय माननीय इंदिरा गांधी जी ने प्रारंभ किया था, तब इस देश की संसद में बताया था कि जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय इसलिए खोला जा रहा है कि देश के गांवों से बच्चे आकर यहां पढ़ेंगे। …(व्यवधान) मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है

कि जनता के पैसे से चलने वाले जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में इसी तरह की राष्ट्र विरोधी बातें हो रही हैं, जैसे ये लोग कह रहे हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, आजादी के पहले जो बात पहले कभी मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे, वही बात ये लोग कह रहे हैं।…(व्यवधान) जो राष्ट्र विरोधी बातें जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में कही जा रही हैं, वही बातें यहां कही जा रही हैं। …(व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय थोड़े दिन के लिए बंद कर देना चाहिए, इस पर जांच बैठानी चाहिए।…(व्यवधान)

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि संसदीय क्षेत्र बुलढाणा में 13 तहसील आती हैं, और वहां एक भी शासकीय मेडिकल कॉलेज उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र में अत्याधुनिक शासकीय स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध नहीं है। दिनांक 22.05.2018 को माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय महाराष्ट्र में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मेडिकल कॉलेज शुरू करने हेतु प्राथमिक जांच पड़ताल के लिए समिति का गठन करते हुए आदेशित किया था।…(व्यवधान) तदुपरांत समिति ने दिनांक 08.06.2018 को बुलढाणा में आकर बैठक की और उसके बाद उन्होंने छ: आरोग्यधाम महिला बाल चिकित्सालय आदि जगहों का निरीक्षण किया। नीति आयोग की 15 जून की बैठक में भी बुलढाणा में मेडिकल कॉलेज शुरू करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन आज तक मेडिकल कॉलेज का कार्य आरंभ नहीं हो सका है।…(व्यवधान)

अत: आपसे निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा में अतिशीघ्र मेडिकल कॉलेज खुलवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Government hospitals are taking care of the patients …(*Interruptions*) Medicines are being given …(*Interruptions*). Sir, I will take the call next.

माननीय अध्यक्ष: आप अपने ही माननीय सदस्य को बोलने नहीं दे रहे हैं। श्रीमती रम्या हरिदास, आप सीट पर जाइए और महत्वपूर्ण विषय को उठाइए।

…(व्यवधान)

(1235/MK/AK)

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रीवा में भारी वर्षा के कारण मूंग एवं उड़द की फसल को भारी नुकसान हुआ है एवं धान में कंडो रोग से धान की फसल को भारी क्षति हुई है। परन्तु, केंद्र से मिले एक हजार करोड़ राहत राशि में रीवा जिले के किसानों को एक रुपया भी राहत राशि नहीं दी गई । जो धान बची थी, मध्य प्रदेश सरकार ने 40-40 किलो मीटर पर खरीदी केंद्र बनाए, जिससे छोटे किसानों को खरीदी केंद्र तक पहुंचने में काफी समस्या हुई एवं धान खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाना नहीं रखे गए। …(व्यवधान)

मध्य प्रदेश सरकार ने निर्धारित तिथि के दस दिनों बाद खरीद प्रक्रिया शुरू की एवं 20 जनवरी को बंद कर दी। भाजपा के संघर्ष के कारण बाद में 30 जनवरी से 2 फरवरी तक धान खरीदी

की, परन्तु खरीदी केंद्र मिसरगवां, रिमारी, अतरैला, सेवा सहकारी समिति वाकघाट, परसिया में अभी तक एक दाना धान नहीं खरीदी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने अब आगे खरीदी करने से इंकार कर दिया है। रीवा का किसान हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहा है। किसान अभी भी खरीदी केंद्रों पर बैठे हैं।...(व्यवधान)

सहकारी समितियों से यूरिया गायब है जबकि बाजार में खुलेआम बिक रही है। व्यापारी उनकी मनमानी कीमत ले रहे हैं तथा जिन पदार्थों को किसान नहीं लेना चाहते उसे भी जबरन खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है।...(व्यवधान)

यह सब रीवा जिले की जनता को दंडित करने के लिए किया जा रहा है क्योंकि आठ की आठों विधान सभा क्षेत्रों में रीवा के मतदाताओं ने भाजपा विधायक को चुना है।

महोदय, ये लोग आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। रीवा के किसानों का, मध्य प्रदेश के किसानों का गला घोंटने का काम कांग्रेस पार्टी के लोग शोर मचाकर कर रहे हैं, जिसके कारण मैं अपनी बात सदन में ठीक से नहीं रख पा रहा हूं। लेकिन, आपसे अनुरोध है कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि रीवा के किसानों की धान की खरीदी की जाए और सहकारी सेवा समितियों के माध्यम से यूरिया की खाद का वितरण किया जाए।

ये कांग्रेस के लोग किसान विरोधी हैं, इसलिए आज ये हमारी बात का गला दबाने का काम कर रहे हैं। ये हिटलर और मुसोलिनी की संताने हैं, जिनका कभी भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री मलूक नागर को श्री जनार्दन मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। प्रयागराज में नैनी क्षेत्र है जो मेरे संसदीय क्षेत्र इलाहाबाद में आता है।...(व्यवधान) यहां पर भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी है, जो भारत की एकमात्र सार्वजनिक और निजी कंपनियों में से है। यह कंपनी भारी क्षमता के पंप्स एंड कंप्रेसर्स बनाती है और ओएनजीसी, ओआईसीएल और एनपीसीआईएल को सप्लाई करती है। इसकी प्राइसेज इतनी कंपीटिटिव है कि विदेश से आने वाले जो पंप्स एंड कंप्रेसर्स हैं, उन्हें भी इसकी प्राइसिंग की वजह से अपनी प्राइसेज लो रखनी पड़ती है। यह कंपनी वर्तमान में मुनाफे में चल रही है।...(व्यवधान) इस कंपनी के जो हालात खराब हुए थे, वे अब ठीक हो चुके हैं। एक समय में यह मिनी रत्न कंपनी भी रह चुकी है। लेकिन, मेरे संज्ञान में आया है कि संभवत: अधिकारियों एवं सचिवों के स्तर पर इस कंपनी को बंद करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मैं आदरणीय मंत्री जी से और सरकार से अपील करती हूं कि नैनी का औद्योगिक नगर धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है, उसको बचाएं और ओएनजीसी और ओआईसीएल वगैरह को, जो हमारी भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स सप्लाई देती है, उसको कंटीन्यू रखें। जनहित में यह कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

1238 hours

(At this stage, Shri Gaurav Gogoi *and some other hon. Members went back to their seats.)*

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, it is shocking to note that for the last six months three former Jammu and Kashmir Chief Ministers, including 84-year-old Dr. Farooq Abdullah, have been languishing in jail illegally. It is totally an illegal detention. …(*Interruptions*)

However, in spite of our protest, the Government is hell-bent on putting them behind bars. …(*Interruptions*) So, finding no alternative and out of desperation we are staging walkout from the House in protest. …(*Interruptions*)

1239 hours

(At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi, Shrimati Supriya Sadanand Sule *and some other hon. Members left the House.)*

श्रीमती गोमती साय (रायगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। यह मामला छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा का मामला है। …(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़-बिलासपुर एवं सरगुजा हाथी प्रभावित संभाग हैं। बिलासपुर संभाग, कोरबा, रायगढ़-सरगुजा संभाग, जसपुर जिला, सरगुजा एवं बलरामपुर जिलों में हाथियों के कारण फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है।…(व्यवधान)

(1240/YSH/SPR)

हाथियों के द्वारा काफी व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। दो-तीन साल में 300 से 400 लोगों की मृत्यु हो चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है इसलिए जंगली इलाकों में ,जहां ग्रामीण लोग रहते हैं, वहां पर शाम को निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है। मेरे निवार्चन क्षेत्र में बादलखोल अभयारण्य है, जिसे एलिफैंट रिसर्च क्षेत्र घोषित किया जाए व वहां प्राकृतिक आवास की व्यवस्था भी की जाए। बादलखोल अभयारण्य हाथियों के लिए काफी घना है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक-एक मिनट में अपना विषय रख दें।

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने के लिए मौका दिया। मैं सरकार और रक्षा मंत्रालय का ध्यान एक बहुत संवेदनशील मुद्दा, जो किसानों से जुड़ा हुआ है, उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में के.के.रेंज में सन् 1956 से लगभग 40 हजार हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसका उपयोग भारतीय सेना के फील्ड एंड आर्टिलरी प्रैक्टिसेज के लिए किया जाता है। सन् 1980 में तेजगांव में 25619 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन भी इस रेंज के विस्तार के लिए नोटिफाइ की गई थी। वर्ष 2005 में इस क्षेत्र को रेडज़ोन भी घोषित किया गया है, जिसके कारण उस क्षेत्र में कोई विकास का कार्य नहीं हो सकता

है। इसी क्षेत्र के 23 गांवों से प्रभावित किसान, जिनकी जमीन इस रेंज के लिए नोटिफाइ की गई है, उनमें बहुत आक्रोश है और वे अपनी भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के खिलाफ हैं। मैं आपके माध्यम से इस मुद्दे का समाधान प्रदान करने के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसानों के आक्रोश को शांत करने के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में सरकार का निर्णय क्या है और साथ ही अधिग्रहण के संदर्भ में स्पष्टीकरण जारी करने की भी व्यवस्था करें।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, I just want to make a request to you. Before the Session, when you convened the meeting of all-Party Leaders, then also we discussed about Dr. Farooq Abdullah, about his age and health. Why should he not be allowed to attend the Parliament Session? Even after that, when the Parliamentary Affairs Minister convened the meeting, the same issue was discussed. I would request you to intimate the House at least as to what is his status. There is Nothing wrong in it. Why should the main Opposition Party suddenly be given a scope to walkout?

My humble submission to the Government also is to intimate the House as to how he is and what is the status of health of Dr. Farooq Abdullah? Please inform us about it.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत केन्द्र सरकार नौकरी ढूंढ़ने वाले व्यक्ति को 100 दिनों की नौकरी गारंटी करती है। केन्द्र प्रयोजित इस योजना के नाते धन जारी न करने के कारण राज्य सरकारे गरीबों और मनरेगा मजदूरों का भुगतान नहीं कर पा रही हैं। वर्ष 2020 में मनरेगा में करीब 15 राज्यों का केन्द्र सरकार ने पैसों का पूरा भुगतान नहीं किया है बल्कि बकाया कर रखा है। उदाहरण के लिए आप उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए। उत्तर प्रदेश का 323 करोड़ रुपया बकाया है और इसका सीधा प्रभाव मेरे संसदीय क्षेत्र अम्बेडकर नगर में पड़ रहा है, जहां मनरेगा कर्मियों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। इसके कारण वे अपना जीवन-यापन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि जो पशु शेड्स बन रहे हैं, उसके अन्दर मनरेगा का पैसा लगाया जा रहा है, जिसके कारण जो पैसा गांवों के विकास के लिए जाना चाहिए था, वह नहीं जा रहा है और इससे विकास नहीं हो पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि ये जो 323 करोड़ रुपये बकाया हैं और खास तौर से जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में जो खेती का सीजन भी नहीं होता है और लोग इस समय मनरेगा की मजदूरी पर निर्भर भी रहते हैं, उन्हें यह पैसा दें ताकि वे लोग अपनी मजदूरी का भुगतान पा सकें। इसकी उचित व्यवस्था करवाई जाए। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी का ध्यान इस विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें 15 राज्यों का पैसा बकाया है।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री अच्युतानंद सामंत व श्री गिरीश चन्द्र को श्री रितेश पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, कि आपने मुझे शून्य काल में मेरे संसदीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का अवसर दिया है। अध्यक्ष महोदय, उदयपुर-अहमदाबाद आमान परिवर्तन का काम तेज गति से चल रहा है। इसकी वर्ष 2009 में घोषणा हुई थी, लेकिन वर्ष 2009 से 2014 तक इस पर मात्र 109 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। जब से देश के प्रधान मंत्री मोदी जी बने हैं, तब से लेकर अभी तक 850 करोड़ रुपये इस परियोजना पर खर्च हो चुके हैं।

(1245/RPS/UB)

यह लगभग 210 किलोमीटर लम्बाई की परियोजना है। इसमें उदयपुर से खारवा-चांदा तक, 25 किलोमीटर तक इस परियोजना का काम पूरा हो चुका है, सीआरएस हो चुकी है, ट्रायल हो चुका है। डूंगरपुर तक 110 किलोमीटर परियोजना है, जिसमें तीन तीन सुरंगें पड़ती हैं। इन सुरंगों का 40 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इनमें से एक सुरंग 840 मीटर लम्बी है, दूसरी 120 मीटर और तीसरी 100 मीटर लम्बी सुरंगें हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी और सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उदयपुर-अहमदाबाद तक, गुजरात राज्य को जोड़ने वाली इस परियोजना के लिए पर्याप्त बजट दिया जाए, जिससे उदयपुर में आने-जाने वाले पर्यटकों को सुविधा मिल सके और यात्रियों को उसका पूरा लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मैं आपका ध्यान इन्दौर के नेशनल हाइवे की ओर दिलाना चाहता हूं। इन्दौर में भंवरकुआं चौराहा से खण्डवा तक नेशनल हाइवे माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में घोषित हुआ, लेकिन उसके घोषित होने के कई माह बाद भी, वह इसलिए नहीं बन पा रहा है कि राज्य सरकार वहां की यूटिलिटी सर्विसेज, खासकर इलेक्ट्रिक पोल नहीं हटा पा रही है। इसके कारण वहां निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। उस रोड पर लगभग 200 से ज्यादा एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, वहां स्कूल हैं, कॉलेज हैं। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार अपने स्तर पर इसका निर्माण कार्य शुरू करे।

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, the novel Coronavirus epidemic of Wuhan, China, which has infected more than 25,000 people and killed 500 people, has created a huge pandemonium and fear among citizens of several, if not all, countries.

We have a case reported in Kerala and a few more suspected cases are also there. This has caused rumours and fears in Tamil Nadu as well. Rumours that medical waste containers from China are being dumped in Tamil Nadu have added to the growing panic. In this situation, the Health Ministry can provide information regarding precautionary measures using print, TV and social media.

Also, novel Coronavirus being a larger virus than the past viruses of the same family, the Health Ministry can ask doctors to research if folded handkerchiefs may provide protection from the spread of virus equivalent to

medical masks. This will reduce the need for medical masks being sold in the country.

I also request that the Departments of the Ministry of Shipping and the Ministry of Health to take adequate measures to allay the fears of the common citizens.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा एवं श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को डॉ. कलानिधि वीरास्वामी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, the hon. Minister should make a statement about this matter.

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Sir, we want a categorical statement from the Health Ministry.

श्री चंदन सिंह (नवादा): अध्यक्ष महोदय, मुझे शून्य काल में बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, मैं नवादा, शेखपुरा एवं जमुई की आम जनता की समस्या से माननीय रेल मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं। आजादी के इतने साल बीतने के बाद भी मेरे संसदीय क्षेत्र नवादा से देश की राजधानी दिल्ली के लिए एकमात्र साप्ताहिक ट्रेन भागलपुर-नई दिल्ली एक्सप्रेस है, जिससे वहां की जनता को आवागमन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि गाड़ी संख्या 12397 और 12398 महाबोधि एक्सप्रेस का परिचालन नई दिल्ली से गया एवं गया से नई दिल्ली तक होता है। यह गाड़ी नई दिल्ली से दोपहर 12.10 बजे चलकर, सुबह तीन बजे गया पहुंचती है एवं पुन: गया से दोपहर 2.15 बजे चलकर सुबह साढ़े चार बजे दिल्ली पहुंचती है। यह गाड़ी गया में करीब नौ घण्टे खड़ी रहती है। ऐसी परिस्थिति में, अगर इस गाड़ी का परिचालन गया से बढ़ाकर किऊल किया जाता है तो यह गाड़ी नवादा, शेखपुरा एवं जमुई लोक सभा क्षेत्र से होकर गुजरेगी, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र के आम नागरिकों को दिल्ली आने-जाने में काफी सहूलियत होगी। इसके साथ ही, रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी। अत: मैं इस सदन के माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि जनहित में गाड़ी संख्या 12397 और 12398 महाबोधि एक्सप्रेस का परिचालन गया की जगह किऊल से किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री चंदन सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1250/RAJ/KMR)

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया है। हमारे लोक सभा क्षेत्र फर्रूखाबाद और इसके आस-पास कई लोक सभा क्षेत्रों में और देश के कई प्रान्तों में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आलू सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। आलू एक ऐसी सब्जी है, जिसका पूरे देश में साल में 365 दिन सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि आलू का उत्पादन कम हो जाए, तो देश में अन्य सब्जियों के दाम

आसमान छू जाते हैं। जहां किसान देश में आलू का उत्पादन करते हैं और अन्य सब्जियों के दाम भी नियंत्रित करते है, वहीं किसानों को आलू का लाभकारी मूल्य नहीं मिलने के कारण, उनका हाल बेहाल है।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार मसाला बोर्ड की स्थापना करने से मसाला उत्पादक किसानों की दशा में आशातीत सुधार हुआ है, इसी प्रकार जूट बोर्ड, टी बोर्ड, आदि की तरह राष्ट्रीय आलू विकास बोर्ड की स्थापना कराई जाए। आलू विकास बोर्ड के गठन से भारत में आलू प्रसंस्करण उद्योग का भी समग्र विकास होगा और क्षेत्र की आलू की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसके साथ-साथ आलू के उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति में भी व्यापक परिवर्तन आएगा एवं आलू आधारित उद्योगों को भी नई संजीवनी मिलेगी।

महोदय, मेरा एक और अनुरोध है कि मिड-डे मील योजना में भी सप्ताह में दो बार आलू सब्जी के रूप में उपयोग हो।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री मुकेश राजपूत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस पवित्र सदन में सरकार का ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, माल्दहा उत्तर, पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, अभी तक हमारे संसदीय क्षेत्र में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। वहां रेलवे का एक बड़ा केन्द्र होने के साथ-साथ, केन्द्रीय सेवा के हजारों कर्मचारी निवास करते हैं, लेकिन उनके बच्चों को समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र सम्सइ में शीघ्र अति शीघ्र एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने हेतु यथोचित कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री खगेन मुर्मु द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राम शिरोमणि (श्रावस्ती): अध्यक्ष महोदय, मैं अति महत्वपूर्ण विषय पर आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान लोक सभा श्रावस्ती के जिला बलरामपुर के विकास खण्ड गैसडी के ग्राम सभा डालपुर बकौली में ग्राम भंवरिया से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 पर जाने वाले संपर्क मार्ग पर रेलवे लाइन के दोनों तरफ रेलवे विभाग द्वारा मार्ग को जेसीबी मशीन लगा कर गहरा गड्ढा खोद दिया गया है। मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण गांव के किसानों को अपना गन्ना क्रय केन्द्रों पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यह गांव भाभर नाला व बरूनी नाला से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। मानव रहित संपर्क मार्ग होने के कारण रेलवे के अधिकारियों द्वारा इसे आये दिन सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया जाता है, जबकि ग्रामीणों के लिए घर से दो पहिया या चार पहिया वाहन से निकल कर मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए यही एकमात्र विकल्प है।

अत: आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि किसानों की विकट समस्या को देखते हुए जनहित में मानव रहित रेलवे लाइन के पास एक अंडर पास मार्ग बनवाने का कष्ट करें, जिससे ग्रामीणों के आने-जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री मलूक नागर और श्री गिरीश चन्द्र को श्री राम शिरोमणि द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रामदास तडस (वर्धा): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा के अंतर्गत 3 तारीख को एक घटना हुई है कि सुबह साढ़े सात बजे युवती अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रही थी, तो उसके ऊपर पेट्रोल डाला और उसको जला दिया। पूरे महाराष्ट्र में इससे हलचल मची।

मेरी आपसे विनती है कि युवती की आर्थिक परिस्थिति बहुत ही बेकार है, उसको आर्थिक मदद देनी चाहिए। यह केस जल्द से जल्द निकाय में लगना चाहिए और कड़ी से कड़ी शिक्षा दी जानी चाहिए। यह केस प्रसिद्ध अधिवक्ता उज्ज्वल निकम को देना चाहिए। मेरी आपसे विनती है कि महाराष्ट्र सरकार को इस विषय में शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करें, तथा भारत सरकार की ओर से पीड़ित युवती को उचित सहायता देने की कृपा करे।

(1255/VB/SNT)

श्री सैयद इम्तियाज़ जलील (औरंगाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सहयोगी ने मुद्दा उठाया कि महाराष्ट्र के वर्धा जिले में जिस महिला को जिन्दा जलाया गया, वह एक नौजवान लड़की थी। उसको एकतरफा प्रेम के कारण जिन्दा जला दिया गया। हमारी सहयोगी श्रीमती नवनीत राणा ने भी यह मुद्दा उठाया था। एक दिन के बाद औरंगाबाद, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, के सिल्लौड़ में रात के साढ़े ग्यारह बजे एक आदमी, जो बीयर बार चलाता है, वह एक महिला के घर पर गया और उस महिला के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने की बात की। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसके ऊपर गैस-तेल डालकर उसे जिन्दा जला दिया। वह महिला 95 परसेंट तक जल चुकी है और जिन्दगी एवं मौत से जूझ रही है।

मैं चाहूंगा कि संतोष नाम का आदमी, जो आरोपी है, जो बीयर बार चलाता है, कानून मंत्री जी आप यहाँ पर मौजूद हैं, हमने इससे पहले भी कहा है कि शराब की दुकानें कब तक चलाएंगे? वह आदमी बीयर बार चलाता था। जिस महिला की जान गई है, उस बेकसूर महिला का उससे कोई लेना-देना नहीं है, उसके घर में ज़बरदस्ती घुसकर उसे जिन्दा जला देता है। दो दिनों में इस तरह की लगातार दो घटनाएँ हुई हैं। हम सरकार से चाहेंगे कि जो भी आरोपी हैं, इन दोनों केसेज को फास्ट ट्रैक कोर्ट से चलाकर दोनों आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। यह मेरी माँग है।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री सैयद इम्तियाज़ जलील द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण इश्यू उठाना चाहूँगा, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अटेंशन भी जरूरी है।

ब्रिटिश जमाने का सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसने हिन्दुस्तान का नक्शा ड्रा किया है। मेरे पार्लियामेंट्री क्षेत्र में अनिनी क्षेत्र है, जो एक रिमोट ईस्टर्न ट्रायंग्ल क्षेत्र है। म्यांमार, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर आंगिए वैली है, जिसको मिलिटेरिली पीसटेल वांग का नाम दिया गया है। इसका सौ किलोमीटर से ज्यादा भाग चाइना के मैप में ड्रा किया हुआ है। हमारे बॉर्डर आउट पोस्ट्स अन्दर हैं, लेकिन वे आउट पोस्ट्स चाइना के नक्शे में दिखाए गए हैं।

दूसरा मुद्दा है, अंजॉ जिले के बारे में मैंने लास्ट टाइम चाइना इश्यू में कहा था, दराई वैली में हाडिंग्रा, दागरू, गलाई-तागरू, तातू पास आउट पोस्ट्स हैं, ये सारे आउट पोस्ट्स मैकमोहन लाइन पर हैं। लेकिन सौ किलोमीटर से ज्यादा हिन्दुस्तान का भाग काटकर चाइना के मैप में दिखाया हुआ है।

जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में पीओके को इंडियन पॉलिटिकल मैप में डाला गया है, उसी तरह से अंजॉ जिले का आंगिए वैली, दिबांग जिले का वैली और सांगलागाम जिले के दराई और कोयू वैलीज को इंडियन पॉलिटिकल मैप में वापस ड्रा करना होगा, क्योंकि इंडिया और चाइना का झगड़ा उसी के कारण है। पॉलिटिकल मैप में चाइना का नक्शा बनाकर रखा गया है, लेकिन इंडियन आर्मी आउट पोस्ट्स को बाहर दिखाती है।

इसलिए जिस तरह से पीओके को इंडियन मैप में लाया गया है, उसी तरह से इनको भी इंडियन पॉलिटिकल मैप में लाना चाहिए, सरकार से मैं यही माँग करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री रितेश पाण्डेय को श्री तापिर गाव द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): सर, लॉ मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे विनती करूँगी कि रोज जिस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, उसे बंद करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। इसके लिए विशेष कदम उठाना होगा, नहीं तो कोई किसी को जला देता है, कोई किसी पर एसिड डाल देता है, कोई मार देता है, कोई चाकू से मार देता है, अगर हमें ये सारी घटनाएँ बंद करनी हैं, तो हमें इसके लिए कुछ काम करने ही पड़ेंगे।

मैं सभी महिला सांसदों से आग्रह करती हूँ कि सभी को इस पर अपनी बात कहनी चाहिए।

(1300/GM/PC)

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): सर, हमारी आदरणीय बहन सदस्यों ने महाराष्ट्र के बारे में जो चिंता उठाई है, मैं उनकी चिंता के साथ हूं। यह निर्णय करने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार का है। इस सदन में उन्होंने अपनी बात उठाई है, महाराष्ट्र सरकार सुन रही है। हम भी अपनी ओर से उनको बताएंगे कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। …(व्यवधान) आप एक मिनट के लिए बैठिए।

सर, जहां तक 'निर्भया' का सवाल है, यह बात मैं बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको फांसी की सजा हो गई। माननीय राष्ट्रपति जी ने उनकी दया याचिका को अस्वीकृत कर दिया, फिर भी कानून का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर के वे सभी सज़ायाफ़्ता अपराधी उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह उचित नहीं है। …(व्यवधान) आपने देखा होगा कि सरकार दिल्ली हाई-कोर्ट में खुद गई, उस निर्णय के खिलाफ, जो लोअर-कोर्ट ने किया था। …(व्यवधान) हम इस पर बिलकुल सख्त हैं कि निर्भया, जो इस देश की बेटी थी, उसको पूरा न्याय मिलना चाहिए और फांसी की सज़ा जल्द से जल्द होनी चाहिए, यह हमारा विश्वास है। …(व्यवधान) यह हम कहना चाहेंगे। …(व्यवधान)

श्री अच्युतानंद सामंत (कंधामल): ऑनरेबल स्पीकर सर, शून्यकाल में आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं ओडिशा का एक इम्पॉर्टेन्ट सब्जैक्ट – नेशनल ट्राइबल म्यूज़ियम फॉर ओडिशा के बारे में बोलूंगा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। …(व्यवधान) आपकी कृपा होते ही शून्यकाल में बोलने का मौका मिलता है। मेरा नाम आज तक लॉटरी में नहीं आया है। …(व्यवधान) Odisha is home to as many as 62 tribes including 13 Particularly Vulnerable Tribal Groups. The State of Odisha has a number of PVTGs. In terms of percentage, they constitute 24 per cent of the total population of the State. These tribes form the soul of the State. Odisha is proud of the cultural diversity brought over by them. It is imperative that we preserve, promote and educate the public about their rich culture, tradition and legacy. Keeping this in mind, I request the Central Government, particularly the Ministry of Tribal Affairs, to set up the National Tribal Museum in Odisha in line with the one proposed in Ranchi. It will help the current and future generations to understand the tribal art and culture. The tribal communities embody the sustainable practices we all must strive to meet. Our hon. Chief Minister Shri Naveen Patnaik has undertaken numerous measures for inclusive growth, development of tribal areas, welfare of the tribal people and preservation and promotion of their cultural heritage by setting up unique Special Development Councils in various tribal districts. The rich diversity of tribal culture in Odisha makes it a perfect place to showcase the tradition and heritage of the

tribes present in the country. We will appreciate if the Central Government considers our request to set up the National Tribal Museum in Odisha.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री अच्युतानंद सामंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): Respected Speaker, Sir, the hon. Member Shri T.N. Prathapan raised the issue in this House. I would like to draw your attention to a serious matter. It is important. Three persons' blood samples tested positive for coronavirus at Alappuza, Thrissur and Kasaragod, and about 2,000 persons are in observation. The Kerala Government has taken positive and corrective measures to eliminate and prevent this dreadful disease. Government has opened isolation wards and other facilities in medical colleges, district hospitals, and taluk hospitals, including private hospitals. Kerala must be more vigilant and needs expert and financial aid from the Central Government. I request the Central Government to announce a special package for Kerala Government and send a full-fledged medical team to Kerala.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती राम्या हरिदास द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI COSME FRANCISCO CAITANO SARDINHA (SOUTH GOA): Hon. Speaker, Sir, I would like to bring to the notice of the Railway Minister that train no. 12133/12134 Mumbai-Mangalore-Mumbai Express used to halt at Karmali station near Panji, the capital of Goa. That halt has now been withdrawn. The train was started from 29th January 2019 on public demand when the Railway Minister had visited Goa.

(1305/RK/SPS)

Suddenly, the halt of this train has been withdrawn from 28th January, 2020, thus putting the whole of North Goa in difficulty as the only halt now is at Madgaon, South Goa. People from North have to go all the way to Ratnagiri to catch the train. I would request the Railway Minister, through you, to restart this halt. Goa is a tourist place. A number of tourists visit Goa and travel from North to South Goa.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री कास्मे फ्रांसिस्को कोईटानो सर्दिन्हा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Thank you for the opportunity, Sir. The cultural deposits unearthed by the Archaeological Survey of India at

the Keeladi excavation site on the bank of river Vaigai in the State of Tamil Nadu, indicate high literacy of the contemporary Tamil society that lived in the 6th century BCE in this region, that is, at least three centuries earlier than we previously thought. More evidence is needed to prove that there was a thriving river Vaigai Valley Civilization or an urban civilization in the southern districts of Tamil Nadu State.

Hon. Union Finance Minister has allocated Rs.3,150 crore in the Budget for the financial year 2020-21 for the establishment of on-site museums near archaeological sites in the country. The subject matter, Keeladi excavation site situated in Tamil Nadu, is not included in the list.

Hence, through you, I would urge the Union Government to allocate funds and issue order for subsequent phase work of Keeladi excavation in order to bring to fore the archaeological richness of my mother-tongue Tamil to the world.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): महोदय, आज सारे देश और दुनिया में पानी का भयंकर संकट आने वाला है। पर्यावरण को देखें तो दिल्ली भी कई बार प्रदूषित हो जाती है। हमको पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। माननीय प्रधान मंत्री जी की भी सोच है कि किसी प्रकार से पानी को बचाया जाए। हमें पौष्टिक आहार मिले, नहीं तो बीमारियां फैलती हैं। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार को सुझाव है कि ज्वार, बाजरा, जौ, सरसों, तिलहन, दाल के एम.एस.पी. को दोगुना कर दिया जाए तथा गेहूं और चावल का रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये केवल पेट भरने के काम आते हैं। बाजरा, जिसमें आयरन ज्यादा होता है, चना, ज्वार आदि इस प्रकार की फसलों से पौष्टिक तत्व मिलेंगे, आहार अच्छा मिलेगा, बीमारियां दूर होगी, डी.ए.पी. यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो अवशेष से प्रदूषण फैलता है, वह भी बंद हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन फसलों के दाम दोगुने करके दाना-दाना खरीदा जाए, ताकि आम आदमी बीमारी से बच सके और पानी का भी बचाव हो सके।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री धर्मवीर सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मेरे भिवंडी लोक सभा क्षेत्र में मध्य रेलवे में कसारा स्टेशन है। वहां दो दिन पहले छोटा टनल होने की वजह से जब भीड़ ज्यादा हुई तो भगदड़ मची। इससे पहले भी दो बार ऐसा हुआ है और वहां दो लोगों की मृत्यु हुई है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कसारा स्टेशन पर जो छोटा टनल है, उसे जल्द से जल्द से बड़ा करके यात्रियों को जो असुविधा हो रही है और यात्रियों की जो जानें जा रही है उससे उनको बचाने के लिए जल्द से जल्द उपाय करें।

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): अध्यक्ष जी, हम भी सदन में दुबले-पतले बैठे हैं, हमें भी मौका दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: अब इस सदन में आपका मौका कभी नहीं आएगा, आप बैठ जाइए। आप सदन में इस तरह से उठेंगे तो आपका इस सत्र में कभी भी अतिरिक्त समय नहीं आएगा।

(1310/MM/PS)

*SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR): I thank you, Hon. Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak on a subject of urgent public importance. Sir, I draw you attention towards my constituency Amritsar. The previous Central Government had granted the setting up of an AIIMS institute in Amritsar. However, the present Government has shifted that AIIMS to Bathinda. During the 550th anniversary celebrations of Shri Guru Nanak Dev ji, the Central Health & Family Welfare Minister and Punjab Chief Minister held a meeting and it was decided that another AIIMS institute would be granted to Punjab. In Malwa region of Bathinda, an AIIMS has been granted. PGI is there in Chandigarh. In Ludhiana, there are good hospitals like CMC & DMC. Jalandhar also has a good hospital. International airport is there in Amritsar. Good road infrastructure is also there. Tarn Taran, Gurdaspur and Amritsar can gain out of it if the Central Health and Family Welfare Minister grants the second AIIMS to Amritsar. The people of holy city of Amritsar should also be allowed to avail the benefits of an AIIMS institute.

Thank you.

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे झारखण्ड के जमशेदपुर लोक सभा क्षेत्र में हाथियों द्वारा परसों तीन आदमी जो बाजार से, हाट से जा रहे थे, उनको कुचल कर मार दिया। पिछले एक साल से देखा जाए तो लगभग 25 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लगभग तीन सौ घरों को हाथियों के द्वारा तोड़ा गया है। चाकुलिया, बहरागोड़ा तहसील, पट्टमदा तहसील और घाटशिला में खासा प्रभाव है। अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की सीमा को काट दिया गया है, वहां गड्ढे कर दिए गए हैं, जिससे हाथियों का आना-जाना बंद हो गया है। इससे हाथी इन चार प्रखण्ड में सीमित हो गए हैं। हाथी आए दिन लोगों को कुचलकर मार रहे हैं। इसके लिए मुआवजा भी बहुत कम दिया जाता है, दो-ढाई लाख रुपये ही दिए जाते हैं।

मैं आपके माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसका मुआवजा कम से कम दस लाख रुपये किया जाए और जिनके मकान तोड़ दिए जाते हैं, उनको भी मुआवजा दिया जाए ताकि लोगों के रहन-सहन में दिक्कत न हो।

---

* Original in Punjabi

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री एच. वसंतकुमार। वसंतकुमार जी सदन में बोलने के लिए रोज सूट पहनकर आते हैं।

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANNIYAKUMARI): Thank you very much, hon. Speaker, Sir, for giving me this opportunity to speak.

In Kanniyakumari district, there is only one National Highway. For the past two years, it has not been repaired. Nothing has been done to repair the same. The people of Kanniyakumari including the students are suffering very much due to the same problem. They are also blaming me saying that Vasanthakumar is unable to get the road repaired.

Through you, I would like to request the Ministry concerned to expedite the repair work of the road. It is the only National Highway in Kanniyakumari. When we meet the contractor, he does not tell us anything about the road. He is always smiling. The Government officers are also not doing anything. It is my request to you to get the road repaired expeditiously and ensure the safety of our people.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री एच. वसंतकुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने लोक सभा क्षेत्र गढ़वाल के एनएच-121 के पौढ़ी से लेकर बुआखाल, पावो, थलीसैंण, बैजरो, बीरोंखाल और रामनगर तक के विस्तारीकरण के लिए माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा।

मान्यवर, यह एनएच दसों साल से है और यह रामनगर से भी जुड़ता है, जहां कार्बेट नेशनल पार्क है। वहां के जंगली जानवर भी इन गड्ढों के कारण कई बार एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। वहां मानवीय एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। वहां चार पुल हैं और दो सैंक्शन्ड भी हैं, लेकिन अभी उन पर काम शुरू नहीं हुआ है। साथ ही, यह रोड दो सौ किलोमीटर का है और यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मेरा आपके माध्यम से सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): अध्यक्ष महोदय, मैं किशनगंज से चुनकर आता हूं जो बिहार के एक कोने में है। मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली और चेन्नई तक जाना पड़ता है। सरकार ने यह निर्णय लिया था कि एम्स की एक शाखा बिहार में खुलेगी। मैंने पिछले सत्र में भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया था और आज भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के लिए बिहार सरकार ने दो सौ एकड़ जमीन को चिह्नित करके प्रपोजल भी भेजा है। मैं चाहता हूं कि

आपके ज़रिए जोर लगे ताकि किशनगंज, जो बिहार के कोने में है, जो पश्चिम बंगाल को भी केटर करता है और असम के लोग भी इलाज करा सकते हैं, इसलिए एम्स की दूसरी शाखा किशनगंज जिले में खोलने की कृपा करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1315/RC/SJN)

SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity.

The economy of Tiruvannamalai Parliamentary Constituency is mainly agrarian based. Water scarcity in that area affects agricultural production. There is no industrial set up in that area. This constituency is also backward and people are largely unemployed. Even the tourism sector in that area has not picked up due to infrastructural constraints. In order to boost the economy of my constituency, industrial development may be given priority.

I, therefore, seek intervention of hon. Finance Minister to extend a special economic package for the development of Tiruvannamalai area.

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिए दो बजे तक स्थगित की जाती है।

1316 बजे

<u>तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न-भोजन के लिए चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।</u>

(1400-1405/KN/RU)

1406 बजे

मध्याह्न-भोजन के पश्चात् लोक सभा चौदह बजकर छः मिनट पर पुनः समवेत् हुई।
(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले- सभा पटल पर रखे गए

माननीय अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पार्ट को व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर रख सकते हैं। यह 20 मिनट वाला क्लॉज हटा दिया है।

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सर, फ्राइडे को भी अनुमति दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : आप सब के सहयोग से फ्राइडे को भी अनुमति दे दी गई है।

Re: Need to introduce double degree programme for students of IIITs in the country

श्री अजय कुमार (खीरी): छात्रों की मांग व जरूरत को पूरा करने हेतु भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा दोहरा डिग्री कोर्स प्रारंभ करने की सूचना है जिसके तहत कोई भी छात्र बी.टेक के साथ एम.टेक या एम.बी.ए. की डिग्री 6 वर्ष के बजाय 5 वर्ष में उक्त कोर्स को पूरा किया जा सकेगा जिससे छात्रों को महत्वपूर्ण एक वर्ष का समय बच सकेगा। फिलहाल सिर्फ दोहरे कोर्स बाम्बे, दिल्ली व मद्रास जैसे कुछ चुनिंदा आई.आई.टी. में शुरू किए गए हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि दोहरे डिग्री कोर्स शोध व फैकल्टी से जुड़े विषयों को आई.आई.टी. दिल्ली की तरह दूसरे संस्थानों से मिलकर ऐसे कोसों का निर्णय लेने व लागू करने हेतु भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान काउंसिल को निर्देशित करके सभी 25 आई.आई. आई. टी. संस्थानों में दोहरे डिग्री कोर्स व पी.एच.डी. की सीधी सुविधा प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(इति)

Re: Need to accord the status of Classical Language to Marathi language

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): मराठी भाषा को Classical language (प्राचीन भाषा) का दर्जा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को भाषीय विशेषज्ञ सामिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। उक्त समिति ने मराठी भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी।

उक्त सिफ़ारिशों पर केन्द्रीय संस्कृति मन्त्रालय में विचार किया जा रहा था तथापि इस विषय पर माननीय मद्रास उच्च न्यायालय मे दायर अनेक रिट याचिकाओ के आलोक मे निर्णय लिया गया कि उक्त रिट याचिकायों के परिणाम की प्रतीक्षा की जाए। मद्रास स्थित माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण ने अब इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना करते हुए दिनाक 8-8-2016 के सामान्य आदेश द्वारा इन रिट याचिकाओ का निपटान कर दिया है। तदुपरान्त, मराठी भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव पर पुनः केन्द्रीय संस्कृति मन्त्रालय मे संक्रिय विचार किया जा रहा है। मैंने विगत लोक सभा में भी नियम 377 के अधीन दिनांक 6 फरवरी, 2017 में इस प्रकरण को उठाया था।

लेकिन, केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय ने मराठी भाषा को Classical Language (प्राचीन भाषा) का दर्जा प्रदान किए जाने के बारे में अब तक क्या निर्णय लिया है, उसकी कोई सूचना आज तक प्राप्त नहीं हुई है।

अतः मेरा पुनः अनुरोध है कि मराठी भाषा को Classical Language (प्राचीन भाषा) का दर्जा प्रदान किए जाने के बारे में मंत्रालय ने क्या निर्णय लिया है, उसकी सूचना भिजवाई जाए।

(इति)

(PP 319-320)

Re: Need to commission a project for eradication of poverty and backwardness in Mahasamund, Gariaband and Dhamtari districts in Chhattisgarh

श्री चुन्नी लाल साहू (महासमुन्द): छत्तीसगढ़ के लोक सभा क्षेत्र महासमुंद अन्तर्गत महासमुंद के साथ जिला गरियाबंद व जिला धमतरी (मगध) सीमावर्ती क्षेत्र राज्य ओड़ीसा से लगा है। इन तीनों ही क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक परिदृश्य में समानता है। जिसके उत्थान के लिए (मगध) प्रोजेक्ट बनाकर यहाँ के लोगों को पलायन एंव अति दयनीय गरीबी स्थिति से बचाया जा सकता है। जैसा कि कुछ वर्ष पहले जिला कालाहांडी पिछड़ापन व अकाल की स्थिति व पीड़ित अवस्था में था। जहां पिछड़ापन व अकाल कि स्थिति का उन्मूलन करने के लिए के बी के प्रोजेक्ट बनाकर कालाहांडी, बालनगीर, कोरापुट के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा उस क्षेत्र का विकास कराया गया। जिससे वहाँ की दयनीय स्थिति में सुधार हुआ है। ठीक उसी प्रकार से (महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी) के लिए (मगध) प्रोजेक्ट बनाकर उन्मूलन हेत् अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कर यहाँ के लोगो को अत्यंत गरीबी एंव पिछड़ेपन के कारण अति दयनीय अवस्था को सुधारने व पलायान को रोकने हेतु उचित कार्यवाही आतिशीघ्र कराए जाने की आवश्यकता है।

महोदया मैं सदन के माध्यम से उक्त विषय जो जन-जन की आवाज है सरकार के संज्ञान लाते हुये पुरजोर मांग करता हूँ।

जय जौहर - जय छत्तीसगढ़

(इति)

Re: Need to introduce PM National Dialysis Programme in Bihar particularly in Maharajganj parliamentary constituency in the State

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज): महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम की घोषणा सरकार द्वारा 2016 में की गई थी। इसके तहत किडनी के मरीजों को उनके घर पर ही पेरिटोनियल डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है ताकि डायलिसिस के लिए मरीजों को दूर बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। इस योजना द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को किट और दवा मुफ्त में मिलेगी व अन्य को रियायती दामों पर उपलब्ध कराया जायेगा।

विदित हो कि मेरा संसदीय क्षेत्र महाराजगंज लोक सभा, बिहार स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से एक अत्यन्त ही पिछड़ा क्षेत्र है। हमारे संसदीय क्षेत्र में प्रतिवर्ष अनेक संख्या में किडनी के मरीजों को इलाज व डायलिसिस के लिए अन्यत्र दूसरे दूर-दराज के शहरों में जाना पड़ता है। इसके कारण मरीज को समय पर डायलिसिस नहीं होने के कारण मरीज की स्थिति गंभीर हो जाती है साथ में इन्हें अत्यधिक आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ता है।

अतः आपके माध्यम से भारत सरकार के माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि बिहार राज्य सहित मेरे संसदीय क्षेत्र के ऐसे मरीज जिन्हें किडनी की डायलिसिस कराने की आवश्यकता है, उनके लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम को शीघ्र शुरू किये जाने की व्यवस्था की जाये।

(इति)

Re: Need to construct a by-pass road in Pratapgarh district, Rajasthan

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): महोदय,मेरे संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) का प्रतापगढ़ ज़िला एक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। 2008 में इस खूबसूरत शहर को जिला भी बनाया गया। यहाँ तब से लेकर अब तक यहाँ सभी सरकारी कार्यालयो का निर्माण किया गया। यहाँ पर रहने वालों की संख्या में भी अचानक से बढ़ोतरी हुई व देखते ही देखते शहर का विस्तार हो गया। यहाँ एक सड़क बाइपास की जरूरत है। यहाँ प्रतापगढ़ शहर में वाहनों के अत्यधिक दबाव के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाओ की जानकारी आती रहती है। प्रतापगढ़ में बाइपास बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा स्वीकृत भी है। यदि प्रतापगढ़ बे बाइपास के कार्य को वरीयता देते हुए इसे शीघ्ता से बनाया जाता है, तो इससे न केवल इस जनजातीय क्षेत्र का विकास होगा बल्कि आए दिन होने वाली दुर्घटनाओ से होने वाली जान व मान की हानि से भी प्रतापगढ़वासियों को निजात मिल जाएगा।

(इति)

Re: Need to expedite construction of Lower Wardha Irrigation Project in Maharashtra

श्री रामदास तडस (वर्धा): मेरे वर्धा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में निम्न वर्धा प्रकल्प की नींव 1977 में रखी गई, किन्तु आज भी प्रकल्प का काम पूर्ण नहीं होने से नहरें पानी की प्यासी हैं। 42 वर्ष के बाद भी यह प्रकल्प पूर्ण नहीं होने से उसकी लागत 40 करोड़ रुपये से बढ़कर 3615 करोड़ रुपये तक जा पहुंची है। यह प्रकल्प अधूरा होने के कारण किसानों को सिंचाई का लाभ भी पूर्णरूप से नहीं मिल रहा है। प्रकल्प पूर्ण होने के बाद 63,333 हेक्टयर खेती सिंचाई के क्षेत्र में आनेवाली थी, परंतु वास्तविकता में अब तक केवल 41, हेक्टयर भूमि सिंचाई में आई थी।

इस प्रकल्प को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया है। इसके लिए तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने विशेष निधि के तहत रू 481 करोड़ मंजूर किये है। लेकिन इतनी बड़ी राशि उपलब्ध होने के बाद भी अभी तक प्रकल्प का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

(इति)

Re: Conservation of bee species

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Beekeeping is a practice done since ancient times in India. There are communities that exclusively practice beekeeping as a profession. Honey production is also a focus across the National Horticulture Mission and the SFURTI Scheme. However, globally, bee population is declining. Over 500 million bees died in Brazil in the last 4 months. Many specific bee species are endangered across the world. In India, however, there is no official data on the different bee species, their numbers and conservation efforts. Bees are a huge factor in crop pollination and studies have proved that decline in bee populations will severely affect crop yield and also threaten nearly 500 fauna species. While we look at conservation efforts for tigers, elephants and rhinos, we must also make efforts to save these small species that affect the local farmers.

(ends)

Re: Need to enact a law providing for adequate safety and security of labourers engaged in hazardous work

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): देश के बड़े-बड़े शहरों में जहां बड़ी-बड़ी निर्माण परियोजनाएं चल रही हैं जिनमें मजदूर काम करते हैं। इसके अलावा बड़े होटलों तथा सीवर की सफाई आदि में भी बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं। उक्त स्थानों पर काम करने वाले मजदूरों का जीवन सदैव जोखिम भरा होता है। सुरक्षा उपकरणों के बगैर मजदूरों का जीवन सदैव खतरों से भरा रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस स्थिति को अमानवीय बताते हुए कहा है कि सफाई कर्मचारी जैसे मजदूर रोज़ मर रहे हैं। किसी भी देश के मजदूर सुरक्षा उपकरणों के बगैर काम नहीं करते। यह अमानवीय स्थिति है कि मैन होल और नालों में सफाई करने वाले मजदूरों को मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाते हैं। जिसके कारण आये दिन उपरोक्त क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की दुघर्टनाओं में मौत होती रहती है।

इस सम्बन्ध में सरकार से मेरा आग्रह है कि देश में मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर शीघ्र एक कानून बनाया जाए।

(इति)

Re: Movement of commercial vehicles between India and Nepal and establishment of an immigration office at Kakarwaha

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): There is a need to provide for movement of commercial vehicles between India and Nepal and the need to establish an immigration office at Kakarwaha.

(ends)

Re: Need to make medical arrangements at all the airports in the country to screen in-bound passengers for Corona virus

श्री कीर्ति वर्धन सिंह (गौंडा): मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान Coronavirus (2019-ncovi) की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसकी उत्पत्ति चीन देश से होते हुए आस्ट्रेलिया एवं यूरोप के कुछ देशों तक फैल चुका है।

यह अत्यन्त ही गंभीर बीमारी है तथा संक्रमित व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्तियों में आसानी से पहुंच जाता है। अपने देश में भी मुम्बई और केरल राज्य के 6 कोरोना वायरस द्वारा संक्रमित व्यक्तियों पहचान हो पायी है। इन व्यक्तियों को आइसोलेशन वार्ड में रखकर इलाज किया जा रहा है। यह बीमारी महामारी का रूप न धारण कर ले इससे पूरा विश्व चिंतित है।

मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस गंभीर बीमारी को अपने देश में फैलने से रोकने के लिये अन्य मंत्रालयों जैसे कि विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालयों से सामंजस्य बैठाते हुए हर एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर Quarantine की व्यवस्था हो जिससे कि कोई भी संक्रमित विदेशी नागरिक का अपने देश में प्रवेश न हो पाए और इन देशों से आने वाले भारतीय नागरिकों की भी जांच करवाते हुए उनका निकटतम अस्पताल में इलाज कराया जाए।

(इति)

Re: Need to establish a Cancer Hospital in Gorakhpur, Uttar Pradesh

श्री रवि किशन (गोरखपुर): मेरा संसदीय क्षेत्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत बड़ी है। यहाँ एम्स अस्पताल है लेकिन कैंसर का कोई अस्पताल नहीं है। गोरखपुर की आधारभूत संरचना पर आस पास के बीस जिले निर्भर हैं। उन्हें कैंसर का ईलाज करने के लिए दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता है जो मेरे क्षेत्र और आस पास के जिलों और पड़ोसी राज्य बिहार के गरीब लोगों के लिए अत्यन्त दुष्कर है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है।

अत: मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि गोरखपुर में यथाशीघ्र एक कैंसर अस्पताल की स्थापना करने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to set up an agriculture-based micro and small industries in Salempur parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): मेरा संसदीय क्षेत्र सलेमपुर उत्तर प्रदेश के पिछड़े लोकसभा क्षेत्रों में से एक है। मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों की एक मात्र आय का साधन कृषि है। महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र का देवरिया जिला एक समय चीनी की कटोरी कहा जाता था। यहाँ के किसान भरी मात्रा में गन्ने की खेती करते थे, जो आज चीनी मिलों के बंद हो जाने की वजह से गन्ने की खेती भी खत्म होने के कगार पर है। इसी तरह मेरे संसदीय क्षेत्र के भाटपार रानी विधानसभा में भारी मात्रा में हल्दी व अदरक की खेती करते हैं तथा सिकंदरपुर व बिल्थरा विधानसभा में भारी मात्रा में फूलों की खेती करते है। महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र में एक कृषि आधारित सूक्ष्म एवं लघु उधोग धंधों की स्थापना करने की आवश्यकता है। महोय मैं इस मान्य सदन के माध्यम से माननीय सूक्ष्म एंव लघु उधोग मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के भाटपार रानी, बिल्थरा व सिकन्दरपुर विधानसभा में कृषि आधारित सूक्ष्म एंव लघु उधोगों की स्थापना कराने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to review the conditions of availing benefits under various schemes

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): महोदय, केंद्र सरकार द्वारा उद्योगों के विकास हेतु विविध योजनाओ का नियोजन आयोजन किया जाता है। कई बार यह अनुभव आता है कि औधोगिक क्षेत्र को योजनाओं का लाभ देने में उदासीनता का अनुभव होता है। जिस में कई बार सरकार द्वारा योजना की घोषणा की जाती है और जब व्यक्ति उसका लाभ लेने जाता है तब कई छिपी हुई शर्ते ऐसी होती है जिसके कारण योजना कम सफल होती है। मसलन लघु उद्योगो को प्रोत्साहन देने हेतु गत दिनो में सरकार द्वारा MSME सैक्टर में 2 प्रतिशत ब्याज में राहत की योजना घोषित की गई परंतु जब लोग उसका लाभ लेने गए तब पता चला कि RBI द्वारा शर्त लगाई गई है कि जिस किसी ने अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ लिया न हो उसी को यह लाभ मिलेगा। मसलन कपड़ा मंत्रालय की टफ या राज्य सरकार की इंटरेस्ट सबसिडी का लाभ किसी ने लिया है तो उसे ऐसी राहत नहीं मिलेगी।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सूरत में लाखो यूनिट ऐसी है जिन्होंने टफ और राज्य सरकार की योजनाओ का लाभ ले कर अपना कारोबार शुरू किया था परंतु RBI की शर्तों के कारण वे इस लाभ से वंचित रहेंगे। मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि ऐसी शर्तो का संज्ञान लेकर अन्य योजनाओ में भी जो शर्ते योजनाओ को सफल होने में बाधक है उनका पुनः विचार करते हुए सुधार किया जाये।

(इति)

Re: Need to rename all the Central Institutes and Organisations in Allahabad, Uttar Pradesh after 'Prayagraj'

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): महोदय,हिन्दू मान्यता है कि सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद सबसे प्रथम यज्ञ प्रयागराज में ही किया था। इसी प्रथम यज्ञ के 'प्र' और 'याग" यज्ञ की संधि द्वारा प्रयाग नाम बना। ऋग्वेद और पुराणों में भी इस स्थान का उल्लेख प्रयाग के रूप में ही किया गया है तथा हिन्दी भाषा में प्रयाग का शाब्दिक अर्थ 'नदियों का संगम' भी है और यही पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम भी होता है।

इन्हीं सब पौराणिक और धार्मिक तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये उ0 प्र0 सरकार ने 16 अक्तूबर, 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया है, लेकिन इलाहाबाद रेल्वे स्टेशन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालया, आई० आई० आई० टी० इलाहाबाद सहित अन्य केन्द्रीय संस्थाओं का नाम अभी तक प्रयागराज नाम से नहीं किया गया है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है की वह इलाहाबाद नाम से संबंधी सभी केन्द्रीय संस्थाओं के नाम इलाहाबाद के स्थान पर प्रयागराज किए जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही करें।

(इति)

Re: Need to include Kokborok language of Tripura in the Eighth Schedule to the Constitution

श्री रेबती त्रीपुरा (त्रिपुरा पूर्व): मेरी सरकार से मांग है कि त्रिपुरा राज्य की राज्य भाषा (कॉकब्रॉक) को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 19 जनवरी, 1979 को त्रिपुरा राज्य सरकार ने (कॉकब्रॉक भाषा) को राज्य भाषा की स्वीकृति प्रदान की। त्रिपुरा के 9 सम्प्रदाय के लोग कॉकब्रॉक भाषा का प्रयोग करते हैं। त्रिपुरा के हर स्कूल एवं विश्वविद्यलाय में कॉकब्रॉक भाषा पढ़ाई जाती है। पूर्व में राज्य सरकार ने कॉकब्रॉक भाषा के विकास हेतु पहले से ही कॉकब्रॉक लैंगवेज, डायरेक्ट्रेट की स्थापना कर चुका है। आदिकाल एवं वर्तमान समय से बहुत सारे चलचित्र, किताबों को भी वर्तमान समय में कॉकब्रॉक लैंग्वेज में प्रकाशित किया जाता है। क्राक ब्राक भाषा में एक फिल्म को अर्न्तराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है। त्रिपुरा समेत पूरे देश में 18 लाख लोग इस क्राकबॉक भाषा का प्रयोग करते हैं। क्राकबॉक सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। पुरातनकाल में त्रिपुरा के 184 राजाओं ने राज्यभाषा के रूप में कॉकब्रॉक भाषा का प्रयोग किया था। कॉकब्रॉक भाषा के विकास हेतु राज्य सरकार ने प्रसिद्ध भाषा विद् पवित्र सरकार की अध्यक्षता में कॉकब्रॉक लैंग्वेज कमेटी का भी गठन किया था। परन्तु इन सब के बावजूद कॉकब्रॉक लैंगवेज को राष्ट्रीय भाषा की स्वीकृति नहीं मिली। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से मांग है कि कॉकब्रॉक भाषा के विकास एवं संरक्षण हेतु, संविधान संशोधन विधेयक लाकर कॉकब्रॉक भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

(इति)

Re: Compensation to family members of a Martyr of Indo-Pak War, 1965

SHRI SAPTAGIRI ULAKA (KORAPUT): Martyred Signalman No. 6298642 Jesudan Khosla is the only war hero for entire Odisha who was killed in battlefield of Indo-Pak war in1965. Despite repeated requests to Prime Minister and other Ministers, no action has been taken with regard to grievances of the Martyred family.

The Martyred family has been demanding financial compensation since 1965 from the Central Government and jobs to children of the Martyred family.

On behalf of the people of undivided Koraput district, I would like to urge upon the government to provide Martyred family, Homestead land and agriculture land, allotment of Petrol Pump, death compensation on battle ground, army group insurance as provided by army, concession in railway and air travel, education, health, social, economic facilities besides installing a statue of Maryred Jesudan Khosla with a park around it.

(ends)

Re: Need to extend the services of Uday Express upto Palakkad

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): It has been a long pending demand for the extension of 22665/22666 Uday Express upto Palakkad. Many people from Kerala living in Bengaluru wish to travel by this train. However, the connectivity between Coimbatore and Palakkad in late hours is pretty low. Therefore, although they would like to travel by this train, yet hesitate to make use of this train due to poor connectivity between Coimbatore and Palakkad in late hours. If this train is extended upto Palakkad, the rate of occupancy of this train will also increase as in the case of other trains running between Kerala and Bangalore. Even if this train is operated for 5 days to Palakkad and 1 day to Coimbatore for periodic maintenance, by terminating Tuesday service at Coimbatore, the patronage of this train will increase. The train is not running on Wednesday for maintenance now, which can be followed as such. Therefore, Hon'ble Minister is requested to extend the said train upto Palakkad.

(ends)

Re: Improvement of sports infrastructure in the country

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANNIYAKUMARI): In India, the standard of sports infrastructure is not at a satisfactory level for a number of reasons. The following recommendations may be implemented for the development of sports infrastructure in the country and particularly in Kanyakumari District.

(1) To arrange dedicated land bank for setting up of sports infrastructure.

(2) To adopt PPP model in which the government will provide institutional and financial support for building of infrastructure and private sector will manage and maintain its operations.

(3) To use these facilities for multiple purposes, such as organizing exhibitions, conferences or for setting up of sports academies.

It is a pity that majority of the children going to schools in India do not get the opportunity to take part in sports due to the lack of infrastructure or even open spaces. I urge upon the government to solve this problem permanently.

(ends)

(PP 332-334)

Re: Relaying of sewage and water pipelines in North Chennai

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): North Chennai is one of the oldest (more than 150 years) and most historic parts of the city. The infrastructure of sewage and water lines have got damaged over time. Sewage water getting mixed with potable drinking water has become a common problem in few localities of North Chennai, making public of these localities susceptible to waterborne infections. The situation has put many residents in a tough spot, as they are now buying water for drinking and other purposes. People belonging to lower economic groups are using the water, as they cannot afford to buy canned water. Multiple complaints have been made to the local authorities in this regard but the issues have not been fully solved as yet.

As it involves huge costs, I request Centre and State Governments to provide fund for relaying of sewage and water lines in North Chennai or through any Central Government Scheme to help the poor people of my Parliamentary Constituency.

(ends)

Re: Need to extend services of Akola-Purna (Train No. 57581/82), Akola-Parli-Baijnath (Train No. 57539/40) and Akola - Purna (Train No. 51583/84) upto Shegaon Railway Station in Buldhana parliamentary constituency, Maharashtra

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा (महाराष्ट्र) के अंतर्गत शेगांव सद्गुरु श्री संत गजानन महाराज की पावन स्थली है। यहाँ स्थित शेगांव रेलवे स्टेशन शेगांव, को 'अ' दर्जा प्राप्त है। यहाँ पर प्रतिदिन एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओ का आवागमन होता है। रेलवे को भी इस स्टेशन से यात्री टिकट से 15 करोड़ रु0 प्रतिवर्ष प्राप्त होते है।

अकोला-पूर्णा (57581-57582), अकोला-परली वैजनाथ (57539-57540) और अकोला-पूर्णा (51583-51584) पैसेंजर रेलगाडियाँ अकोला स्टेशन पर काफी समय तक खड़ी रहती है। इन पैसेंजर रेलगाड़ियों को शेगांव तक चलाये जाने से न केवल श्रद्धालुओ को आवागमन में सुविधा होगी, बल्कि रेलवे की आय में वृद्धि होगी।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त पैसेंजर रेलगाड़ियां, जो अकोला रेलवे स्टेशन पर काफी समय तक खड़ी रहती है, को शेगांव तक चलाये जाने हेतु निर्देशित किया जाये।

(इति)

Re: Need to include 'Thathera' caste of Bihar in the list of most backward castes

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): बिहार राज्य में ठठेरा जाति की आबादी लगभग 25 लाख है। ठठेरा जाति के लोगों की स्थिति काफी दयनीय है। वे शैक्षणिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में काफी पीछे हैं। बाल-बच्चों के साथ मजदूरी करके अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हैं। ठठेरा जाति आदिवासी की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर हैं। ठठेरा लोग शिल्पकार भी कहलाते हैं और यह जाति बर्तन की फेरी कर भी अपना जीवन बसर कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ठठेरा जाति के बच्चों के हाथों में कलम के बजाए वे गली-गली घूमकर लोहा-टीना खरीदने का काम करते हैं। इन जातियों के लोगों के पास घर या मकान नभी नहीं हैं न खेतीबाड़ी के लिए जमीन। वे खानाबदोश की जिन्दगी जी रहे हैं।

प्राचीन काल में धातु के विभिन्न प्रकार के बर्तनों को बनाने एवं व्यापार करने वाले ठठेरा कहलाये ठठेरा जाति के लोग अन्य प्रदेशों में दूसरे नामों जैसे कसेरा. कंशारा. शाह, वर्मा. सिंह, राजपूत, चन्द्रवंशी या ध्यारण भी कहलाये हैं। वैसे तो ठठेरा जाति पिछड़ी जाति की सूची में क्रमबद्ध है। किन्तु अभी भी ठठेरा जाति समुदाय की आर्थिक एवं शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति अति दयनीय है। समाज में इस समुदाय को एक समान लाने के लिए ठठेरा जाति संघ अपने समुदाय का अति पिछड़ी जाति के श्रेणी में लाना चाहता है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस विषय में सभी प्रकार की साक्षयों एवं शोध के पश्चात ठठेरा समुदाय की अति पिछड़ी जाति के श्रेणी में लाने की अनुमति दे। इससे उक्त समुदाय को बराबरी के लिए सरकारी सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

(इति)

Re: Revision of coal royalty rate

SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): Odisha accounts for 33% of coal produced in India and 50% coal production in Odisha is in Talcher area. Though several years have passed but royalty on coal has not been revised and office of coal company at Talcher is not as yet functional.

(ends)

Re: Need to undertake construction of various roads in Medak Parliamentary Constituency, Telangana

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): I would like to draw the attention of the House regarding sanction of Funds for construction of following roads under CRF (Central Road Fund) in my Medak Parliamentary Constituency in Telangana State :-

(1) Mundrai Nagurajpally Road from Km 0/0 to 18/6 in Nanganoor Mandal (length - 18.6 km , cost Rs. 3400.00 lakhs);

(2) Machapur — Nangnanoor road from Km 13/8-17/0 in Nanganoor Mandal (length - 3.2 km, cost Rs. 580.00 lakhs);

(3) AR Sub Headquarters to Karimnagar District Border road 10/2- 16/0 in Chinnakoduru Mandal (length 5.8 km, cost Rs. 1100.00 lakhs);

(4) Ibrahimpur to Dubbak road from Km 0/0 to 6/2 in Narayanraopet Mandal (length 6.2 km cost Rs. 1200.00 lakhs);

(5) Bussapur to Thimmayapally road from Km 20/8 to 30/0 in Chinnakoduru mandal (length of 9.2 km cost Rs. 1700.00 lakhs);

(6) Dubbak to Mustabad road via Rajakkapet from Km 0/0 to 8/380 in Siddipet Rural Mandal (length 5.6 km cost Rs. 1100.00 lakhs);

(7) Dubbak to Mustabad road via Rajakkapet from Km 0/0 to 8/380 in Dubbak mandal (length 8.0 km cost Rs. 850.00 lakhs) and

(8) Widening and strengthening of Siddipet R&B road via Rampur, Chelnar, Nandagokul, Naskal, Nizampet link road in Nizampet Mandal, (length 18.3 km cost Rs. 290.00 lakhs).

I request the Hon'ble Minister of Road Transport & Highways, through the Chair, to kindly do the needful.

(ends)

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS – Contd.

1408 hours

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Hon. Speaker Sir, I rise to dwell on the President's Address. As we know, in our Parliamentary democracy, President's Address is always recognised as a solemn occasion. The genesis of this exercise goes back to 1921. In the aftermath of Independence, the provisional Parliament, in the year 1950, lasted for two years, two months and 22 days. The number of Members were 313 and discussion was held for three days following the President's Address.

We know that President's Address is regarded as a statement of policy whereby it contains the activities and achievements of the Government for the previous year. It also incorporates both internal and international policies of the Government. Everything is right but I fail to subscribe to the views enshrined in this President's Address. And that, I will try to elucidate in my following speech. (1410/NKL/CS)

Sir, yesterday, Dr. Satya Pal Singh*ji* was referring to Swami Vivekananda. His name was Narendranath Datta. He was trying to juxtapose the then Swami Vivekananda*ji*, who was a Saint and a Demigod, in our view, with the present Prime Minister of our country, Shri Narendra Modi*ji.* Anybody can compare one with anybody else; there is no issue of it. But there is a yawning gap between Shri Narendranath Datta and Shri Narendra Modi. If one is regarded as *'Yogi'*, another is regarded as *… (Not recorded)* …(*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, यह अनपार्लियामेन्टरी शब्द है।…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I have not referred to anybody's name. …(*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): You can say anything in the House. …(*Interruptions*) Why are you protesting? …(*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, this is unparliamentary. …(*Interruptions*) Sir, this is not correct. …(*Interruptions*) The Leader of the Congress Party is speaking. …(*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I have not said any unparliamentary word. …(*Interruptions*) No unparliamentary word has been expressed by me. I am challenging you. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : इस शब्द को निकाल दीजिएगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भी बड़े दल के फ्लोर नेता हैं। कोई भी ऐसा शब्द, जिसे एक्स्पंज करना पड़े, यह मुझे भी उचित नहीं लगता है। इसलिए मर्यादित रूप से बोलें, सदन आपका है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, अगर आपको यह लगे कि मैंने कोई अनपार्लियामेन्टरी वर्ड इस्तेमाल किया है, तो आप जो चाहे वह कर सकते हैं, लेकिन मेरे बोलने का मकसद यह है कि we are living in a material word. Swami Vivekananda was living in a spiritual world. Whosoever is living in a spiritual world, he is regarded as a Saint, that is, *'Yogi'.* Whosoever is living in a material world, he is called a *'Bhogi'.* There is nothing wrong in it. …(*Interruptions*) We all are *'Bhogis'* because we are living in a material world. Every one of us is a '*Bhogi'.* We all are '*Bhogis'.* …(*Interruptions*) Whoever lives in a material world is considered as a '*Bhogi'.* …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट रुकिए। महताब जी कुछ कहना चाहते हैं।

…(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I am not yielding. …(*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, insinuation should not be allowed in this House. …(*Interruptions*) One is Parliamentary and the other is unparliamentary. But nobody should insinuate another person in this House who is also a Member of this House. …(*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, he is not yielding. How can he speak? …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सभी सदस्य अपनी राय रख सकते हैं, यह सदन सबका है।

…(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, यह पॉइंट ऑफ ऑर्डर का सवाल है।…(व्यवधान) जो मिस्टर महताब ने कहा है, वह पॉइंट ऑफ ऑर्डर का सवाल है।…(व्यवधान) आप *… (Not recorded)* हो सकते हैं।…(व्यवधान) हम डिसाइड करेंगे।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं बैठ जाता हूँ।…(व्यवधान)

(1415/KSP/RV)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, he is our leader. If they disturb him like this, we will also disturb the Prime Minister's speech. …(*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, मेरा पॉइंट-ऑफ-ऑर्डर है।…(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय……(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप नए-नए आए हैं, आप बैठिए। आपको इजाजत नहीं दी है। अधीर रंजन जी।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आप रूलिंग दे सकते हैं, पर मेरे कहने का मतलब है, the person who preaches for the spiritual world, he is called *yogi* and a person who preaches for the material world, he is called *Bhogi*. …(*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, इन्हें पता नहीं है।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): हाँ, हाँ, तुम्हें ज्यादा मालूम है।…(व्यवधान) सर, जो समय इसमें निकल गया, आप उसकी बाद में मुझे भरपाई कर दीजिएगा।…(व्यवधान) Sir, according to Swami Vivekananda:

> "Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now."

सर, मैं, स्वामी विवेकानंद को कोट करते हुए, सत्यपाल जी से कहना चाहता हूं, वे कल 'स्वर्गादपि' की बात कर रहे थे।…(व्यवधान) वे कल 'स्वर्गादपि …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)' की बात कर रहे थे।…(व्यवधान)

सर, ये विवेकानन्द जी की बात है।…(व्यवधान) विवेकानन्द जी ने क्या कहा था, क्या आप जानते हैं?…(व्यवधान) Swami Vivekananda said:

> "Our own motherland is a junction of two great systems, Hinduism and Islam – Vedanta brain and Islam body is the only hope for India."

It was not told by me. It was stated by Swami Vivekananda.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, ये क्या बात कर रहे हैं?...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): विवेकानन्द ने कहा कि our motherland is a junction of two great systems. ...(*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, ये स्वामी विवेकानन्द को गलत क्वोट कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): विवेकानन्द जी ने यह भी कहा था कि "every soul is potentially divine. Our goal is to manifest the divinity among human beings", not the devilish nature. इसलिए नकली हिन्दू मत बनो, असली हिन्दू बनो हमारे जैसा।...(व्यवधान) नकली हिन्दू बनने की कोशिश मत करो।...(व्यवधान)

(1420/MY/KKD)

You are pseudo nationalists; you are pseudo humanists; you are pseudo Hindus ...(*Interruptions*) आज आपको बचने के लिए महात्मा गांधी जी की जरुरत पड़ती है। आज बात-बात में पूज्य बापू, पूज्य बापू करके आपने सारे प्रेसिडेन्शियल ऐड्रेस को भर दिया है। आपने पूज्य बापू, पूज्य बापू क्यों किया है? आप पूज्य बापू के साथ यह नहीं कह सकते हैं कि पूज्य बापू का जो हत्यारा है, हिन्दुस्तान में उनकी पूजा नहीं की जाएगी। आप यह तो नहीं कर सकते हैं! क्या आपने ऐसा कभी कहा? ...(व्यवधान)

आज तक हमारे हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री जी ने कभी कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष हिन्दुस्तान चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं कहा। मैं चैलेंज करता हूं।...(व्यवधान) मैं चैलेंज करता हूं कि उन्होंने आज तक ऐसा नहीं कहा।...(व्यवधान) आज तक हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसी वक्त नहीं कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष हिन्दुस्तान चाहते हैं।...(व्यवधान) मैं इसको चैलेंज करता हूं। आपने पूज्य बापू कह कर अच्छा किया और हम इससे खुश हैं। ...(व्यवधान) लेकिन आप पूज्य बापू पर सर्जिकल स्ट्राइक मत करना। आप उनके ऊपर आइडियोलॉजिकल स्ट्राइक करते हैं।...(व्यवधान) महात्मा गांधी जी पर आइडियोलॉजिकल स्ट्राइक करते हुए, आप यह कहते हैं कि गांधी जी ने ऐसा कहा-

> "Hindus and Sikhs of Pakistan, who do not wish to live there and come to India, it is the duty of the Government of India to ensure a normal life for them. "

यह सही कहा, लेकिन आपने क्या किया, आप जानते हैं। इसको cherry picking कहते हैं, इसको pixelating कहते हैं। जहां पसंद हुआ, वहां उठा कर लाया। आपने गांधी जी की असली बात का कभी जिक्र भी नहीं किया और आप लोग जानना भी नहीं चाहते हैं। यही आपकी समस्या है। आप सुन लीजिए कि गांधी जी ने क्या कहा था। हमारे जयशंकर जी हैं, काफी एरुडाइट पर्सन है, लर्नेड पर्सन है। In the year, 1947, on 10th July, Gandhiji said:

> "If people flee their homes in Sindh and other places out of fear and come here, shall we turn them away?"

ऐसा गांधी जी बोल रहे हैं। He further says:

> "If we do so with that face, shall we call ourselves Indians? How can we chant the slogan 'Jai-Hind'? Welcome them, saying, this too is your country just as that is your country. This is how we should deal with them. If nationalist Muslims are also forced to leave Pakistan and come here, then they too will live here as Hindustanis. We all have the same standing. If this cannot be, then Hindustan cannot come into being."

अभी आप लोगों की गांधी जी के बारे में जो सोच है, उस पर आप लोग आइडियोलॉजिकल सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। आप लोग आइडियोलॉजिक्ली सर्जरी कर रहे हैं। आप लोग गांधी जी का आइडियोलॉजिक्ली सर्जरी मत किया कीजिए, आप फंस जाओगे। यह नहीं होगा।

कल आप कर्नाटक में कह रहे हैं *… (Not recorded)* आज यहां कहते हैं कि वह पूज्य बापू है। यह क्या *… (Not recorded)* कर रहे हैं? …(व्यवधान) *… (Not recorded)*…(व्यवधान) आज हिन्दुस्तान के आम लोग क्या कहते हैं? आपने जरूर संविधान पढ़ा होगा। संविधान में क्या लिखा है:

"WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR, AND DEMOCRATIC REPUBLIC…"

We never said: 'We the Hindus of India…' We never said: "We the Muslims of India having resolved to constitute India.'

मैंने क्या कहा:

"WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST, SECULAR, AND DEMOCRATIC REPUBLIC…"

Do you know what is the true spirit of our Constitution? The true spirit of our Constitution is that each and every one of our countrymen should feel that this country is his own.

(1425/CP/RP)

यह जो हिंदुस्तान की ट्रू स्पिरिट है, इसको आप खत्म करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के साथ आप यह सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में कोई और बात नहीं होती है। हमारी रोजी-रोटी की बात नहीं होती, उद्योग की बात नहीं होती और शिक्षा की बात नहीं होती। सत्ता पक्ष के नेताओं की केवल तीन बातें होती हैं, एक - मुसलमान, दो - पाकिस्तान, तीन - इमरान। ये तीन बातें हैं, और कुछ बात नहीं है। लगता है कि हमारे देश को किसी और चीज की जरूरत नहीं है। इन तीन बातों में आप सिमट गए हैं। आज क्या हो रहा है? आजादी के बाद हिंदुस्तान में बहुत सारी लड़ाइयां

हुईं, प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, कभी नौकरी के लिए, कभी उद्योग के लिए, कभी कोई वंचना के लिए, लेकिन this is the first time we are witnessing that people are fighting to save their Constitution. This is a new awakening in our country. हजारों-लाखों की तादाद में लोग निकल रहे हैं। किसलिए? संविधान को बचाने के लिए, किससे, आप लोगों से। आप लोगों से संविधान बचाने के लिए आज जंग छेड़ी है। उसको आप लोग क्या कहते हैं? यह टेररिस्ट है, पाकिस्तान की मदद है, वगैरह-वगैरह कह रहे हैं। आप खुद अभी क्या कर रहे हैं? आप खुद रणछोर की भूमिका का पालन कर रहे हैं। कैसे? कल यह कहा कि एनआरसी अभी नहीं लागू होगा। क्यों, इस सदन के अंदर आपने क्या कहा था? सदन के अंदर आपने खुद कहा था कि एनआरसी सीएबी के बाद चालू होगा। अमित शाह जी ने 23 अप्रैल, 2019 में कहा,

> "Understand the chronology, first refugees will be given citizenship and then the All-India NRC will be created."

मैंने नहीं कहा, अमित शाह जी ने कहा। अमित शाह जी ने 1 मई, 2019 में क्या कहा?

> "First, we will pass the Citizenship Amendment Bill and ensure that all the refugees from the neighbouring nations get the Indian citizenship. After that, NRC will be made and we will detect and deport every infiltrator from our motherland."

सारे घुसपैठियों को निकाला जाएगा। अमित शाह 20 नवंबर, 2019 को राज्य सभा में क्या कहते हैं?

> "The Assam exercise was carried out under a Supreme Court order. NRC will be carried out across the country, will be done in Assam again at the time, no one from any religion should be worried." He said" "Adding that decision is a just process."

कल निशिकांत दुबे जी भी यही कह रहे थे।

> हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने 20 जून, 2019 को ज्वाइंट सैशन में में क्या कहा?
> "My government has decided to implement the process of National Register of Citizens on priority basis in areas affected by infiltration."

रविशंकर प्रसाद जी ने 29 दिसंबर, 2019 में क्या कहा? On the question of NPR data being used for NRC, he said: "Some may be used or some may not be used." यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपके मंत्री ने कहा। हमारे हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री क्या कह रहे हैं? पीएम मोदी ने 22 दिसंबर, 2019 को रामलीला ग्राउंड में क्या कहा?

> "NRC has neither been discussed in the Parliament nor any rules regarding it have been framed. There are no talks about it at all. It was only when the Supreme Court directed us to implement it in Assam, we had to do it there."

अमित शाह जी पलटी खाकर क्या कह रहे हैं?

> "There is no need to debate this (pan-India NRC) as there is no discussion on it right now. PM Modi was right and there is no discussion on it yet either in the Cabinet or Parliament."

हम किसकी बात पर भरोसा करें, आप खुद कह दीजिए। हम प्रधान मंत्री के ऊपर भरोसा करें या अमित शाह जी के ऊपर भरोसा करें या रविशंकर जी के ऊपर भरोसा करें, आप खुद कह दें। आपका जो निर्णय होगा, वह हम मान लेंगे। आप खुद नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए। आपने सोचा था कि एक बार सीएए, सीएबी लागू कर दें, एनआरसी की बात कर दें, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे, सारे मुसलमान अलग-थलग हो जाएंगे और हमारे वोट बैंक में तुरंत इजाफा होने लगेगा। आपकी जो कल्पना थी, It was a sinister design. It has been foiled by the common people. इनके खिलाफ सारे हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग, हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग, सबने इकट्ठा होकर आंदोलन छेड़ दिया।

(1430/NK/RCP)

इसका नतीजा क्या निकला? कल आप कह रहे थे कि एनआरसी चालू नहीं होगा, एनपीआर में किसी को डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, आप कह रहे हैं। इससे क्या साबित होता है? इसमें एक चीज साबित होती है कि हमारे हिन्दुस्तान के आम लोगों के आंदोलन के नतीजे से अब सरकार पीछे हटने लगी है। हिन्दुस्तान के कंस्टीट्यूशन की यह सबसे बड़ी जीत है, हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जीत है। आपको चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ा, क्योंकि मामला गड़बड़ हो रहा है। आप हड़बड़ी में गड़बड़ कर दिया, इसे कैसे संभाले, इसकी आपको चिंता है? आप हिन्दुस्तान को कमजोर नहीं कर सकते। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसमें हर मजहब के लोग हैं, उनका क्या कहना है?

> "लालकिले से आई आवाज, सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज। "

यही उनका स्लोगन है।

"आजादी की शाम कभी न होने देंगे,
हमारा शहीदों की कुर्बानी कभी न बर्बाद होने देंगे,
जब तक रहे एक बूंद भी लहू की,
भारत माता के आंचल को नीलाम न होने देंगे,

इनका नारा है,

आजादी की शाम न होने देंगे,
शहीदों की कुर्बानी को बदनाम न होने देंगे।
जब तक रहे एक बूंद भी लहू की भारत माँ के आंचल को नीलाम न होने देंगे।
सलामी दिया करो, हमारे तिरंगे को जिसमें हमारी शान है।
इसके सर को उँचा रखना जब तक दिल में जान है।"

यह कौन कहता है? ये लोग कहते हैं। आप इन लोगों के खिलाफ में हिन्दुस्तान में फैला रहे हैं कि ये देश विरोधी काम कर रहे हैं, देशद्रोही काम कर रहे हैं। हम सभी ने मिल कर इस देश को बनाया है। आप जानते हैं इतिहास में क्या लिखा है? आजादी के समय दो गांधी थे। एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और एक खान अब्दुल गप्फार खान सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान की 95 वर्ष की आयु थी, ब्रिटिश लोगों ने उन्हें 45 वर्ष कैदखाना में रख दिया था। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। आजादी की लड़ाई में एक तरफ जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद। हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में एक तरफ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे। उनके साथ आबिद हसन खान, शाहनवाज खान थे, यह हिन्दुस्तान आप नहीं मांगते हैं। ऐसा हिन्दुस्तान आप नहीं चाहते? हिन्दुस्तान के लिए सबसे पहले पूर्ण स्वराज का नारा किसने लगाया था, आप जानते हैं। मौलवी हसरत मोहानी ने सन 1921 लगाया था। आज हिन्दुस्तान में हम लोग 'जय हिन्द' कहते हैं। 'जय हिन्द' नारा किसने दिया था? आबिद हसन सफरानी ने नेताजी के साथ लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने यह नारा तय किया, 'जय हिन्द'। सोरायब तैयबजी राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था, गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम किसने दिया था, यूसूफ मेहराली जी ने दिया था। हम सभी ने मिल कर हिन्दुस्तान बनाया है। आज हम सब आपस में क्यों लड़ाई करने जा रहे हैं? हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई के लिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेन्डेंस सिपाही बगावत में उनतीस हजार मुसलमानों को दिल्ली की सड़क पर ब्रिटिशों ने कुचल दिया था।

(1435/SK/SMN)

35,000 ने सहायता की, यह हिस्ट्री है। क्या हमारा देश इस तरह से पालन नहीं कर सकता है, जहां रविन्द्र नाथ ठाकुर भी हों और काज़ी नज़रुल भी हों, जहां रवि शंकर हों और साथ में सरदार अमजद अली भी हों, सितार और सरोद की धुन साथ हो, क्या हम यह नहीं चाहते हैं? क्या हम ऐसा हिन्दुस्तान नहीं चाहते, जहां सत्येन्द्र बोस हो और डॉ. कलाम हों? हम ऐसा हिन्दुस्तान इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वह हिन्दू है और यह मुसलमान है, जबकि यह देश सबने बनाया है। Our Indian

civilisational enterprise has never indulged in any singular thought. We have never indulged in any kind of singular idea. हमारे चार वेद हैं, दो एपिक हैं, 18 उपनिषद् हैं, इसका मतलब है कि हमारा कॉस्टयूम अलग है, विज़न अलग है, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, We are all linked to the realm of plurality. प्लुरेलिटी देश की सबसे बड़ी धड़कन है, इसे बचाकर रखना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने वर्ल्ड बैंक में ईज़ आफ डुइंग बैंकिंग रैंकिंग रखी, रिजाल्व इनसॉल्वेंसी की रैंकिंग रखी, ग्लोबल इनोवेशन की रैंकिंग रखी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, Under hon. PM Modi, India has fared terribly on other important global rankings. इसमें क्या है, Democracy Index had dropped by ten places to the 51st position in January, 2020. हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स घट रहा है। ग्लोबल जैंडर इंडेक्स 108 पहुंच गया है, पहले 112 था। 180 देशों में एन्वायर्नमेंट परफार्मेंस में 177वां स्थान है। प्रैस फीडम इंडेक्स 140 हो गया है। 117 देशों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102वां स्थान है। आप कहते हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश हमसे आगे हो गया है, 88 पर आ गया है। पाकिस्तान हमसे आगे है, नेपाल हमसे आगे है और हम ग्लोबल हंगर इंडैस में पीछे रह गए। In World Happiness Index, India fell by seven positions in 2019 to 140 from 133 in 2018. Global Competitiveness Index slipped ten places between 2018 and 2019 and now, is at the rank of 68. Global Peace Index slipped five ranks to 140th rank out 163 countries. In World Passport Index, it was 84th rank out of 199 countries. Furthermore, the Ease of Doing Business Report only focusses on business in two Indian cities, that is Delhi and Mumbai. The Report also does not cover informal sector and micro, small and medium enterprises which cover 95 per cent of the industrial units in our country.

महोदय, इस सरकार ने कश्मीर से 370 अनुच्छेद हटाया, 35ए भी हटाया, यह कहकर कि कश्मीर की तरक्की होगी, हिंदुस्तान में आतंकवाद नहीं रहेगा। अब छ: महीने हो गए हैं, हमारे साथी सुरेश जी ने यह मुद्दा उठाया था। अगर हम छ: महीने के बाद आकलन करें तो क्या देखते हैं। According to official data, Kashmir witnessed 1999 stone-pelting incidents in 2019 as compared to 1458 in 2018 and 1412 in 2017. According to a recent estimate of multi-agency centre headed by Intelligence Bureau, 400 militants are active in the valley increasing the possibility of heightened insurgency activities even in the border districts of Rajouri, Poonch and Kishtwar.

(1440/MK/MMN)

You are trying to conduct proactive measures to regain the trust of the people and normalise the situation even as these actions have dented India's global image as a liberal democracy. जयशंकर जी इसको अच्छी तरह जानते हैं। आप यह

कहते आए हैं कि कश्मीर हमारा आतंरिक मामला है। क्या आज यह आंतरिक मामला रह गया है? मैं फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं। नहीं, यह इंटरनेशनल मामला बन गया है। आपने वहां तीन बारात भेजा था। आप वहां तीनों बारात ले गए थे। एक मिडिल मैन इसके जरिए यूरोप से एक बारात लाए थे। उसके बाद हिन्दुस्तान में रहते हुए, सारे एम्बेस्डर की एक बारात गई। तीसरी बार, आपके सारे मंत्री वहां जा रहे हैं। क्या हमारे लिए कश्मीर एक्सेसेबल नहीं है, हमारे लिए कश्मीर अछूता है, क्या हम वहां जा नहीं पाएंगे, आप लोग जा नहीं पाएंगे, क्या आपको और हमको, सबको इच्छा नहीं होती है, कश्मीर कैसा है, उसको देखकर आएं? आपने हमारे तीन-तीन चीफ मिनिस्टर को जेल की सलाखों के पीछे रख दिया। उनमें से एक 84 साल की उम्र के हैं। आपको क्या लगता है? उसी दिन इस सदन में जब हमने सवाल पूछा कि फारूख अब्दुल्ला साहब कहां हैं? अमित शाह जी कहते हैं की ठीक हैं। क्या हम कान में बन्दूक लगाकर कहें कि चलो निकल चलो। हम तो नहीं कह सकते हैं। हमको कान में बन्दूक लगाना पड़ेगा। हम यह नहीं कर सकते हैं। क्या आप लाए हैं यहां? छ: महीने हो गए। आपने लाखों की तादाद में वहां फौजी तैनात किए हैं। आप तो 56 इंच वाले हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर आप क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं कश्मीर के फारूख अब्दुल्ला से, उनके बेटे और हमारे एक फार्मर चीफ मिनिस्टर हैं, आप लोग इनसे क्यों डरते हैं? क्या आपके पास मोरल पावर नहीं है? आप, हम सब कश्मीर जाना चाहते हैं। अभी कश्मीर हमारे लिए इनएक्सेसेबल हो गया है। …(व्यवधान) हम जाना चाहते हैं। यह हमारा अधिकार है। हम क्यों नहीं जा पाते हैं? चलो सब चलो। कश्मीर हमारा अंग है। आपने कश्मीर को अंतराष्ट्रीय मुद्दा बनाया, हमने नहीं बनाया। जब हमने यहां पर पूछा था कि हमारा अफगानिस्तान से कोई बार्डर नहीं है तो हमारे गृह मंत्री जी कहते थे कि आपको मालूम नहीं पीओके तो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा हां यह तो सही है। लेकिन, आप पोओके को कब लाओगे? अभी चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। इकॉनोमिक कोरिडोर बनने के बाद जो गिलगित बाल्टिस्तान है, उसमें इकॉनोमिक कोरिडोर बन रहा है। यह ग्वादर पोर्ट तक जाएगा। हमारे हिन्दुस्तान की ईस्टर्न फ्लैंक की सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। क्या आप कह सकेंगे कि पीओके में चीन हस्तक्षेप न करे? क्या आपने एक लब्ज भी कहा? क्या आपने एक बार कहा कि चीन-पाकिस्तान कॉरिडोर नहीं बनने देंगे? आपके प्रधान मंत्री जी कहते हैं सात से दस दिन का वक्त हमें चाहिए, हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे।…(व्यवधान) हमारी पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी ने वर्ष 1971 में 3 दिसम्बर से 16 दिसम्बर, 13 दिन में बंग्लादेश छीन कर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया, बहुत पहले तोड़ दिया।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपको एक बात क्लीयर कर दूं कि इनके प्रधान मंत्री नहीं हैं, हम सबके प्रधान मंत्री हैं, देश के प्रधान मंत्री है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): जी सर, सबके प्रधान मंत्री है। मैं प्रधान मंत्री जी की बहुत इज्जत करता हूं। …(व्यवधान) मैं जयशंकर जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि कश्मीर आंतरिक मामला है, कश्मीर इंटनेशनल मामला नहीं है? आपने चीन-पाकिस्तान कॉरिडोर के बारे में क्या किया, आपने चीन-म्यांमार कॉरिडोर में क्या किया? क्यौकप्यू सी-पोर्ट म्यांमार में बन रहा है। बे ऑफ बंगाल में हमारे लिए खतरा पैदा हो रहा है। नेपाल के साथ चीन बेल्ट

एंड रोड इनीशिएटिव हंस-हंस के कर लिया। अब नेपाल भी खतरे में आ रहा है। चीन का नेपाल के साथ कॉरिडोर, पाकिस्तान के साथ कॉरिडोर, म्यांमार के साथ कॉरिडोर, आपने इसके बारे में कुछ बताया, चर्चा में कुछ आया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कुछ आया? हमारे ईस्टर्न फ्लैंक्स और वेस्टर्न फ्लैंक्स दोनों खतरे में पड़ गए हैं। पीओके में जब चीन घुसने लगेगा PoK has come under the possession of Pakistan and it will be treated as a *fait accompli.*

(1445/YSH/VR)

आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप पीओके में कुछ करना चाहेंगे तो आपको चीन से टकराना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बताइए, क्या आप पाकिस्तान और चीन से एक साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो पीओके पर कब्जा क्यों नहीं करते हैं? हमें चीफ ऑफ आर्मी कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट मंजूरी दे तो हम पीओके पर कब्जा कर लेंगे। सन् 1994 में हमने सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पारित किया था कि पीओके को कब्जे में लाना चाहिए। आज सरकार की तरफ से दूसरा रिजोल्यूशन लाया जाए कि चीफ ऑफ आर्मी पार्लियामेंट की तरफ से पीओके को कब्जे में लेकर आए। हम यह चाहते हैं। क्या आपमें हिम्मत है? आप दिन-रात सिर्फ पाकिस्तान-पाकिस्तान करते हैं। पाकिस्तान है क्या, हमारी बीएसएफ पाकिस्तान को हरा सकती है। इसके लिए आर्मी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप सिर्फ पाकिस्तान-पाकिस्तान करते हैं। You are roaring like a lion against Pakistan but you are whimpering like a pygmy against China. This is the tragedy of our country. युनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने इस मुद्दे को दो बार उठाया है। चाहे क्लोज़ डोर में उठा हो, लेकिन उठा तो है। यूरोपियन पार्लियामेंट रिजोल्यूशन ला रही है। पूरी दुनिया की हमारे खिलाफ कश्मीर और सीएए को लेकर आवाज बुलंद हो रही है। क्या इससे हमारा स्टेटस नहीं घट रहा है? क्या इससे हिन्दुस्तान का स्टेटस कमजोर नहीं होता है? इसके चलते ही प्रधान मंत्री जी दवोस में नहीं गए। हमारे जो भी डिप्लोमेटिक असेट हैं, उनके मालिक जयशंकर जी हैं। आप डिप्लोमेटिक असेट का इस्तेमाल पूरी दुनिया को समझाने के लिए करते हैं कि कश्मीर हमारा आंतरिक मुद्दा है, सीएए हमारा आंतरिक मुद्दा है। आपको और कोई काम नहीं है। आप अफगान पीस प्रोसेस में भाग नहीं ले सकते हैं। आप इंडियन ओशियन रीजन में जो इंटरनल समस्या है, उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। आपने पूरी फोर्स को तैनात कर दिया है। आपने पूरी डिप्लोमेटिक असेट लगा दी सारी दुनिया को यह समझाने के लिए कि कश्मीर हमारा है, हमारा है, हमारा है, सीएए हमारा आंतरिक मसला है। क्यों हम आपको इससे ज्यादा अग्रेसिव नहीं देख पाते है। हमारे ऊपर दोहरा झटका क्या है? दोहरा झटका यह है कि कश्मीर पीओके चीन के साथ जाना चाहता है और हम उस पर कब्जा करना चाहते हैं। नैतिकता के आधार पर चीन आगे निकल चुका है और हिन्दुस्तान पीछे रह गया है। यह हमारे लिए दोहरा झटका है। चाहे इसे आप स्वीकार करें या न करें। यह आपकी राय है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I would ask the hon. Minister to take a separate class for the hon. Member and inform him the actual position

because the manner in which disinformation is being created is not good. *....(Interruptions)*

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): We do not need an agency like you of BJP party. Better you should sit there. *....(Interruptions)*

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): We will decide where we should sit. ....(Interruptions)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): They cannot digest the truth. That is why he is talking like that. *....(Interruptions)*

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Sir, it is an unnecessary behaviour. It is our business. ....(Interruptions)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आज हालात यह हो गए हैं कि New Delhi is now resembling a provincial capital today. Don't take me wrong. सर, हमारा स्टेटस गिर गया है। सर, बीजेपी का क्या मकसद है? ये बोलते हैं कि हम न्यू इंडिया बनाएंगे। न्यू इंडिया बनाने का क्या मतलब होता है? आपने कौन सा न्यू इंडिया बनाया है? हम जैसा न्यू इंडिया देखते हैं, उसमें शुरू में कोशिश करते हैं कि हमारे जो हिन्दुस्तान के नेता है या हिन्दुस्तान के जो ड्रीमर्स हैं, उनको शामिल किया जाए, जिसको हम को-ऑप्शनल कहते हैं। You are practicing co-optional politics. आपने क्या किया? आप नेहरू जी को लेकर आए, आप महात्मा जी को लेकर आए और आपने बहुत सारे महापुरुषों का नाम भी उठाया है। यह हमें बहुत अच्छा लगा।

(1450/RPS/SAN)

यह आपकी मजबूरी है। In the pantheon of dreamers, you have not included the names of other dreamers of our country, including Swami Vivekananda, Netaji Subhash Chandra Bose, Indira Gandhi, Rahul Gandhi and even Atal Bihari Vajpayeeji. …(*Interruptions*) राजीव गांधी, ठीक कर लिया। …(व्यवधान) ठीक कर लिया है। ठीक है। …(व्यवधान) यह कोई गलती नहीं है। …(व्यवधान) इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा हो सकता है। …(व्यवधान) हो सकता है। …(व्यवधान) इंदिरा जी, राजीव जी, बोल दिया। …(व्यवधान) उसके साथ ही आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं लिया। …(व्यवधान) अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिन्दुस्तान के रूरल डेवलपमेंट में एक सिग्नीफिकेंट भूमिका निभाई थी। …(व्यवधान) उनको भी इसमें रहना चाहिए। वह भी एक ड्रीमर थे। …(व्यवधान) आप दिखाते हैं कि हमारा सिर्फ एक ही ड्रीमर है। एक ड्रीमर नहीं, हिन्दुस्तान में बहुत सारे ड्रीमर्स हैं। …(व्यवधान) आपके न्यु इंडिया में क्या हो रहा है? आपके न्यु इंडिया में आज पोलराइजेशन हो रहा है। आपके न्यु इंडिया में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आपके न्यु इंडिया में गरीबी बढ़ रही है। आपके न्यु इंडिया में रोजगार नहीं है। आपके न्यु इंडिया में रिलीजियस जिंगोइज्म हो रहा है। आपके न्यु इंडिया

में मॉब लिंचिंग होती है। यह है आपका न्यु इंडिया, जिसमें मॉब लिंचिंग होती है, दलित रिप्रेशन होता है और रिलीजियस जिंगोइज्म होता है। यही है आपका न्यु इंडिया। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप कन्क्लूड करें।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, यह जो सरकार आई, यह चेस्ट थम्पिंग गवर्नमेंट आई है। ये ब्रैगिंग और वेनग्लोरी जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। …(व्यवधान)

सर, मैं एक और छोटा सा मुद्दा उठाना चाहता हूं। चाइना के साथ हमारी इतनी दुश्मनी रहते हुए भी आप चाइना को 5जी कांट्रैक्ट क्यों दे रहे हैं? जहां अमेरिका ने ना कर दिया, यूरोप ने ना कर दिया, आस्ट्रेलिया ने ना कर दिया, कनाडा ने ना कर दिया, आप उसे 5जी की सुविधा क्यों दे रहे हैं? यह हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर 5जी चाइना को मिल जाए तो हमारे लिए बड़ा खतरा पैदा करेगा। इसमें भी आप सोच-समझकर कदम उठाइए। …(व्यवधान)

सर, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उनके काफी नजदीकी एक एडवाइजर थे, उनका नाम था कुलकर्णी जी। …(व्यवधान) सुधीन्द्र कुलकर्णी की एक बात मैं क्वोट करना चाहता हूं। सुधीन्द्र कुलकर्णी ने एक बात कही :

> "What does the Sangh Paravar want? The Sangh Parivar wants second republic."

क्योंकि पहले रिपब्लिक में उनका कोई योगदान नहीं था, *… (Not recorded)* …(व्यवधान) ब्रिटिश लोगों के लिए अपनी युवा को रिक्रूट करने के लिए कहा था। …(व्यवधान) उसमें उनका कोई योगदान नहीं था। इसलिए वे सेकण्ड रिपब्लिक चाहते हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रिकॉर्ड से निकाल देना।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, सेकण्ड रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? सेकण्ड रिपब्लिक का मतलब है कि हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहिए।

Sir, de-nationalising a community or at least diminishing its place in the nation is the hidden agenda of the Citizenship (Amendment) Act. What do they want? They foretell a plan by the Sangh Parivar, the ideological family to which the Ruling Party belongs, to transform the Indian State into a Hindu State, Indian society from a Hindu majority society into a Hindu-majoritarian society and, finally, the Indian nation itself into a Hindu nation.

यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह एडवाइजर सुधीन्द्र कुलकर्णी का बयान है। यह मेरा नहीं है। मैं और एक बात कहना चाहता हूं। एफ. एस. एजाजुद्दीन नाम के एमिनेंट पाकिस्तानी स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा है :

"We, Pakistanis, have paid a huge price - violent conflicts, sectarianism, extremism, intolerance and loss of rights and freedom – because we allowed Islamisation of our State and society. If India wants to commit the same mistake by allowing its Hindu-isation, you are almost welcome, but remember that the price you will pay will be far, far higher."

सर, इसलिए आज हिन्दुस्तान में संविधान की रक्षा करने के लिए जो संग्राम हो रहे है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, आन्दोलन हो रहे हैं, उनको हम सभी को मदद करनी चाहिए, क्योंकि वे संविधान को बचाना चाहते हैं।

(1455/RAJ/RBN)

हम लोग मदद करना चाहते हैं।…(व्यवधान) यह संविधान को बचाने की लड़ाई है और उससे डर कर आप लड़खड़ाते हुए पीछे हट रहे हैं। Last but not the least, let me talk about the courses of civilisation. वर्ष 1939 में जब सेकेण्ड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, तब हमारे रविन्द्र नाथ टैगोर यूरोप में गए थे। उन्होंने वहां देखा कि आइंस्टाइन को जर्मन से भगाया जा रहा है। उन्होंने यह देखा कि वहां के अच्छे-अच्छे लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, तब कवि का मन बहुत दु:खी हुआ था। उन्होंने अपने दोस्तों को पत्र लिख कर कहा था कि मैंने यूरोप में देखा कि इस तरह का फासिज्म चल रहा है, इससे निपटने का क्या रास्ता है? उनको बहुत दोस्तों ने रिप्लाई दिया। एक रिप्लाई ऐसा था :-

The course of civilisation has never been determined by the brutal forces. The course of civilisation is determined by the forces of humanity. Therefore, neither the Brown shirt of Hitler nor the Black shirt of Mussolini is going to determine the course of civilisation in the contemporary period. The course of civilisation is going to be determined by a person who has no shirt and he is Mahatma Gandhi. He still lives in our soul.

हम आपके खिलाफ लड़ते रहेंगे। जितनी संख्या हो जाए, हम आपके खिलाफ लड़ते रहेंगे, क्योंकि आप अन्याय कर रहे हैं, देश का विभाजन कर रहे हैं, देश के टुकड़े करना चाहते हैं, इसलिए आपके खिलाफ लड़ना वाजिब है।

"ना संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में।
बड़ा-बड़ा तूफान थम जाएगा, जब आग लगी हो सीने में।"

हमारे सीने में आग लगी है। हिन्दुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को खत्म करने वाली साजिश से लड़ने के लिए, हमारे सीने में आग लगी है, हम लड़ते रहेंगे। जय हिंद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : श्री पी. पी. चौधरी जी।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, Shri Adhir Ranjan Chowdhury quoted Shri Sudheendra Kulkarni. He has to place that material on the Table of the House.

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): उनको प्रेज करने दें।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

***श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर (दाहोद):**

---

* Laid on the Table

*DR. R.K. RANJAN (INNER MANIPUR):

---

*Laid on the Table.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):

*Laid on the Table

***श्रीमती शारदाबेन अनिलभाई पटेल (महेसाणा):**

---

* Laid on the Table

*** श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर):**

---

* Laid on the Table

*श्री विष्णु दयाल राम (पलामू):

---

* Laid on the Table

***श्री राहुल कस्वां (चुरू):**

---

* Laid on the Table

1458 बजे

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा में समय देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

1458 बजे (श्री ए. राजा पीठासीन हुए)

अभी हम ने बहुत ही विस्तार से अधीर रंजन चौधरी जी को सुना है, लेकिन मैं यह बता दूं कि उन्होंने जिस हिसाब से बोला है, हमारा काम सॉल्व कर दिया। आम जनता ने जो सुना है, पूरे सदन ने सुना है, जिस हिसाब से इन्होंने रैंकिंग की बात की है, इन्होंने पाकिस्तान और दूसरे देशों का हवाला दिया है, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि अगर आप उनके सपनों को साथ लेकर चलते, उनको पूरा करने की सोचते, आपने जो लंबे समय तक राज किया है, उससे हमारी रैंकिंग इस तरह की नहीं रहती। आपने जो काम 60 सालों में काम नहीं किया, हम ने वे काम पांच सालों में किया। आपने खुद ब्यान देकर यह बता दिया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से देश में गांव और शहर में जो दूरी है, जिस हिसाब से गांधी जी ने ग्राम स्वराज का जो सपना संजोया था, आप 60 सालों तक राज करते रहे, उनका नाम लेते रहे, उनका सपना आपने कभी पूरा नहीं किया। मैं बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी की बात करूंगा। उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की है, उन्होंने फाइनैंशियल इंक्लूजन की बात की, उन्होंने समाज के अंतिम छोर पर बैठे लोगों को मदद देने की बात की है, लेकिन आपने बाबा साहेब अम्बेडकर का भी यह सपना पूरा नहीं किया।

(1500/VB/SM)

मैं सरदार पटेल जी की बात करूँगा, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की। धारा 370 पर मैं विस्तार से आगे बताऊँगा, क्योंकि आपने उसके बारे में काफी बताया है, मैं उसका जवाब भी देना चाहूँगा। सरदार पटेल जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कहा। जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में जो गलतियाँ और जो पाप आपने किए, उनको साफ करने और धोने का काम मोदी सरकार ने किया है।

मैं आपके नेहरू जी की बात कहूँगा। उन्होंने आधुनिक भारत का जो सपना देखा था, उस सपने को भी आपने चकनाचूर किया। यही नहीं, पंडित दीनदयाल जी का तो आप नाम ही नहीं लेते हैं, लेकिन उनके अंत्योदय का लक्ष्य, जो हमारा कोर इश्यू है, उसको हमने अचीव करने का काम किया है और यह काम मोदी सरकार के समय में हुआ है।

लोहिया जी बात करूँ, तो समता समाज के दर्शन का जो सपना है, उसे पूरा करने के लिए आपने 55 साल के राज में कुछ नहीं किया है। आपको सिर्फ एक परिवार दिखता है। उनके अलावा आपको किसी का सपना नहीं दिखता है। ये सपने आपके लिए गौण हैं। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी की जो सोच है, जो दूरदृष्टि है, उसके अनुसार वे 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' को लेकर चल रहे हैं।

आप महात्मा गांधी जी को भूल गए, आप बाबा साहब अम्बेडकर जी को भूल गए और आप नेहरू जी को भी भूल गए। अगर आप उनके सपनों को साकार करते, तो यह तकलीफ नहीं होती। आज हमारे प्रधान मंत्री जी एक नये भारत का सपना देख रहे हैं। पिछले पाँच सालों में उन्होंने जिस

नये भारत की नींव रखी है, भारत को पूर्ण करने के लिए पाँच साल में जो काम हुए हैं, वे अनुकरणीय काम हुए हैं।

नये भारत के सपने में पुरानी समस्याओं का निराकरण है। सभी क्षेत्रों में विकास और सामाजिक न्याय के साथ फाइनेंशियल इनक्लूजन पर काम हुए हैं। गाँवों और शहरों में जो दूरियाँ बढ़ी हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उस दूरी को ब्रिज करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं प्रधान मंत्री मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूँगा कि जिस हिसाब से आने वाली चौथी औद्योगिक क्रांति होगी, उसमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस हिसाब से देश आगे बढ़ रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी की ज़बरदस्त भूमिका होगी और यह भारत को आगे लेकर जाएगी।

जहाँ तक ग्राम स्वराज की बात है। मैं आपको बता दूँ कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने लगभग 25 लाख करोड़ रुपये आने वाले समय में ग्राम स्वराज के लिए खर्च करने का निर्णय लिया है। यही नहीं, लम्बे समय से गाँवों और शहरों के बीच जो दूरी बनी हुई थी, जो गैप बना हुआ था, खाई बनी हुई थी, उसको पाटने का और सेतु बनाने जो काम हो रहा है, वह टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। इसके लिए पूरे देश में भारत नेट के द्वारा हर ग्राम पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का काम हो रहा है। लगभग 1,25,000 ग्राम पंचायतें इससे जुड़ चुकी हैं और आने वाले समय में कुल 2,60,000 ग्राम पंचायतें इससे जुड़ जाएंगी। अपने आप में यह एक बहुत बड़ा काम होगा।

अगर मैं गवर्नेंस की स्पीड की बात करूँ, तो वर्ष 2011 में भारत नेट योजना शुरू हुई और वर्ष 2014 तक सिर्फ 56 ग्राम पंचायतें ही कवर हो पाईं, लेकिन वर्ष 2014 से आज तक लगभग 1,25,000 ग्राम पंचायतों को कवर किया गया है। इससे एक बहुत बड़ा रूरल एम्प्लॉयमेंट मिला है। जो कॉमन सर्विस सेन्टर्स हैं, उनमें करीब 3,60,000 सर्विस सेन्टर्स खड़े हुए हैं, जिनकी वजह से इंटरनेट की रूरल सर्विस आम आदमियों को मिल रही है।

यदि हम गाँवों की बात करें, तो जिस तरह से हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का सपना संजोया था, उसके तहत थर्ड फेज में 1,25,000 किलोमीटर का काम पूर्ण होने वाला है। वर्ष 2024 तक हर घर को नल का पानी मिले, यह प्रधान मंत्री जी का सपना है।

देश को आजाद हुए लगभग 70 साल हो गए, लेकिन अगर पूरा कार्यकाल देखा जाए, तो घर-घर पानी पहुँचाने का काम बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उस बारे में कुछ नहीं किया।

मैं यह भी बताना चाहूँगा कि विकास के जो अन्य काम हैं, आने वाले समय में उनके लिए लगभग सौ लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, खासकर हाइवेज़, वाटरवेज़, एयरवेज़ और आई-वेज़ के निर्माण के लिए खर्च किए जाएंगे।

जहाँ तक पारदर्शिता की बात है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि जब भी मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूँ, तो पन्द्रह पैसे ही पहुँच पाते हैं और पचासी पैसे बीच में ही खत्म हो जाते हैं।

(1505/PC/AK)

इसके इंतज़ाम के लिए इन्होंने कभी नहीं सोचा। इसके लिए पुख्ता इंतज़ाम हों कि गरीब आदमी के लिए और समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, उसको पूरा पैसा मिले। इसके लिए कभी नहीं सोचा। इसके लिए अगर काम किया तो वह मोदी सरकार ने पिछले पांच सालों में किया। मैं सबसे पहले कहूंगा कि हमारे विज़नरी प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि जब तक हमें सामाजिक न्याय नहीं मिलता, तब तक फाइनेंशियल इन्क्लूज़न नहीं हो सकता। उन्होंने फाइनेंशियल इन्क्लूज़न के लिए करीब 38 करोड़ जन-धन के अकाउंट खोले। यही नहीं, उन्होंने अकाउंट खुलवाने के बाद आधार भी बनवाया। आज देश में 121 करोड़ आधार कार्ड बने हैं। यह एक बहुत बड़ा, बहुत मजबूत फाइनेंशियल इन्क्लूज़न का देश में काम हुआ है।

यही कारण है, इसी की वजह से डायरेक्ट बेनिफेट ट्रांसफर से लगभग 450 विभिन्न योजनाओं में दिल्ली से सीधा पैसा उन गरीबों के पास, वह व्यक्ति जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा है, जो लाभार्थी हैं, उनके खातों में सीधे जाता है। पहले यही पैसा लीक हो जाता था। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इस लीकेज का जो अमाउंट था, आज तक, पिछले पांच सालों में करीब नौ लाख करोड़ रुपये उनके खातों में पहुंचे हैं, लेकिन जो लीकेज बचा, वह करीब एक लाख सत्तर हजार करोड़ रुपये है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर यह डीबीटी नहीं होता, अगर यह आधाार नहीं होता, अगर फाइनेंशियल इन्क्लूज़न के तहत ये 38 हजार अकाउंट नहीं होते तो उनके खातों में यह पैसा नहीं पहुंचता। इससे एक लाख सत्तर हजार करोड़ रुपये का इस देश को नुकसान होता। यह अपने आप में एक सबसे बड़ा काम हुआ है। अगर भ्रष्टाचार को मिटाने का किसी ने काम किया है तो प्रधान मंत्री मोदी ने किया है।

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से विकास के काम में, और खासकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में प्रतिवर्ष चार लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और एप्लाएंसेज़ इम्पोर्ट होते हैं, लेकिन हमारे बजट की बहुत बड़ी फॉरेन करन्सी उसमें मिसयूज़ हो रही थी, बर्बाद हो रही थी। हमारे देश में जब मोदी जी प्रधान मंत्री बने, उस समय दो मोबाइल कंपनीज़ थीं, लेकिन वर्ष 2019 तक 268 मोबाइल कंपनीज़ आ गई हैं। इसके अलावा करीब चार लाख साठ हजार करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और एप्लाएंसेज़ इंडिया में बन रहे हैं। यही नहीं, हमारी रुरल बैकबोन एमएसएमई है। इसके बारे में कभी ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आज हमारा जो 90 परसेंट एम्प्लॉयमेंट है, रूरल एमएसएमई उसका आधार है। इसको बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री जी और हमारी सरकार भरपूर काम कर रही है। इसी कारण आने वाले टाइम में हम जो स्वदेशी का नारा लगा रहे हैं, उसे भी यह एमएसएमई पूरा करेगी। यही हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। अगर इस बैकबोन का, जो ये बात कर रहे हैं, अगर इसका ध्यान दिया होता तो हमें कभी भी यह तकलीफ नहीं आती।

सभापति महोदय, जहां तक हम देख रहे हैं, पिछले पांच सालों में गवर्नेंस की स्पीड और स्केल की बात हम करें तो अपने आप में ये अनप्रेसिडेंटेड हैं। विकास के मामले में विश्व स्तर पर पूरे

भारत की साख और पैठ बनाने का जो काम किया है, वह पांच सालों में हमें पहली बार देखने को मिला है। यही नहीं, पिछले पांच सालों में करीब 220 बिल्स, विभिन्न कानून बने हैं, चाहे जीएसटी कानून हो, चाहे आईबीसी हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे एनिमी प्रॉपर्टी का कानून हो। इसके साथ-साथ 1,500 कानून ऐसे थे, जो ब्रिटिश राज के टाइम के थे। वे कानून चले आ रहे थे, कन्फ्यूज़ कर रहे थे। उनको हटाने का, उनको रिपील करने का, जो रिडन्डेन्ट कानून थे, जिनका कोई औचित्य नहीं, जिनका लॉजिक नहीं था, जो अननेसिसरी कानून थे, उनको हटाने का काम किया।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, कई और काम भी ऐसे हैं, जिन पर काम किया जाना चाहिए, जैसे संविधान का आर्टिकल-44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का है। उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए साफ लिखा है। यह पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यह लिखा हुआ है। मैं इसके साथ-साथ यह भी बताना चाहूंगा कि आर्टिकल-48 में - prohibition of cow slaughter and calves and other milch and draught cattle, के बारे में लिखा हुआ है। मुझे विश्वास है कि इसके लिए भी कानून जरूर आएगा।

(1510/SPS/SPR)

अगर हम इकॉनोमिक सेक्टर की बात करें तो पहले बैंकों द्वारा वर्ष 2006 तक 18 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया गया था, लेकिन 2006 से 2013 के बीच सिर्फ 6-7 साल के अंदर उस अमाउंट को करीब 52 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया गया। यही कारण था कि एक समय ऐसा आया जब बैंक डगमगा गए और एन.पी.ए. हुआ। बैंकों की रिकवरी नहीं हो रही थी, फिर हमारी सरकार मोदी सरकार ने आई.बी.सी. लाकर रिकवरी कराई और 10 लाख करोड़ के एन.पी.ए. में से लगभग 3.5 लाख करोड़ एन.पी.ए. के अमाउण्ट की बैंकों में रिकवरी हो चुकी है। आई.बी.सी. के आने की वजह से हमारी रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छी बढ़ी है। इसके साथ ही लम्बे समय से नॉन कंप्लायंस सेल कंपनियां चल रही थीं। करीब 4 लाख कंपनियों को स्ट्रक ऑफ करके, जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन के वक्त लाखों-करोड़ों रुपये जमा किए हैं, उनकी भी जांच चल रही है।

हम नए भारत की बात करें तो पुरानी समस्याओं का समाधान वाला भारत, ऐसा भारत जहां पुरानी समस्याओं का समाधान हो। अभी अधीर रंजन जी ने धारा 370 की बात की, अनुच्छेद 35A की बात की। मैं यह बताना चाहूंगा कि यह धारा 370 का मामला क्यों आया और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की भी बात की है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और धारा 370 के पाप कांग्रेस ने किए गए थे। जब वहां के राजा हरी सिंह जी ने इनसे सेना मांगी, तो उस समय नेहरू जी ने सेना नहीं दी थी, लेकिन सरदार पटेल जी को धन्यवाद जाता है कि उन्होंने उसी समय वहां पर उन कवाइयों को वापस किया और जम्मू कश्मीर को अपने पास रखा। जो धारा 370 थी, उसका 70 साल तक टेम्परेरी स्टेटस रहा और 70 साल तक डेमोक्रेसी तीन परिवारों के इर्द-गिर्द घूमती रही। डेमोक्रेसी का नाम नहीं था और यही कारण था कि जम्मू कश्मीर विकास की गति में दूसरे प्रदेशों से पीछे रहा। अब हम देखें तो प्रोग्रेस हुई है। चाहे प्रधान मंत्री आवास योजना को देख लीजिए। अगर हम वर्ष 2018 तक की

बात करें तो वर्ष 2018 के पहले करीब 3500 आवास थे, लेकिन अब प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 24 हजार आवास बन चुके हैं।

इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी काफी विकास हुआ है। अगर बोडोलैंड की बात करें तो यह समस्या लम्बे समय से बनी हुई थी। अगर हम देखें तो यह यह नार्थ-ईस्ट की बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या को खत्म करने का काम किया, उनके साथ वार्तालाप करके, उनकी मांग का निपटारा किया, उनकी बात को भी समझा। उस पीरियड में करीब 4 हजार लोगों की मृत्यु हुई थी। इस तरह से देखा जाए तो यह बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इसके अलावा और भी ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ समझौते किए गए हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को खत्म किया गया है।

जहां तक ट्रिपल तलाक की बात है तो जेंडर इनइक्वैलिटी का मामला एक लंबे समय से चल रहा था, तो उसके लिए कानून लाया गया। आज हमारे प्रधान मंत्री जी ने लोक सभा में राम मंदिर के बारे में स्टेटमेंट दिया है, यह एक बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। पहले कोर्ट के फैसले की लम्बे समय तक पालना नहीं हुई थी, लेकिन राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला होते ही, ट्रस्ट का निर्माण कर दिया, कैबिनेट में डिसीजन ले लिया और वह अप्रूव भी हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सुन्नी वक्फ बोर्ड को अपनी स्वीकृति दे दी। यह जो काम हुआ है, वह बहुत स्पीड से हुआ है।

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे अभिनन्दन की बात हो, दिल्ली के नेता इसका मजाक उड़ाते हैं। वे पूछते हैं कि आतंकियों को मारा है या नहीं मारा है और कितने आतंकी मारे हैं? अबकी बार जब भी इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक होगी, तो गिनती कराने के लिए उनको ही साथ में भेज दिया करेंगे।

मैं 'आयुष्मान योजना' के बारे में बताना चाहूंगा, जिसमें गरीब को प्रति परिवार 5 लाख रुपये की मदद मिलती है। उससे करीब 10 करोड़ परिवार और 50 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं। उस योजना को दिल्ली जैसे शहर, जहां गरीब लोग भी रहते हैं, लागू नहीं किया गया है। वे लम्बे समय से कॉलोनीज में रह रहे थे। उनके लिए मोदी सरकार ने कानून लाकर उनकी कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का काम किया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है।

(1515/MM/UB)

महोदय, सीएए के बारे में उन्होंने बात कही है। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। यह सबसे भारी भूल थी। कांस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क जो है, जिस समय भारत का संविधान बना, वह नहीं चाहते थे, क्योंकि जिस तरह से आना-जाना रहा, जबरदस्त माइग्रेशन था, मार-काट हो रही थी, इसलिए उस समय कांस्टीट्यूशन में सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं किया गया था। इसकी पावर भारत की पार्लियामेंट को दी गयी थी। पार्लियामेंट ने वर्ष 1955 में यह एक्ट बनाया और धारा 5 और 6 के तहत सिटीजनशिप देने का प्रावधान रखा गया।

महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पार्टिशन के वक्त खून खराबा हो रहा था, इसलिए नेहरू-लियाकत संधि हुई थी। उस संधि को पाकिस्तान को ऑनर करना था और माइनोरिटीज को प्रोटेक्ट करना था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे गांधी जी का भी दिल दहल गया और उन्होंने भी

बार-बार कहा, अपनी प्रेयर मीटिंग में कहा कि अगर हिन्दू और सिख, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर वे भारत आते हैं, तो सम्मान के साथ जीवन जीने का उन्हें मौका मिलेगा और उनको नागरिकता मिलेगी। लेकिन वह कमिटमेंट, गांधी जी के जो कमिटमेंट उस समय के थे, इन्होंने क्यों पूरे नहीं किए? जबकि अधीर रंजन जी आज गांधी जी की बात कर रहे थे। गांधी जी का जो कमिटमेंट था, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। यही नहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे गोगोई जी हों, चाहे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी हों, चाहे आई.के. गुजराल जी हों, सभी ने कहा था कि जो हिन्दू और सिख आए हुए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। लेकिन मोदी जी ने अब इसको कर दिया है तो इनको तकलीफ हो रही है कि मोदी जी ने यह कैसे कर दिया? इसलिए सीएए कोई उपकार नहीं है, यह अन्याय का प्रायश्चित है। यह संवैधानिक बाध्यता थी, यह अनफिनिश्ड एजेंडा था, जिसको मोदी सरकार ने पूरा किया है। यह राजनैतिक इच्छाशक्ति का परिणाम है, अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम है, यह पूर्ण समर्पण का और दूरदर्शिता का प्रमाण है।

महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि सीएए से सरकार पीछे हट रही है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। कर्तव्य के पूनीत पथ पर यह सरकार आगे बढ़ती रहेगी और चुनौती के समक्ष नहीं झुकेगी।

"कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद से सींचा है।
कभी-कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्ध्य भी दिया है।
किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं,
किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं हैं।"

महोदय, अधीर रंजन जी ने कहा कि इनको तकलीफ हो रही है कि इन लोगों को नागरिकता क्यों दी जा रही है? मैं यह बताना चाहता हूं कि परसेक्यूटेड मॉइनोरिटीज के पाकिस्तान में जिस प्रकार के हाल थे, उनकी संख्या 23 से 3 परसेंट हो गयी है, उनके मंदिर तोड़ दिए गए हैं। पाकिस्तान में करीब दो लाख मंदिर थे, अब केवल पांच सौ मंदिर रह गए हैं। अब वहां तीन परसेंट पॉप्युलेशन मॉइनोरिटीज की रह गयी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि या तो वे भागकर हिन्दुस्तान आ गए हैं या उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है या उनको मार दिया गया है। नेहरू-लियाकत पैक्ट की अगर बात करें तो हमारे देश के मुस्लिम बहुत सिक्योर और सुरक्षित हैं। आज हमारे देश में मुस्लिमों की संख्या 8 से 15 परसेंट हो गयी है, लेकिन पाकिस्तान में मॉइनोरिटीज की संख्या 23 से 3 परसेंट हो गयी है। अगर हम हमारे यहां आए शरणार्थियों को राहत नहीं देंगे, उनको नागरिकता प्रदान नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? यह मानवता के सिद्धांत के भी खिलाफ होगा।

महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री दलित थे। भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे तो पाकिस्तान में जोगेंद्र नाथ जी मंडल थे। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से वहां नरसंहार देखा और घूम-घूमकर देखा तो उन्हें पता लगा कि दलितों और माइनोरिटीज़ का, हिन्दुओं और सिखों का कत्लेआम हुआ है। इनके पुरुषों को तो मार दिया गया और फीमेल बच्चियों और बेटियों को उनके रिंग लीडर्स में आपस में बांट दिया गया। उनके साथ रेप

हुए तो उनका दिल दहल गया। वे इस्तीफा देकर भारत में आ गए। वर्ष 1955 में भारत आने के बाद वेस्ट बंगाल में रहे और एक शरणार्थी के रूप में रहे। वर्ष 1968 में जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक वे शरणार्थी थे। इससे ज्यादा परस्युकेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है?

(1520/SJN/KMR)

हमारे प्रधान मंत्री जी ने जिस हिसाब से सीएए का एक्ट बनाया है, वह अपने आप में उन कम्युनिटीज़ को, रिलिज़ियस पर्सेक्युटेड माइनोरिटीज़ को प्रेफरेन्स देने के लिए है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके लिए वर्ष 1950 में नेहरू जी और अंबेडकर जी ने जो असम की समस्या थी, उन्होंने उसको सॉल्व करने के लिए कहा था कि इस तरह के जो लोग आए हैं, उनको वापस भेजा जाएगा, लेकिन हिन्दू और सिखों को यहीं पर रखा जाएगा। यही नहीं, वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय गुजरात और राजस्थान के जो बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स थें, उनमें उन लोगों को नागरिकता देने का काम किया गया था।

अधीर रंजन चौधरी जी ने बड़ी लंबी-चौड़ी बात कही है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप शाहीन बाग के धरने में जाकर यह भाषण क्यों नहीं देते हैं कि जो पर्सेक्युशन हुआ है, जो अन्याय हुआ है, आपको पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आपने 70 सालों तक क्यों नहीं आवाज उठाई? आप यह बता दीजिए कि आपने 70 सालों से आवाज उठाई हो और आप जिस हिसाब से धरने में जाकर बात करते हैं।...(व्यवधान) आपने वहां जाकर यह क्यों नहीं बताया है? आप उनको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं।...(व्यवधान) आपको यह बताना चाहिए कि यह कानून नागरिकता लेने का नहीं है, बल्कि यह नागरिकता देने का कानून है। आप यह देखिए कि किनके ग्रीवेन्सेज हैं, पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, उनके ग्रीवेन्सेज हैं। आपका ग्रीवेन्सेज नहीं है। आपको तकलीफ नहीं है। लेकिन आप उनको भड़का रहे हैं। आप उनको उत्तेजित कर रहे हैं। हमने जमीन का थर्ड पोर्शन उनको दिया है। क्या आप यह चाहते हैं कि जो भगौड़े और आतंकवादी वगैरह हैं, हम उन लोगों को भी यहां पर नागरिकता दें? अगर यह आवाज उठाई गई है, तो कांग्रेस ने नहीं उठाई है, बल्कि वर्ष 1952 से भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है कि इस तरह के जो पर्सेक्युटेड माइनोरिटीज़ हैं, उनको नागरिकता दी जानी चाहिए।

आपने एनआरसी की भी बात की है। लेकिन यह हो सकता है कि शायद आपने सेक्शन 14(सी) नहीं देखा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सिटिज़नशिप एक्ट का जो 14(सी) है, वह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में नवंबर, 2004 में लाया गया था। उसमें क्या किया गया था और वह किस आधार पर लाया गया था? उसमें कमेटी की रेकमेंडेशन्स आई थीं। उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी उसके चेयरमैन थे, उसके मेंबर थे।...(व्यवधान) जब उसके बाद उस कमेटी की रेकमेंडेशन्स आई थीं, तब उसकी रेकमेंडेशन्स के आधार पर 14(सी) आया था। उसमें यह कहा गया था कि सिटिज़नशिप का नेशनल आइडेन्टटी कार्ड है, वह मिलना चाहिए। उसमें यह मैन्डेटरी किया गया था। आप जो एनआरसी की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि एनआरसी की बात को आप लेकर आए हैं। यह हमारी सरकार में डेलिब्रेशन का, डिस्कशन का इश्यू नहीं है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है, वह आपने एनआरसी की रेकमेंडेशन के तहत कम्प्लसरी माना है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब आप भारत का संविधान पढ़ाते हैं, तो आप अपने नेता को पूरा संविधान पढ़ाइए। आप अपने नेता को संविधान का पहला पेज मत पढ़ाइए। संविधान एक पेज का नहीं है। मोदी जी के लिए आपने सेक्युलर की बात कही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने पूरे संविधान को

प्रणाम किया है, न कि सिर्फ एक पन्ने को किया है। उसमें सेक्युलर भी है और उसमें पूरा संविधान भी है। जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, आपने उन राज्यों में इस तरह का संकल्प लाने का काम किया है। आप यह बता दीजिए कि जब आप संविधान की बात करते हैं, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि आप आर्टिकल 256 को देख लीजिए। पार्लियामेंट से जो कानून बनता है, उसमें राज्यों की यह ड्यूटी है कि उसकी पालना कराई जाए। लेकिन आपने पालन कराने की बजाय यह काम किया है कि कैसे उसकी अवहेलना की जाए। संसद के द्वारा जो कानून बनता है, क्या वह सड़कों पर तय हो सकता है? यह आपको अच्छी तरह से पता है कि संसद के कानून को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, उसको कोर्ट देख सकता है। लेकिन सड़कों पर जनता को देखकर इस कानून को सरकार संसद के सामने लेकर आई है और आप लोग भी यहीं थे। आप लोगों ने इसको पास किया है। राज्य सरकारें आर्टिकल 256 के तहत बाधित हैं कि वे उसको लागू करें। यही नहीं, आर्टिकल 51(ए) में यह है कि हर नागरिक संविधान की इज्जत करें। यह कानून भारत के संविधान के तहत बना है। हर नागरिक की यह ड्यूटी है कि वह संविधान के आइडियल की रिस्पेक्ट करे और संवैधानिक संस्थान की रिस्पेक्ट करे। आपको शाहीन बाग में जाकर यह भाषण देना चाहिए, यह बताना चाहिए। उनको यह बताने की बजाय आप उनको भड़काने का काम कर रहे हैं।

यही नहीं, आप जिस हिसाब से भ्रमित और भड़काने की राजनीति कर रहे हैं, आप देश के बंटवारे के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, आपकी जो वोटों की राजनीति है, वह लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। यह कानून संसद में व्यापक बहस के बाद में बना है।

(1525/GG/SNT)

जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, उसमें आपने कुछ नहीं बोला है। जो वहां पर, शाहीन बाग में या जेएनयू में पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, वहां पर जा कर आपके लीडर्स उनको उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं और उनको और ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि और नारे लगाओ। आपने एक शब्द भी नहीं बोला कि हम आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। यही नहीं, मैं यह बता दूं कि आपके नेता दिग्विजय सिंह जी हों, शशि थरूर जी हों, चाहे आप पार्टी के नेता हों, वहां शाहीन बाग में गए और जा कर और भी भड़काऊ भाषण दिए। यह ठीक नहीं है।

महोदय, मैं अंत में यही बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार देश की सुरक्षा के लिए है, देश के विकास के लिए है। हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारी पार्टी बाद में है, लेकिन देश सर्वोपरि है और मातृभूमि सर्वोपरी है। हम इस तरह की राजीनीति के बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन मैं अंत में अटल जी की कविता 'भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है', से चार पंक्तियां पढ़ कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

" यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है।
यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है।
इसका कंकर-कंकर शंकर है, इसका बिन्दु-बिन्दु गंगाजल है।
हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। "

(इति)

1526 hours

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am rising to speak to oppose the Motion of Thanks on the President's Address. But who will I speak to? These empty Treasury Benches! There is only one Minister from Rajya Sabha and only one Lady Minister from the Lok Sabha. All the others are 'half Ministers'. …(*Interruptions*) Shri Arjun Munda is also here. So, all 'reserved people' are here but the Ministers have all fled. They have gone for the Delhi elections which they are going to lose. Remember this. …(*Interruptions*)

Sir, I speak in favour of the eight amendments moved by me. Most of them relate to the nationwide agitation against the Citizenship Amendment Act and the insecurity among the minority community over the Act. The amendments specifically relate to protest, especially by students and women as in Shaheen Bagh. They also refer to the lowest GDP growth of 4.8 per cent and the highest unemployment rate in 45 years. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Please address the Chair. No cross talk. Please address the Chair.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, my amendments also relate to the highest unemployment rate in 45 years of which there has been no mention in the Address. They raised the matter of disinvestment of BPCL, LIC and 28 other PSUs to be disinvested. The whole Address does not mention the crisis in the auto industry, real estate sector, and the non-banking financial companies. So, this is an empty Address, which does not address any of the pressing problems of the country.

Sir, before I proceed further, I strongly protest the way Mahatma Gandhi's name has been used by these people in wrongly quoting him. In para 36, they have referred to Mahatma Gandhi's statement as if on Mahatma Gandhi's advice they are bringing the Citizenship Amendment Act. Please listen to what Mahatma Gandhi said. It is from The Collected Works of Mahatma Gandhi Vol. 96. Mahatma Gandhi said:

> "If we regard all the Muslims as fifth-columnists, will not the Hindus and Sikhs in Pakistan also be considered fifth-columnists? That would not do."

He was referring to Hindus and Sikhs in Pakistan.

"The Hindus and the Sikhs staying there can come here by all means if they do not wish to continue staying there. In that case, it is the first duty of the Indian Government to give them jobs and make their lives comfortable. But they cannot continue to stay there and become petty spies and work for us and not for Pakistan."

(1530/GM/KN)

This is what Gandhi ji said. He said that they should not stay there as our spies. If they stay there, they should be part of them. In the same writing, he said about the Muslims, "The Muslims have said they would be loyal to India. Let us trust them with our heart. Let us remember that truth alone triumphs; not untruth. सत्यमेव जयते, नानृतम्।" This Government is going on untruth, not according to what Gandhi ji said. So, I demand that Gandhi ji's name should be deleted from para 36. They should not use the name of *Pujya Bapu* in pursuing their nefarious, divisive political designs.

I want to mention that the country is in the biggest economic crisis in many years. You would understand that Reserve Bank of India was made to change its forecast four times on the domestic growth rate. First, it was 7.4 per cent; then they made it 6.14 per cent in November; in December, they made it 5 per cent. The International Monetary Fund slashed India's 2019 growth rate forecast to 4.8 per cent from 6.1 per cent projected in October last. Both the United Nations and the World Bank have cut India's growth rate forecast for the year 2020 to 5.7 and 5.0 per cent respectively. It is a dire state of affairs. Five per cent growth rate is lowest in 14 years; industrial growth rate is lowest in 14 years; demand for electricity consumption is lowest in last 12 years; private investment is lowest in last 16 years; unemployment index is alarmingly high in the last 45 years. Where will the unemployed get their jobs? Government says, "Go and riot." That is how unemployment will go.

In Davos, in World Economic Forum this year, Oxfam report says that India's richest one per cent hold more than four-times the wealth held by 953 million people who make up for the bottom 70 per cent of the country's population, while the total wealth of all Indian billionaires is more than the full-year budget in our country. Just imagine, 63 billionaires are holding all the assets.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): What was Oxfam doing in Davos?
PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): They gave a report in Davos. There is nothing wrong. Our Ministers also go to Davos.
SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): What was Oxfam doing there?
PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Oxfam is an economic organisation. They know a lot of things. I know you are opposed to Oxfam. …(*Interruptions*) Sir, 5000 billionaires who made money here, have escaped from India. They include Nirav Modi, Mehul Choksi *… (Not recorded)* यहाँ से पैसा बनाकर भाग जाते हैं। यही देश में हो रहा है। Vijay Mallya, Lalit Modi- *… (Not recorded)* …(*Interruptions*) अर्जुन मुंडा जी, ज़रा उठ जाइये। आपके सोने से ठीक नहीं लगता है। …(*Interruptions*)
जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): आपकी बात मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। …(*Interruptions*)
प्रो. सौगत राय (दमदम): आँख बंद नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को निराशा होती है।
THE MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL): Hon. Chairperson, how can he make these kinds of accusations?

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): We will check the record.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): The words *… (Not recorded)* are not good. …(*Interruptions*)
PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Ever since the Citizenship (Amendment) Act was passed by the Parliament on 11th December 2019, there has been spontaneous protests all over the country starting with Tripura, Meghalaya and Assam.
(1535/RK/CS)

In Assam, three people were killed in police firing. Firing by the police has spread all over the country. In UP, the biggest State of the country, more than 20 people have been killed in police firing. The students of Jamia Millia Islamia were lathi charged by the police in the campus itself. The protest has spread from Jamia to AMU, BHU and Delhi University. Universities and colleges, even IITs across the country, have joined the protest. The controversial Citizenship

(Amendment) Act has resulted in protests in several European cities and also by the Indian student community in US. Women have joined the protest in large number. I will tell you later, Shri Jaishankar, how we have been a failure. Women at Shaheen Bagh in Delhi have been on *dharna* in this cold open air for the last one-and-a-half months. The Government's anger is directed towards them. The Prime Minister makes them their target but they are braving the cold and sitting in protest against the Government's divisive agenda. There have been firing and attacks on them by the BJP leader and pro-Hindu elements....(*Interruptions*)

Madam, you are not part of this. Shiromani Akali Dal is against NRC. I know it. You are with us. Why are you fighting with me?

THE MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL): How can you make false accusations?...(*Interruptions*)

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैंने सुखबीर का बयान पढ़ा, वह आधा तो हमारे साथ है।...(व्यवधान)

मैडम, शाहीन बाग में बैठी महिलाओं की ओर आप जरा सहानुभूति रखिए।...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: आम आदमी पार्टी के लोग फायरिंग कर रहे हैं।...(व्यवधान) आप आम आदमी पार्टी से पूछिए।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): कोई भी फायरिंग करे, उन महिलाओं को देखिए।...(व्यवधान) हमारा आम आदमी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है।...(व्यवधान)

सर, आप मैडम को जरा कंट्रोल कीजिए।...(व्यवधान)

Sir, my main protest against the CAA is, because for the first time in matters of citizenship, it has introduced religions, and also, because it violates the Preamble and Article 14 of the Constitution. Sir, four State Assemblies of Kerala, Punjab, Rajasthan and West Bengal have passed Resolutions against the Act. The West Bengal Chief Minister has been relentless in her fight and has walked in many-many protests since mid-December, 2019. Petitions have been filed in the Supreme Court in the matter.

This Government speaks in many voices on the Act and the proposed NRC. The Home Minister has asserted in this Lok Sabha that we shall have the NRC throughout the country. I heard it with my own ears. He said that NRC would be implemented throughout the country. The Prime Minister while speaking at the Ramlila Maidan said; "Oh, nobody talked to me about the NRC.

We have never discussed it." The Minister replied in the Parliament yesterday that we have not yet decided to enact the NRC.

My appeal to the Government is to speak with one voice. Scrap the NRC and CAA and declare that there will be no NRC. Do not stand on prestige. The protesters at Shaheen Bagh are not our enemies. They are holding the National Flag and singing the National Anthem. Do not take them as enemies. Do not shoot at them. Do not shout at them. I think, shooting and shouting alone is the actual conspiracy against the Prime Minister. Some people, his Ministers, are out to destroy his image. Is the Minister who said, '*goli maro'*, a friend of the Prime Minister?

(1540/PS/RV)

The BJP MP has said, "I will break or demolish all the unauthorised mosques in my constituency". Is he a friend of the hon. Prime Minister? His name is Shri Parvesh Sahib Singh Verma. Then, there is another MP who said that Gandhi's freedom struggle was a stage-managed affair. Is he a friend of the hon. Prime Minister? The image of the hon. Prime Minister is being destroyed every day. This conspiracy is led by somebody called *… (Not recorded)*. He is saying that there will be NRC, while the hon. Prime Minister says that there will be no NRC. So, will the real Prime Minister please stand up and be counted and say as to who is saying the real thing? We want to know about it.

I would like to say one thing. Dr. Subrahmanyam Jaishankar, this is for you. Our hon. Prime Minister has assiduously tried to build-up the image of an international person. We saw him swinging on a *jhoola* with the Chinese President. He was leading an International Solar Alliance with Mr. Macron in Paris. He used to call Barack Obama as 'Barack', to which Dr. Jaishankar must have contributed. Now, recently he has gone to Houston and did 'Howdy Modi' with Mr. Trump, who is under impeachment. Anyway, that is their internal matter. What is the hon. Prime Minister's image coming through after all these build-ups and after all these '*jhoola*.' Today, we hear that that image has been destroyed. In May, Mr. Aatish Taseer wrote in the international edition of *The Time Magazine*. …(*Interruptions*) I know who he is. He is the son of Ms. Tavleen Singh. …(*Interruptions*) Ms. Tavleen Singh is a very well-known journalist. I know who he is and you have made him a *persona non grata* in India. Thank you, Dr. Jaishankar. Mr. Aatish Taseer is a good novelist. You read one of his

books. His mother, Ms. Tavleen Singh is an Indian. …(*Interruptions*) He wrote a novel in Sanskrit. We do not do this hard line in India, Dr. Jaishankar.

I would also like to say that we did not believe Mr. Aatish Taseer. We said that Shri Modi cannot be a 'Divider-in-Chief'. What is happening now? I thought that his massive victory in the elections would go for passing badly-needed reforms to make it easier to build homes, to lay roads, and to create jobs in India. But Shri Modi and his Hanuman have spent the last six months in dividing India. Earlier, they used to say Standup India, Shutup India or whatever.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Chairperson, if I heard correctly, did he say, Modi and his Hanuman? What does that signify? …(*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Hanuman Ji. …(*Interruptions*) It means his right hand. …(*Interruptions*) Have you heard of the word 'Fifth Columnist'? We have a fifth columnist in our ranks. It does not matter. We shall fight on nevertheless. …(*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): They are more in Dum Dum area.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): We do not really care about fifth columnist. Now, what is happening? Dr. Jaishankar, his divisive action on CAA spoiled his and India's international image. In December, Shri Narendra Modi was forced to cancel a summit with the Japanese Prime Minister due to unrest in Assam. Bangladesh, one of India's closest allies, cancelled three-Ministerial visits to signal displeasure at the turn of events. The European Parliament is preparing a resolution on both Jammu and Kashmir and the Citizenship Act and they are opposing it. Let him stand up and controvert me. …(*Interruptions*) A billionaire philanthropist, George Soros, who is asking for capital, openly criticised Modi for creating a Hindu National State in his speech in Davos at the World Economic Forum on 23rd January.

(1545/RC/MY)

Sir, *The Economist* is a world renowned magazine. It is the most balanced magazine. I was speaking to a Nobel Laureate, Peter Thiel, the other day. He only reads *The Economist*. Now what did *The Economist* write? The headlines of its issue of January 23 said: 'India's 200 million Muslims fear the Prime Minister is building a Hindu State'. This is not by me or by Shri Adhir Ranjan Chowdhury but this is by *The Economist.* a most respected journal as Dr.

Jaishankar would confirm. It is the most respected magazine anywhere in the world …(*Interruptions*).

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR): Please read that editorial. Do not call it a balanced magazine. I do not confirm it.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): What is a balanced magazine? Tell me which a balanced magazine in the world is. The *Time* magazine is not balanced.

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): You are having only one minute. Do not unnecessarily waste time. Please address the Chair.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, what did *The Economist* say? It said that largely fawning media in India have begun to speak out against Shri Narendra Modi, the Prime Minister, for his apparent determination to transform India from a tolerant and a multi-religious place into a chauvinist Hindu State. That is what you are doing. It further stated that massacre of Muslims in the State of Gujarat in 2002 when Mr. Modi was Chief Minister, made him a hero in the minds of Hindu nationalists (Hindu Hridaya Samrat) around the country. I am not saying this. This is being said by *The Economist* magazine …(*Interruptions*).

HON. CHAIRPERSON: Please take your seat. Prof. Ray, you address the Chair. You wind up your speech.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): It further says that by undermining the secular principles of the Constitution, Mr. Modi's latest initiatives threaten to do damage to India's democracy that could last for decades. They are also likely to lead to bloodshed. This Government has nothing to say except head bashing Pakistan. Mr. Adhir was right. He asked whether Pakistan would roar like a lion in front of China. It becomes a whimper.

With such a divided India, will Foreign Direct Investment come to this country to remove our unemployment? Dr. Jaishankar, I will give you an example. There is a Company called KKR in the United States. *The Financial Times*, London, reported that KKR the biggest private equity firm in the world will not consider India for their core investment. You cannot have a divided India. Your own private investment is shrinking. One Ambani and one Adani will not be able to sustain this country.

When Mr. Modi came to power again in 2019, we were in minority sitting on this side and looking at the great man how he would transform India. He had no new slogans. No Swachh Bharat. No Start-Ups. No Prime Minister's Fasal Bhima Yojana. No Prime Minister's Kisan Samman Nidhi. There was only 'persecuted' and 'polarisation'.

(1550/SRG/CP)

मुसलमान को मारो, देश का भाग कर दो, विभाजन कर दो।...(व्यवधान)

Lastly, I end my speech with this small quotation from a song from Hindi movie `1942 – A Love Story'. Our path to democracy is difficult. The girls in Shaheen Bagh are sitting there in this hope that the Government will scrap this.

" ये सफर बहुत है कठिन मगर
ना उदास हो मेरे हमसफर,
दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है,
लम्बी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है।"

It is only the evening. Nothing will change. ...(*Interruptions*). With this, I again oppose this. I really expected Mr. Modi to be here today. I spoke to the hon. Speaker. But he has no time to attend the Parliament. He only had Barack and he had Donald and all these people. We are just MPs ...(*Interruptions*). Why should he come and waste his time listening to us? ...(*Interruptions*) Minister Arjun Munda has also got up and left. ...(*Interruptions*). In Bengal, Shri Dilip Ghosh spoke against us. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): I already called Mr. Jayadev's name. please conclude in one second.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Shri Dilip Ghosh became MP and left his MLA seat. In the by-election held for that seat, BJP lost by 24000 votes. It proves that the BJP does not exist and will not flourish in West Bengal. ...(*Interruptions*)

With these words, I conclude.

(ends)

1552 hours

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address. Let me start by saying that this is the eighth consecutive Budget that the people of Andhra Pradesh have had to face disappointment. AP has been in a crisis mode for more than ten years. Even before the bifurcation with all the Telangana agitation etc. for more than 10 years, our State has been in crisis mode. We are not in a position to envision our future due to the continuing uncertainties. We are constrained to focus on our State issues and do not even have the luxury to participate in the dialogue about the nation as a whole when our State is suffering and on the brink of economic collapse.

On top of the challenges being faced due to unfair bifurcation, our State was victimized. We are also facing lack of promised support from the Centre in not fulfilling the provisions of the AP Reorganization Act in full. Further to that, due to the illogical and irrational decisions taken by the new Government, our State which was among the top performing States in the country with double digit GSDP growth and leading in industrial investments, in infrastructure development, is now on the brink of economic collapse. The fall in tax revenue collection in the State is one of the highest in the country and over Rs. 1.8 lakh crores worth of investments have been withdrawn from the State. The decision to scrap PPAs has brought the reputation of the State and the country as an investment destination into question with countries threatening legal action.

Among the many challenges we are facing the most burning issue is the decision of the AP Government to split the capital into three pieces, moving the executive capital to Vishakhapatnam, the legislative capital to Amravati and the judicial capital to Kurnool …(*Interruptions*). What is this? I seek your intervention. I seek your protection. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except Shri Jayadev Galla's speech.

… (Not recorded)… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Take your seats.

… (*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Among the many challenges we are facing, the most burning issue is the decision of the AP Government to split the capital into three pieces. They want to move the executive capital to Vishakhapatnam,

leave the legislative capital in Amravati, and move the judicial capital to Kurnool. …(*Interruptions*)

(1555/RU/NK)

The Acts to repeal the CRDA Act and decentralise the governance have been approved by the Cabinet and passed in the Assembly. They are pending in the Legislative Council as the Chairman has sent them to Select Committee. Now the YCP Government wants to abolish the Legislative Council in order to subvert the democratic process. Just imagine a situation that the Central Government decided to move the Parliament to Hyderabad and move the Supreme Court to Trivandrum and also decided to abolish Rajya Sabha in order to get it passed. This is the situation being faced by the people of Andhra Pradesh now.

We have the Rajasthan Legislative Council Bill, 2013 which was sent to the Steering Committee. One of the suggestions that the Committee took into consideration is:

> "There is a need to evolve a national policy consensus with regard to creation/abolition of Legislative Council particularly in regard to the fact that the status of the second chamber cannot be temporary in nature depending on the mood of the Government of the day nor can be abolished once created, only at the whims and fancies of a newly elected Government in the State."

This Bill came up in 2013 and because of lack of a national consensus, Rajasthan is yet to have a Legislative Council. You can imagine the seriousness of the decision to abolish the Council.

Coming back to Amaravati, I would like to thank the Minister of State for Home Affairs, Shri Nityanand Rai for his response to my Unstarred Question yesterday in which he stated that the Government of Andhra Pradesh had notified Amaravati as the capital of Andhra Pradesh through a GO on 23.4.2015 and it is for each State to decide its capital – and not capitals – within its own territory.

This means that Amaravati has been decided as the capital of the State of Andhra Pradesh as a GO in this regard has been issued and has been recognized by the Centre. It is very clear by the hon. Minister's statement. But this is not only a State issue but it is also a national issue.…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Shri Jayadev Galla, please remember that you are speaking on the President's Address. So, kindly confine yourself to that subject.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): The bifurcation of Andhra Pradesh was done through an Act of Parliament, the AP Reorganisation Act. The need for a new capital arose because of the bifurcation of Andhra Pradesh. So, this is not a normal case. An Act of Parliament has created a State and that Act of Parliament also commits the Central Government to provide funding and assistance to establish a capital, not three capitals, which should include an Assembly, a Secretariat, a High Court and a Raj Bhavan. It also says that the Central Government should provide connectivity by road, by air, and by rail to the capital. If we have three capitals, will the Central Government fund the development of infrastructure and connectivity to all the three capitals? Will the Central Government provide connectivity to three capitals? Will the Central Government give us funding and connectivity to three cities when we are struggling to have connectivity even to one capital? This is a ridiculous idea.…(*Interruptions*)

The people of Andhra Pradesh brought YSRCP into power based on the promises during the elections and the areas of focus mentioned in their election manifesto. They promised that if elected to power, they would get special category status for Andhra Pradesh. Let them concentrate on that. Nowhere had they mentioned the idea of splitting the capital and moving it away from Amaravati. In fact, the leaders of YSRCP during election campaign have made statements denying that there was any thought of shifting the capital if they come to power.…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Please speak on the President's Address. All along, you have speaking on State matters and it will create controversies. Please confine yourself to the President's Address.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I am allowed to speak anything under the President's Address. Yesterday, hon. Speaker also said that in the discussion of the President's Address, we can speak anything. Hon. Speaker has said so.…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): It will create controversy. The decisions taken in the Assembly of the State cannot be questioned here. Any decision taken in the State Assembly cannot be questioned in the Parliament. Please have it in your mind. You are a learned person.

… (*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I am not questioning it.

(1600/NKL/SK)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I am only giving the background of it. I am not questioning. …(*Interruptions*) It is coming to Parliament also. …(*Interruptions*) The AP Reorganisation Act is an Act of Parliament. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please do not waste your time. Please be restricted to the Motion of Thanks on the President's Address.

… (*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, the current CM in the Assembly in 2014 had welcomed the idea of developing Amaravati as the Capital. …(*Interruptions*) The decision is a clear violation of the mandate. …(*Interruptions*)

Sir, the Government had commissioned GN Rao Expert Committee and the Boston Consulting Group to come out with reports on how best decentralised development is possible in the State. They had come out with reports supporting the Government's three capital approach for decentralised development. But these reports have no sanctity and no credibility. Let me clarify this. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please take your seat.

…(*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Before the reports were released, *… (Not recorded)* made statements in the Assembly regarding the three Capital idea, and a few weeks later, the reports came out supporting this view. This clearly shows that the GN Rao Committee Report and the BCG Report were influenced by the statements of the *… (Not recorded)*, and I repeat that they have no sanctity and no credibility. …(*Interruptions*)

Sir, moving the executive branch of the Government to the most developed city in Andhra Pradesh is not decentralised development. …(*Interruptions*) Decentralised development means delegation of powers to Districts and Local Bodies. It does not mean splitting the three branches of the Government into three cities. Three Capitals will mean three times the cost and 1/3rd the efficiency. Taxpayers will fund nine times the Government overspend for generations to come, if they go through with this idea. …(*Interruptions*)

Sir, there is a clear consensus among the expert community around the country that splitting the executive and legislative, and locating it in two different cities is impractical. …(*Interruptions*) They were categorical that this move would create unnecessary problems and lead to wasteful expenditure. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please take your seat.

Mr. Jayadev, I am again telling you that any decision taken in the State Assembly cannot be mentioned here. It is the will of the State Assembly. We cannot interfere. Please be restricted to the Motion of Thanks on the President's Address. Otherwise, I will call another hon. Member.

… (*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, the hon. Speaker himself said that we can speak anything in it. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Rest of the hon. Members, please take your seats.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will take care of that. Please sit down.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, this is not good. Please take your seat. You address the Chair. Rest of the hon. Members, please take your seats.

… (*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I would like to share the views mentioned in the article. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You please come to the main point.

… (*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, in the media, there have been articles that have come out during the last two weeks. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir I have a little more time to speak. They have been disturbing me. Please give me some consideration. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: If you will all along be speaking about the State Assembly, then I cannot permit you.

… (*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, *The Organiser*, on January 25th, 2020 came out with an article named *… (Not recorded)* …(*Interruptions*) *The Financial Express*, on 24th January, came out with an article. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. Nothing will go on record.

…(Interruptions) …(Not recorded)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Jayadev, nothing is going on record.

…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your mic is off. Why are you speaking?

…(*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): The *Times of India*, on 21st January, 2020, came out with an article named *… (Not recorded)* …(*Interruptions*). *The Hindu* on 21st December, 2019 came out with an article named *… (Not recorded)* …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: That is not on record. Do not worry. Please sit down. That is not on record. We have already deleted it. Please sit down.

…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please come to the point, and conclude shortly. You have already taken seven minutes.

…(*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I have a little more time to speak. I was told that I have been allotted ten minutes to speak. …(*Interruptions*) I need some more time, Sir.

HON. CHAIRPERSON: You spoke for more than ten minutes. Please conclude now.

…(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Rest of the hon. Members, please take your seats. I will take care of anything unparliamentary.

…(*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Now, I come to the point of legal, moral and ethical angle. This is a part of the AP Reorganisation Act. It has created our State and put us in a situation where we need to create a new Capital. …(*Interruptions*) The Centre has a commitment to develop that Capital. Any deviation from the AP Reorganisation Act will need an amendment from the Parliament. They have to amend the Act, Sir. That is one thing we need to keep in mind. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, 29,000 farmers have donated 34,000 acres of land based on a master plan that was notified by the Government.

(1605/MK/KSP)

Only then they entered into an agreement with the Government of Andhra Pradesh. So, if they are going to scrap the APCRDA Act, how can they compensate the farmers? …(*Interruptions*)

Sir, there is also the question of democratic and human rights. There has been no sensitivity.

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): I am calling the next Member now. Please take your seat. Shri Hanuman Beniwal.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except Shri Hanuman Beniwal's speech.

…(Interruptions) …(Not recorded)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): Mr. Jayadev, I reminded you repeatedly not to speak on State issues. But you are speaking on the same subject. You are not moving away from that. What can I do?

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, please allow me to conclude my speech.

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): I am allowing you only one minute to conclude your speech. But do not speak on State issues.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI A. RAJA): I request other Members to take their seats.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I would like to say just two things before concluding.

The Capital model being planned by the current Andhra Pradesh Government is not only going to create a burden on the tax payers for generations, but the National Green Tribunal in its verdict on 20th November, 2017, while saying that Amaravati Capital Region does not fall under the flood prone area also said the large scale of the project has already been executed at huge public expense and any prohibitory direction at this stage would not only jeopardize the financial interest of the State, but would even become a serious environmental issue, capable of degrading the environment and ecology of the area to the disadvantage of the public interest as well.

(ends)

1607 बजे

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सभापति जी, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

1607 बजे (डॉ. किरीट पी. सोलंकी पीठासीन हुए)

पांच साल के अंदर प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यह देश जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा और हमारे पड़ोसी मुल्क जिस तरह से आय दिन दादागिरी करते थे, बार्डर पर कई तरह की घटनाएं करते थे, मोदी जी के आने के बाद भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। हाउडी मोदी कार्यक्रम से अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारत से नजदिकियां बढ़ाने लगे हैं। एक जमाना था जब कांग्रेस के शासन में प्रधान मंत्री मिलने जाते थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति उनको टाइम भी नहीं देते थे।

प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रवाद की भावना इस देश के कोने-कोने में जगाई। हर व्यक्ति अपने आप को भारतीय कहने में गौरवान्वित महसूस कर रहा है। देश में नार्थ ईस्ट की सबसे बड़ी समस्या थी। नार्थ ईस्ट के अंदर, चाहे भारत-बंग्लादेश संबंध सुधारने की बात हो या आतंकवाद, अलगवाद, जो इस देश के अंदर लंबे समय से फल-फूल रहा था, इस देश के अंदर भाषावाद, जातिवाद जो लंबे समय से फल-फूल रहा था, इस देश को एक डोर और एक छाते के नीचे लाने का प्रयास किया। नार्थ ईस्ट से लेकर तमाम इलाकों को, हिन्दी भाषी क्षेत्रों को, साउथ के राज्यों को, सबको एक साथ लाने का काम प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। पांच साल के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जो अंतिम छोर पर बैठा है, किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि एक ढाणी के अंदर बिजली लगेगी। उज्ज्वला योजना से प्रत्येक व्यक्ति के घर में बिजली पहुंचाई। आयुष्मान भारत योजना से देश के करोड़ों लोगों को फायदा हुआ और गरीबों का इलाज हुआ।

देश के किसानों के लिए छ: हजार रुपये किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खाते में डाले गए। इस बार उसको बढ़ाकर आठ हजार रुपये कर दिया गया। प्रधान मंत्री जी ने देश के प्रत्येक किसानों के लिए सोचा, बातों और जुमलों से टाईम पास नहीं किया। इन्होंने परिवर्तन किया, इसलिए इस बार पूरी मेजोरिटी प्रधान मंत्री जी को मिली।

आज नार्थ ईस्ट के अंदर जो हालात हैं, असम के अंदर जो सबसे बड़ा काम हुआ है, असम के अंदर जो बोडोलैंड की डिमांड कर रहे थे, उन बोडो भाइयों को साथ बैठाया।

(1610/YSH/KKD)

उनके हथियारों को सरेंडर करवाया। असम के साथ-साथ जहां पर चार हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी वहां पर सरकार की मध्यस्थता से त्रिपुरा और मिजोरम की ब्रू जनजाति का हल निकाला गया। नार्थ ईस्ट अलग-थलग पड़ा था। हम दिल्ली से नार्थ ईस्ट में जाने से डरते थे, वहां पर कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। उन्होंने वहां पर रेलवे कनेक्टिविटी की व्यवस्था की। मेघालय और अरुणाचल में नए एयरपोर्ट बनाए। इस वर्तमान सरकार ने नार्थ ईस्ट को नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया है। बंग्लादेश में जहां पर भारत पाकिस्तान का बोर्डर है, वहां पर फेसिंग की गई। इसी तरह से बंग्लादेश के पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग का काम चल रहा है। हम डिफेंस कमेटी में हैं। सभापति महोदय, हम बोर्डर पर भी गए थे। नाथूला और जितना भी इलाका चीन से लगता है, वहां पर हमारे सैनिक पूरे जज्बे और जोश के साथ खड़े थे। हमें चीन से कोई खतरा नहीं है। भारत सुरक्षित है। आज चीन भी भारत के साथ नजदीकियां बढ़ाने के लिए मजबूर हो गया है।

सभापति महोदय, पिछले सात महीने के अन्दर जो बिल लाए गए, चाहे तीन तलाक का बिल हो और निश्चित रूप से मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कानून बनकर आया और उनको सम्मान मिला। चिट फंड संशोधन कानून, ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को अधिकार देने वाला कानून और सबसे बड़ा कानून धारा 370 और 35 ए, जिसके नाम से कांग्रेस पार्टी डराया करती थी, वह भी आया। श्रीनगर के अन्दर लाल चौक में लोग झंडा फहराने से डरते थे। लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश घोषित किया। जम्मू कश्मीर को अलग केन्द्र शासित प्रदेश करके अब वहां पर केन्द्र के पास से अरबों-खरबों रुपये जाएंगे। उन्होंने इस देश को एम्स के अस्पताल दिए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सुनने का काम किया।

सभापति महोदय, सबसे बड़ा जो काम किया है, वह यह है कि सीएए के अन्दर उन तमाम लोगों को, चाहे वे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से हों या हिंदू, बौद्ध या पारसी के अल्पसंख्यक हो, जिनसे जबर्दस्ती धर्मांतरण करवाया जाता था, वहां पर हमारे मंदिर तोड़ दिए गए थे, वहां पर लोग परेशानी में थे। कश्मीरी पंडितों को काफी सालों पहले वहां से निकाल दिया गया। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे तो कश्मीरी पंडितों, बोडोलैण्ड की और उल्फा की बातें सुना करते थे। अगर उन सभी को किसी ने समाप्त किया है और एक संविधान और एक कानून का किसी ने काम किया है तो वह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। हम इसके लिए अमित शाह जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हिन्दुस्तान के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को हिन्दुस्तानी कह रहा है। नार्थ ईस्ट के अन्दर बैठा व्यक्ति भी हमें भाई समझता है। आपने इस देश को जगाने का काम किया है। सीएए लाने के बाद लाखों परिवारों को, जो अपने आपको को घुसपैठिये समझते थे, उन्हें लगता था कि ये कब यहां से निकाल दें, आपने उन्हें नागरिकता देने का अधिकार दिया है। यह निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम है। यह इतिहास के अन्दर लिखा जाएगा और थोड़े बहुत लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। 8 तारीख को दिल्ली का चुनाव भी है। कुछ तो अखबार की सुर्खियों में आने के लिए वेल में आ जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। दिल्ली के चुनाव में आप पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुल रहा फिर कांग्रेस वाले इतने खुश क्यों हो रहे हैं। कांग्रेस का उसमें कोई काम नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आज कहना चाहूंगा कि देश के प्रधान मंत्री जी जिस हिसाब से चल रहे हैं, कांग्रेस पाटी ने 50-55 साल में जो खड्डे खोद दिए थे, उनको भरने में समय तो लगेगा। अभी और समय लगेगा। देश का किसान और देश का जवान इनके साथ खड़ा हुआ है। सभापति महोदय, किसानों की आय कैसे दुगुनी की जाए इसके लिए प्रधान मंत्री जी चिंतित रहते हैं। मीटिंग के अन्दर मामले उठाए जाते हैं। वे चिंतित है कि किसान की आय बढ़नी चाहिए। सन् 1950 के दशक में जीडीपी में कृषि की भागीदारी 52 प्रतिशत हुआ करती थी। वह आज घटकर 16 प्रतिशत रह गई है। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी का और कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी पूर्णतया लागू किया जाए ताकि देश के किसान को बचाया जाए। आय-व्यय मूल्य का अधिकार विधेयक यहां पर लाया जाए ताकि देश के अन्नदाता को बचाया जाए, जो 70 साल से देख रहा है कि कोई आएगा और हमारी सुध लेगा। सभापति महोदय, आजादी के 70 सालों बाद हजारों किसान कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या कर रहे हैं। किसान के बेटे नौकरियों के अभाव के कारण हाथ में बंदूकें लेकर अपराध की दुनिया के अंदर जा रहे हैं या फिर फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से मांग करता हूं कि तीन सालों में और पिछले 10-15 सालों के दौरान तीन लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है तो कर्जमाफी

पर नए सिरे से दिल्ली की सरकार को सोचना है कि किसान को किस तरह से बचाया जाए। यह हमारा सरकार से निवेदन रहेगा।

(1615/RPS/RP)

जो 2018 के आरबीआई के आंकड़े हैं, वे बताते हैं कि दस सालों में अलग-अलग राज्यों में करीब 2.21 लाख करोड़ रुपये के कर्जे माफ किए गए, वहीं पिछले 15 सालों में धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया गया।

सभापति महोदय, मैं अब राजस्थान पर आता हूं। अभी वहां टिड्डी का बहुत बड़ा प्रकोप हुआ। टिड्डी से राजस्थान के 11 जिलों में नुकसान हुआ है। कल भी हमने बात की थी, अर्जुन मेघवाल जी ने जवाब भी दिया था। वहां टिड्डी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब की फसलों का नुकसान हुआ है। राजस्थान की 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की फसलें नष्ट कर दीं और 60.77 लाख हेक्टेअर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब पाकिस्तान से टिड्डियों का दूसरा दल आ रहा है, ऐसी सूचना मिल रही है। इसमें गुजरात की सरकार ने सहयोग किया और टिड्डी पर कंट्रोल हो गया, लेकिन पंजाब और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं, वे सहयोग नहीं कर रही हैं। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि प्रधान मंत्री जी ने एनडीए की मीटिंग में और आल पार्टी मीटिंग में भी कहा था, हमने रिक्वेस्ट की थी कि यहां से एक दल जाए, हमारे मंत्री जी भी जाएं।...(व्यवधान) सर, मुझे एक-दो मिनट बोलने दीजिए। ...(व्यवधान) मेरा यही निवेदन है कि टिड्डी के मामले में यहां से एक दल जाए, पहले अधिकारियों का दल जाए। माननीय मंत्री जी, अर्जुन मेघवाल जी यहां बैठे हैं, आपके जिले में भी टिड्डी आई है, मेरे जिले में भी आई है। उसके बाद कृषि मंत्री जी को लेकर आप भी वहां जाएं। आप तमाम मंत्रियों को लेकर, सांसदों को लेकर वहां जाएं।...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): मैं आपको बताना चाहता हूं कि केन्द्र का एक दल आज टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच गया है। आपके क्षेत्र में भी, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर आदि सभी जगहों पर आज सुबह ही वह दल पहुंच गया है। जितना भी होगा, केन्द्र सरकार किसानों की मदद करेगी, तत्परता से करेगी।

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सभापति महोदय, मैं वहां का सांसद हूं, मैं वोट बैंक की खातिर नहीं लड़ता हूं। मैंने खुद एक रीजनल पार्टी बनाई, प्रयास किया और देश हित में प्रधान मंत्री जी को सपोर्ट किया और हमारा सपोर्ट बना रहेगा। प्रधान मंत्री जी को हमेशा हमारा समर्थन रहेगा। मैं यहां घोषणा करता हूं कि अपना एक महीने का वेतन प्रधान मंत्री राहत कोष में दूंगा। मुख्य मंत्री राहत कोष में इसलिए जमा नहीं कराउंगा कि पता नहीं मुख्य मंत्री वहां देंगे या नहीं। मैं प्रधान मंत्री राहत कोष में एक महीने का वेतन देता हूं। अगर हम एमपीलैड्स का पैसा इस काम में ले सकें तो एक करोड़ रुपये तक दे सकता हूं। मैं सभी से अपील करूंगा, राजस्थान के सांसदों से और जहां-जहां टिड्डी आई है, वहां हम लोगों को शुरुआत करनी चाहिए। इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य इससे प्रभावित हैं। यह समस्या तो बढ़ेगी, आपको इसका स्थायी समाधान ढूंढना होगा। दो-ढाई महीने पहले जब राजस्थान के अंदर टिड्डी दिखी थी, तब सचेत कर दिया गया था, लेकिन राजस्थान की सरकार, राजस्थान में चूंकि कांग्रेस की सरकार है, वहां पर मुख्य मंत्री खुद परेशान हैं।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान की दो-तीन बातें कहूंगा। राजस्थान के अंदर आज हालात ऐसे हो गए हैं कि पंचायत चुनाव नहीं हुए। चार चरणों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। चौथे चरण की लॉटरी कल खुली

है, प्रधान-प्रमुखों के चुनाव होंगे या नहीं होंगे। प्रधानों-सरपंचों के खातों में पैसा दिल्ली से आ गया है, लेकिन खर्च नहीं हो रहा है। राजस्थान में मंत्री और अफसर रोज आपस में लड़ रहे हैं कि यह इस खेमे का है, वह उस खेमे का है। रोज शिकायत हो रही है और इसी बात की अखबारबाजी हो रही है। बेरोजगारों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है।...(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी चुरू के अंदर छोटी बालिकाओं के साथ गैंगरेप की घटनाएं हुई हैं, मैं एक मिनट में क्वोट कर देता हूं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी): अब आप समाप्त कीजिए।

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सभापति महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

दस वर्षीय बालिका के साथ चुरू में दुष्कर्म की घटना हुई, पत्थर से पीटकर उसे मार दिया गया। 16 जनवरी, 2020 को सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ, कोटा में 17 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार हुआ, टोंक में 1 दिसम्बर, 2019 को छ: वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ। चुरू, बनीपुर में 29 नवम्बर, 2019 को, झालावाड़ के अंदर 24 नवम्बर, 2019 को आठ वर्षीय बालिका के साथ, जयपुर में सात वर्षीय बालिका के साथ ऐसी घटनाएं हुई। थाना गाजी का दलित युवती का वीडियो, जो देश में वायरल हुआ, उससे राजस्थान शर्मसार हो गया, देश शर्मसार हो गया। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, वहां सांसद सुरक्षित नहीं हैं। ...(व्यवधान) सांसद जाते हैं लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए, वहां राजस्थान के मुख्य मंत्री के इशारे पर उन पर पत्थर फेंके जाते हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपके 12 मिनट्स हो गए हैं, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सभापति महोदय, मैं एक ही निवेदन करूंगा और आधा मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

माननीय सभापति: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सभापति महोदय, रोजगार के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए केन्द्रीय युवा बोर्ड का गठन हो। जिस तरह से महिला आयोग बना है, उसी तरह युवाओं के लिए भी आयोग बने। बेरोजगारी की समस्या के ठोस समाधान के लिए प्रधान मंत्री जी को चिन्ता करनी चाहिए। हम सब मोदी जी के साथ हैं, देश साथ है। इन सीएए विरोधियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, इनकी संख्या सिर्फ इतनी सी है और हम इतने लोग हैं। धन्यवाद।

(इति)

(1620/RCP/RAJ)

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी): मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि पांच मिनट में अपनी बात को समाप्त कीजिए।

श्री अच्युतानंद सामंत जी।

1620 बजे

श्री अच्युतानंद सामंत (कंधामल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा 31 जनवरी, 2020 को दोनों सदनों को संयुक्त रूप से उनके संबोधन के लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह संबोधन एक नए भारत को बनाने की आकांक्षा प्रस्तुत करता है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए यह एक प्रेरणा है। इस दशक और शताब्दी को भारत का दशक और शताब्दी बनाने के लिए एक महत्वकांक्षा है। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में गांधी जी, अम्बेडकर जी, लोहिया जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों का उदाहरण दिया है, उनके शिक्षा की व्याख्या की है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। कोई भी विशाल भवन सिर्फ इमारत में महान नहीं बनता है, वह अपनी नींव पर विशाल बनता है। हमें वह नींव अतीत से ही मिल सकती है।

I would like to raise a few points which, I wish, would be covered and improved upon. The hon. President spoke about the Government's focus on the poor, Dalits, women, youth, tribals, minorities and divyangjan. When this is highly laudable, the implementation at the grass-roots level and the actual impact is yet to be seen as promised. Practically, for the benefits to reach them takes time and empowerment does not come so easily.

The hon. President of India highlighted the importance of the Preamble, the democratic fabric of our nation. Here, I would like to reiterate the demand of our hon. Chief Minister regarding inclusion of the term 'non-violence or ahimsa' in our Preamble which is the key to our Constitution.

India commemorated the 150th Anniversary of Pujya Bapu. This will be a great tribute to the Father of the Nation as rightly told by our hon. Chief Minister.

I would like to raise some genuine concerns from Odisha on behalf of our Party, Biju Janata Dal. He touched the point of building Natural Disaster Resilient Infrastructure. But there was no mention about 'Special Focus State' status to be given to Odisha, given our State's experience of facing repeated natural disasters and fighting back every single time. Even I can cite the Report of the hon. Chairman of the 15th Finance Commission, respected N.K. Singh *ji* who has expressed in his report that Odisha faced highest natural calamity in the entire country among all the States. Even the Report highlights and praises Odisha. It should be given adequate waivers, financial assistance and compensation to face natural calamity as Odisha is most prone to natural calamities.

Farmers are the backbone of the nation. If India is surplus in foodgrain production and maintains a huge buffer, it is because of the toil of the farmers. Many schemes of the Government aim at reducing the plight of farmers of selling the produce below the optimum rates but the fact remains that the middlemen take the benefit keeping the farmers languished. To add to it, we know that the first and foremost sufferers are the farmers in case any natural calamity happens, be it drought, floods or even pests. I believe, despite monumental efforts for their welfare, the reality is different. Their purchasing power is very limited. Until their purchasing power increases, poverty of the farmers cannot be alleviated. The crop insurance schemes and loan waivers also do not alleviate their pains and problems. Here, I would like to mention about KALIA scheme of Odisha aiming to improve their productivity and giving them an insurance cover, which is a long-term support to farmers. If farmers prosper, the country prospers.

(1625/SMN/VB)

Hon. President of India has highlighted archaeological sites. Five archaeological sites have been promised to be developed as iconic sites in this year's Budget. Our Odisha has a treasure trove of historical sites. It has not been given its due. History in our part looks ignored. It deserves mention. The State Government under the leadership of hon. Chief Minister Shri Naveen Patnaik Ji has agreed to cover fifty per cent of the financial assistance and give free land for the rail connectivity. Still the rail connectivity is progressing very slowly. This has to be accelerated because the idea of connected India where no region is left behind cannot happen without the Railways – the nerve centre of economy. In this regard, I can site an example of my own Parliamentary constituency Kandhamal which is not connected with the Railway till date which is the dream for the last 50-60 years.

HON. CHAIRPERSON (DR. KIRIT P. SOLANKI): Kindly conclude please.

SHRI ACHYUTANANDA SAMANTA (KANDHAMAL): Sir, please give me another two minutes. They have told me that I will get 6-7 minutes.

I reiterate the State's demands for an increase in the rates of royalty that the State Government should get from the cess collected on coal by the Central Government.

Similarly, Incredible India has a vast tourism potential. Odisha is also being explored as India's best place. Some iconic sites of Odisha should be considered and taken up for tourism development. It can boost the socio-economic development of the region.

Here, I would like to inform the hon. House that our hon. Chief Minister has taken all steps to give a new shape to heritage cities like Puri, Konark and Lingaraja Temple making Puri the cultural capital and Bhuvaneswar as the sports capital of India.

Both the Tele-density and banking density have to be increased in Odisha. People have to climb trees and high-rise structures to get mobile networks. In this context, I would like to state that my Kandhamal district which is an aspirational district, is without any telephone facilities or mobile facilities and also the banking facilities are inadequate.

Similarly, 112 districts have been declared as aspirational districts and many initiatives have been taken. However, things have to be geared up. I represent an aspirational district, Kandhamal, and I know the problems at the grassroots. Unless the initiatives from the Government and collaboration from the corporate world comes to these districts, it will never become inspiration from aspiration.

Similarly, five trillion-dollar economy is doable. But emphasis has to be given on social sector spending like education and health. I believe that the level of education and literacy of the country determines the economy of the nation. For our youth to be turned to be a demographic dividend and not turn out to be a disaster, quality education and skill training are the only solutions. The major challenge is the employment generation. The allocations made have been inadequate. Focus should be on more *hunar haaths* and skill development.

Lastly, Sir, we request for fiscal autonomy for the State. Our beloved Biju babu believed Odisha could transform into the most advanced State in South Asia with financial autonomy.

Thank you very much.

(ends)

1628 hours

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): It is an honour to get this opportunity to address this august House on such a significant occasion. I would like to bring to the notice of the House a few issues pertaining to my State as well as to the country.

As my colleague Mr. Jayadev had raised several issues regarding Andhra Pradesh, I would like to answer a few of his arguments.

Our hon. Prime Minister has come back to lead the country with a thumping majority which I believe and which most people believe was because of his right intention to take the country forward, his dedication and ability to take tough decisions.

But I have to remind the House, the same thing did not happen in my State of Andhra Pradesh. I understand that the Ruling Party's erstwhile partner from Andhra Pradesh, the Telugu Desam Party, broke up the alliance in 2013 on whimsical reasons thinking that NDA is not going to come back to power.

(*Interruptions*)*… (Not recorded)* went around the country parading himself as the champion of anti-Modi campaign. He tied up with the Congress Party in Telangana. He went to Bengaluru, Kolkata and Delhi trying to mobilise party against Modi ji.

(1630/MMN/PC)

HON. CHAIRPERSON (DR. KIRIT P. SOLANKI): Please do not mention names.

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): All right, Sir. *… (Not recorded)* even boasted on live TV of being instrumental in defeating the BJP in Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh. I understand the bad taste they may have left in you by all the backstabbing they attempted. As a consequence, I am afraid Andhra Pradesh is still facing the brunt of their unstable, unreliable and conniving behaviour from the past. I am surprised how *… (Not recorded)* is making his three MPs cosy up to the Ruling Party and dumping his current partners who happen to fall in the Opposition. The TDP has not only betrayed the House but also the State as well as the people of Andhra Pradesh in a similar fashion.

They took our debt from Rs.70,000 crore to a whopping Rs.2.5 lakh crore in five years. They left almost Rs.60,000 crore unpaid bills. They spent Rs.30,000 crore on the last day before election trying to fool people in the name

of freebies. In the name of world-class capital, they planned to centralize development in one particular pocket serving themselves with a plan to amass personal wealth. They acquired 4,000 acres of land, announced that, that was the region where the capital was going to be built and declared all the surrounding areas as green belt. Then, their masterplan was to make more than Rs.1 lake crore from the 4,000 acres of land they acquired with insider information. Our people did not buy into this deceit.

I have to remind the NDA that the old guard was thrown out. A new Government was formed under the YSRCP which I am proudly representing, led by a young dynamic Chief Minister, Shri Jagan Mohan Reddy Garu who won 151 out of 175 MLA seats and 22 out of 25 MP seats. I also have to bring it to your attention that YSRCP has unconditionally travelled with the Treasury Benches since the last few months. We have voted with you for the Triple Talaq Bill; we have voted with you to remove Article 370; and we have voted with you on CAA. We justified these controversial Bills back home all by ourselves. But the general feeling within our State about Delhi is not very positive at the moment. We still feel neglected and ignored as a State.

I have to bring to your attention as to how passionately my Chief Minister is implementing poverty alleviation programmes, taking governance to the doorsteps by employing lakhs of volunteers and village level Secretariat employees. He is also working on decentralizing development by focussing on backward areas--let it be Rayalaseema or North Coastal Andhra Pradesh--unlike the earlier Government which wanted to put all their eggs in their basket.

This is my personal favourite idea which I think the whole country needs to implement. He made a law to bring 50 per cent reservation in nominated posts for BCs, SCs, STs, minorities and women. …(*Interruptions*) Sir, I have more than 10 minutes time. For the first time since Independence, there is a BC District Cooperative Bank Chairman in my district. For the first time there is a Muslim Agriculture Market Committee Chairman in my area. For the first time, there is going to be a woman who is going to be the Chairman of a famous Hanuman temple in my parliamentary constituency. The so-called underprivileged classes are finally getting the much needed social upliftment within our communities or within our villages. I understand we had reservation for the past 70 years but that benefitted people who wanted to get educated, get jobs and leave the

villages but currently, for the first time, within our communities, we see the real social upliftment which was much needed for the last 70 years. The YSRCP is effectively making dreams come true of Dr. Baba Saheb Ambedkar and Mahatma Gandhi Ji.

I now demand more attention to our State. I now demand justice to our State. I now demand that all outstanding dues, which are owed to our State, be cleared. You all must be aware of how unfairly our State has been treated in this very House. I request the Government under the leadership of our hon. Prime Minister, Narendra Modi Ji, to make up for all the shortcomings our State has faced under the previous Government.

(1635/VR/SPS)

Speaker Sir, in addition to these, I am excited about the 5 trillion Dollar economy, we are talking about. I am also excited about the doubling of farmers income. My segment is 90 per cent farming dependent and I would like more clarity on the path to achieving the double income. I have not seen any action plan on achieving this target. Irrigation projects could help us in the long run. I would like the Central Government to assist our Government to complete some our lifeline irrigation projects besides timely funding of Polavaram as promised.

Efforts to identify and create demand for agriculture produce should be a priority. Five years ago, a tonne of eucalyptus was about Rs.5000. For past few years, it has been still struggling at around Rs.2000. Farmers, who have grown eucalyptus for last three years, are in deep distress, unable to get enough money even for harvesting.

The price of paper is down because people are shifting from paper to plastic, which is a lot cheaper, in spite of all the pollution around it. The Government has to step in and regulate to control pollution on one side and to replace it with products made with agriculture produce.

As an example, I suggest a complete ban on plastic plates, plastic glasses and plastic table rolls, which have no safe way to be disposed of. The ban will create a demand for agriculture produce pushing up prices for farmers.

There was an earlier proposal for a National Oil Mission to increase oil seed production within the country to reduce imports. But I see no mention of it in the President's Address or the Budget. A long pending request for Minimum Support Price (MSP) on oil palm bunches as suggested by the Commission for

Agricultural Costs and Prices (CACP) is still awaited. I seek clarity on the National Oil Mission and if it will find a place as part of doubling farmers income.

HON. CHAIRPERSON (DR. KIRIT P. SOLANKI): Please conclude in one or two sentences.

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): Sir, I am concluding it in one minute.

We heard of big numbers for the next few years in infrastructure. I hope we have clarity on how the money is to be distributed across the country. Andhra Pradesh needs it and is ready to deploy it on infrastructure. Upgradation of the 500 kms Buckingham Canal, the freight Canal from Pondicherry to Kakinada is long overdue after the foundation stone has been laid by our hon. Road Transport and Highways Minister, Shri Nitin Gadkari.

A new railway line of just 70 kms from Kovvur to Bhadrachalam, which passes through backward regions including regions of SC/ST population is long overdue. ....(Interruptions).

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. Thank you.

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): It reduces travel time by two hours from Visakhapatnam to Hyderabad, Bhubaneswar to Bangalore, Bhubaneswar to Mumbai saving a lot of money for the railways. ....(Interruptions)

Finally, I hope going forward the Government can give the much needed helping hand to Andhra Pradesh to achieve our common goals of equitable distribution of wealth and social justice.

I gladly support the Motion of Thanks. Thank you.

(ends)

*डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी):

---

* Laid on the Table

1638 hours

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here to speak against the Motion of Thanks on the President's Address.

Sir, when injustice becomes law, resistance becomes duty. I believe that when I joined politics to be a part of an aspirational India, that together, whichever side we sit on, we would like to lead India, represent India to show the global world that we are truly a world leader. But where are we today? With a very heavy heart, I would like to say a few points which Prof. Sougata Roy talked about that India today, for the first time, since I remember at least clearly, is persecuted and completely polarised, and, you have not just polarised it politically, but this whole vision in India today, which is some new India, which I have never experienced and which is on caste and creed, has almost reached our homes.

I have seen that WhatsApp is a new way of communicating. We have groups of our college friends, school friends in WhatsApp and the entire nation is completely divided, whether you are on CAA, NRC or you are not. Then, yesterday, the hon. Home Minister, in his reply mentioned that he has not even thought about it or considered it. I think this is almost making you feel that this entire Government is hiding an agenda of the crisis that our economy is in and is trying to drive that entire attention on to something which is polarizing India, which is costing us dearly, because it is taking a huge beating internationally. So, it is going to hurt investments, it is going to hurt the nation.

(1640/SAN/MM)

It probably sounds very nice right now because I think, this Government does not look at the larger picture. They are so caught up and trapped in every State election that after winning 303 Lok Sabha seats, they still want to go into every State, and the State issue becomes a national issue and on the national issue, the entire country is in a mess. So, I urge this Government to please introspect because this is not about whether you sit on this side or that side because most of their policies in all the States have made them sit in the opposition and not on the Treasury Benches. So, I think that they really need to introspect what their magic theory or idea of politics is.

I oppose and I would like to say something about NRC. Most of my fellow Members have talked about it, but there are two or three points which I would

like to talk about. I am sticking completely to what has come in the President's Address. The point number 12 talks about the World Bank's Ease of Doing Business rankings. It is a wonderful thing if we have done well, but there are a few things I would like to point out. The President's speech has talked five times about index and how well we have done in various indices. There are a few of them which I would like to point out.

When in the Ease of Doing Business Index, we have done well, why are the investments not coming? This is my humble question to this Government. I will give you small examples. In the Traffic Index, in 2019, four of Indian cities are on the top for most congested and polluted cities. In 2009, in the Democracy Index, India has slipped. In Mobility Index, India is at the 76th place out of 82. In the Passport Index, which this Government goes on praising itself about, India has slipped ten positions to 84. In respect of global hunger, which is absolutely dear to my heart, India now ranks 102 out of 117 countries. It slipped by nine positions. I think, this is what it is. I remember that during the Question Hour, the hon. Minister was giving us some data of how well we are doing in Millennium Development Goals, but this is in complete contradiction.

There is another point and Mr. P.P. Chaudhary was talking about ranking. There is another one which is a good programme of this Government. This is about e-unique identification of the divyangs. It is a very good project. The constituency which has benefitted the most in this Government is probably mine. I am proud to say that I rank number one in the country in respect of this particular programme despite being in the opposition because we managed to implement it well and the administration clearly helped us at that time. At that time, we were in the opposition and not a part of the Government in the State.

Even in case of e-unique identification, there is a huge problem because for every divyang who goes there, there is no infrastructure. Even if the hon. President's speech says that it has done well in India, it is not implemented well at all. It needs a huge improvement. I will not take the time of the House, but I want to put it on record.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): If the State Government does not support, how can we do it?

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I come from Maharashtra where you are not in power any more and if we have ranked first in the country, I am happy to tell you that we are ahead of Varanasi also. Compass data speaks for itself. Please check your own data. …(*Interruptions*) We will do even better.

The point number 42 of President's Address talks about MSP. I would like to bring some of these data to your knowledge. The recommendation for *dhan* is Rs. 3,251. What the Kendra Sarkar is giving is Rs. 1,550. So, there is a difference of almost Rs. 2,000. There is same thing about *kapass*. कपास का रिकमण्डेशन 7,204 है और केन्द्र सरकार 4,320 दे रही है। सोयाबीन का 9,000 का रिकमण्डेशन है और केन्द्र सरकार 4,000 दे रही है।

I would like to request the hon. Finance Minister, who happens to be here, in this regard. There is always a huge struggle between the Agriculture Ministry and the Finance Ministry. Every time I speak here, I am blessed and lucky that the hon. Finance Minister is here. She and I have had a run-in on the onion issue. Again, the onion issue has come up again. I think, our destinies are tied to it.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): She does not eat onion.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): That is okay. It does not matter. She was very kind that day. I do not think that she meant it the way the media interpreted it. I think, I would like to stand up for her there.

प्याज का दाम इस बार पूरा घट गया है। I request the hon. Finance Minister to request her colleague in the Commerce Ministry that the export of onions is a must. We lost an opportunity six months ago and this is another golden opportunity for your Government to help the farmer. You keep talking about doubling the income of farmers. उन्होंने अपनी बजट स्पीच में बोला है लेकिन हुआ नहीं है। (1645/RBN/SJN)

So, I would request you to intervene in that. That would be a great help for all these people.

A lot has been said about the foreign policy. I won't get into it because Prof. Roy spoke about it at length.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : आपके यहां प्याज के संबंध में क्या हुआ है?…(व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती) : वे बोलते हैं कि एक्सपोर्ट अलाऊ करिए।…(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : हम लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। अभी तक बाजार में क्या हुआ है, आप जानते हैं कि बीच में प्याज 120-150 रुपये तक चला गया था। हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा था। लेकिन हमने जितना इंपोर्ट किया...(व्यवधान) नतीजा यह हुआ कि उसको राज्य सरकारों ने लिया ही नहीं है।...(व्यवधान) अभी तक 41,000 टन में से सिर्फ 1,600 टन राज्यों ने लिया है। बाकी प्याज के सड़ने का डर भी रहता है। इसलिए, यह बात सही है। चूंकि बोइंग सीज़न लेट से चला था, तो अब प्याज मार्केट में आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक दाम हमारे कंट्रोल में नहीं आए हैं। हमारे कंट्रोल में जिस दिन दाम आ जाएंगे, मैं उपभोक्ता मामले का मंत्री हूं, तो मुझे उपभोक्ता के इंट्रेस्ट को देखना है, लेकिन उसके साथ ही किसानों के इंट्रेस्ट को भी देखना है। जब भी मेरे पास यह आ जाएगा कि अब दाम स्थिर हो गए हैं, अभी जो आपने कहा है, तब हम उस पर विचार करेंगे।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती) : लेकिन आप प्याज के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आज प्याज का जो भाव है, वह दो रुपये में भी नहीं बिक रहा है। वहां पर बेचारा किसान मर रहा है। आप कैसे फारमर्स इनकम डबल करेंगे? मैं आपसे यह विनती करती हूं कि आप अपनी कैबिनेट में इस सुझाव को भी लीजिए।...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : आपकी जो भावना है, मैं उससे सहमत हूं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहां पर दो रुपये किलो में प्याज बिक रहा है। लेकिन आप दिल्ली में अभी-भी जाकर देखिए कि यहां पर कितने रुपये किलो में प्याज बिक रहा है। जब दाम बढ़ जाते हैं, तब आप लोग प्याज की माला पहनकर घूमना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब दाम बिल्कुल घट जाते हैं, तब भी वही करते हैं। इसलिए, सरकार को दोनों चीजों को देखकर चलना पड़ता है। लेकिन हम आपकी इस भावना से सहमत हैं कि किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं उस समय भी यह कह रहा था कि नासिक में सस्ते दर पर प्याज बिक रहा है। लेकिन बारिश हो गई, फ्लड आ गया, उसका नतीजा यह हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत-सी दिक्कतें आने लगी थीं। आप उस बारे में जानती हैं। मैं आपकी भावना से सहमत हूं। समय आने दीजिए, मैं इस संबंध में फैसला लूंगा।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती) : आप अभी भी सोचें, नहीं तो कॉमर्स मिनिस्ट्री रिक्वेस्ट करें, तो हो सकता है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी) : सुप्रिया जी, मेरा निवेदन है कि आप अब कन्क्लूड कीजिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): He was intervening. It was very kind of the Minister to intervene on an important point.

The Minister of External Affairs himself was here. Prof. Roy had spoken extensively about our foreign policy. I just want to raise one point here. The cancellation of visit of various dignitaries is alarming. I have one humble question to ask of this Government. Prof. Roy mentioned about Howdy Modi event. On that same dais, the hon. Prime Minister said, 'Abki Baar Trump Sarkar'. Was it

really in the political interest of our nation? I am asking this because in diplomatic practice, in another country another Premier cannot go and say this. That is what I understand. …(*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): The Minister of External Affairs has already given a clarification on that.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I am just highlighting it. I am talking about the policy. It is nice to be heckled by Ministers. It is interesting. It is a new observation. You have the Congress DNA. How can you heckle?

I just have to make two or three small points. I will conclude very quickly. I will just make three points and conclude. I will skip my other points.

In his Address, at para 53, the hon. President has said that 1,000 fast track special courts and women help desks will be established. I welcome this. But justice delayed is justice denied. हम लोग अभी तक निर्भया के गुनेहगारों को फांसी नहीं दे सके हैं। How is this Government going to implement this? I welcome this step. We will support you wholeheartedly if you implement it. Maharashtra will do it. But how are you going to implement this? I want to know this because you have to establish 1,000 fast track special courts and women help desks.

There is a point about Self Help Groups. It is said that they are provided finance at low interest rates. Which interest rates are low? Can this Government kindly clarify? It is because at least in our State the interest charged is not low at all.

I will make just make two more points and conclude. At para 71, the President mentions about competitive, cooperative federalism. I just would like to highlight the case of Bhima Koregaon. The NIA has intervened and they want to transfer the case. Let me tell you, in thirty seconds, the history of this case.

(1650/SM/GG)

These were riots which happened in Pune district where I come from. At that time, it was their Government. Inquiry was going on. The then Chief Minister had written to the then Home Ministry when it was thought of doing an NIA inquiry. It clearly said: “It was doing exceptionally well; we are satisfied with the progress and there should not be any NIA intervention.”

So, what has happened in the last three months? On one side, you are talking about cooperative federalism. Then, what has happened in Bhima Koregaon case? …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (DR. KIRIT P. SOLANKI): Thank you very much.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, this is my last point. This is very important because it hurts my State directly. Point no. 73 says: "My Government is committed to protecting privacy amidst the increase in use of digital data."

In my own State, Sir, there has been phone tapping. Inquiry for this has just started. Pegasus was not our creation. It was created – if I am wrong, please correct me – by Chhattisgarh Government when they were in power there. So, I need a clarification. These are only my humble questions …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, only the last small point. You have talked about merger of small public sector banks. My luck is on my side today because the hon. Finance Minister is here at present. …(*Interruptions*).

HON. CHAIRPERSON: Thank you, Supriyaji.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): The bank is in real critical stage …(*Interruptions*) The depositors are really poor. …(*Interruptions*) Please make an intervention …(*Interruptions*) Please do something.

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी): सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अपनी बात को पांच मिनट में समाप्त कीजिए। We have a very long list.

… (*Interruptions*)

सौगत राय जी, आप तो बहुत सीनियर लीडर हैं, आप बैठ जाइए। मैं सभी से दोबारा निवेदन करता हूँ कि पांच मिनट में अपनी बात को समाप्त कीजिए।

(ends)

1652 hours

श्री चिराग पासवान (जमुई): सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अपना मत रखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह मौका और लम्हा इसलिए भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि यह इस दशक का राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण था। प्रधान मंत्री जी के प्रयासों को बहुत ही व्यापक तरीके से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में दर्शाया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी की हमारी प्राथमिकता है कि हमारे अभिभावक आदरणीय राम विलास पासवाल जी के सपनों का समाज, उनके सपनों के देश को प्राथमिकता देते हुए, हर उस नीति का हम लोगों ने समर्थन किया। सरकार के साथ मजबूती के साथ हम लोग खड़े रहे, जहां पर समाजिक समानता, आर्थिक समानता और विकास की तरफ जब-जब इस सरकार ने मजबूत कदम उठाए। उसी दिशा में राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण आया है, वह उस लक्ष्य को पूरे तरीके से दर्शाता है। सरकार के सहभागी होने के तौर पर भी और अभिभाषण में हर उस बिंदु को, गहन रूप से उसका अध्ययन करने के बाद पूरे तरीके से हम लोग राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए। इस धन्यवाद प्रस्ताव का हम लोग समर्थन करते हैं।

सर, इस संसद में मौजूद हरेक सांसद को पूरी तरीके से इस बात की इजाजत है कि वे यहां पर सरकार की नीतियों का अपने-अपने हिसाब से आकलन करें। परंतु एक बात मैं बहुत विनम्रता और प्रमुखता से कहना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब देश विरोधी ताकतों की आवाज बनना कतई नहीं हो सकता है। बोलने की आजादी का मतलब विभाजनकारी तत्वों का आवाज बनना कभी नहीं हो सकता है। हकीकत यह है कि सन् 2014 में देश ने पहली बार एक ऐसा चुनाव देखा, जहां पर जात-पात, धर्म और मज़हब से ऊपर उठ कर, पूरे तरीके से केन्द्र की सरकार, हमारी एनडीए की सरकार, हमारे आज के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के विकास के एजेंडे को, उनके डेवल्पमेंट के ऐजेंडों को समर्थन दिया। उससे बढ़ कर सन् 2019 में उन्होंने समर्थन दिया। क्योंकि पिछले पांच साल में जो बातें हम लोगों ने कहीं, कहीं न कहीं वे धरातल पर उतरीं। हम लोग कम ज्यादा पर जरूर बहस कर सकते हैं, परंतु कोई यह बोले कि पिछले पांच सालों में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ तो इस बात को कतई कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। परंतु हकीकत यह भी है कि जहां इस कार्यकाल में एक के बाद एक लंबे पड़े हुए विवादित मसले, जिनके ऊपर निरंतर राजनीति होती रही, चुनाव होते रहे, जैसे धारा-370 की बात हो, अनुच्छेद 35ए की बात हो, या राम मंदिर का मुद्दा हो, या फिर असम में इतना बड़ा मुद्दा, मैं बचपन से इस बात को सुनता आ रहा हूँ कि बोडोलैंड-बोडोलैंड। इतना बड़ा विषय वहां पर चल रहा था। इन तमाम विषयों को सुलझाया गया है। सुलझाया गया तो कहीं न कहीं विपक्ष में इस बात को ले कर एक बौखलाहट भी शुरू हुई, क्योंकि जितने विभाजनकारी मुद्दे थे, अराजकता फैलाने वाले जितने मुद्दे थे, सरकार के द्वारा उनका समाधान कर दिया गया है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।

(1655/KN/AK)

मुद्दा क्या उठाया गया? सीएए का मुद्दा उठाया गया। यहाँ पर बैठा हर एक जानकार शख्स इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि सीएए का भारत में रहने वाले नागरिकों से कुछ लेना-

देना नहीं है, उसके बावजूद भी इस पर भ्रम फैलाया जाता है। निरन्तर हम लोग कह-कह कर थक गए हैं और जो इनको पता भी है, ये खुद जानते हैं कि भईया, यह नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। वर्ष 1955 में नागरिकता का यह कानून बना, सिटिजनशिप का यह एक्ट बना। उसके बाद यह सही है कि वर्ष 2003 में इसमें संशोधन हुआ, एनपीआर को इसमें जोड़ा गया, परन्तु हकीकत यह भी है कि वर्ष 2010 में मनमोहन जी की सरकार में, उस वक्त के वित्त मंत्री चिदम्बरम जी के समय में, उस वक्त इसमें संशोधन करके एनआरसी को जोड़ा गया। एनआरसी का प्रावधान उस वक्त लाया गया और उसको मेनडेटरी किया गया तो उस वक्त तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। उस वक्त किसी की चिन्ता नहीं जागी, पर अब क्योंकि तमाम विवादित मुद्दे खत्म हो गए हैं, तो किसी तरीके से विभाजनकारी राजनीति हम लोगों को करनी है। हिन्दू-मुसलमान में समाज को बाँटना है तो भईया सीएए का विरोध करें। क्यों, क्योंकि इसमें मुसलमान नाम नहीं जोड़ा गया। ये तीन ऐसे देशों के माइनोरिटीज़ को नागरिकता देने का यह कानून है। वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का कानून है, पर उसके बावजूद भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जिस तरीके से इसमें भ्रमित किया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है और वे मासूम हैं। सर, हकीकत है, वे मासूम हैं। उनको जो बात जैसे जाकर बोल रहा है, वह उस बहकावे में आ रहे हैं। निरन्तर हम लोग हर मन से, और यह कहीं न कहीं विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि देश को आप इस तरीके से जला नहीं सकते हैं। सर, इतिहास देखिएगा, 'हाथ कंगन को आरसी क्या', साल, दो साल, तीन साल में पता चल जाएगा कि किसकी नागरिकता छीन ली? पर उस वक्त जब यह बात स्पष्ट होगी कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं गई, तो उस वक्त इतिहास इन लोगों को, ऐसे राजनीतिक दलों को और ऐसे राजनीतिक नेताओं को कभी माफ नहीं करेगा, जिन्होंने देश में आगजनी और अराजकता का माहौल बनाया।

सर, एनपीआर की बात है। एनपीआर में हम लोगों की भी चिन्ता है। हम लोग गए थे, गृह मंत्री जी से हम लोगों ने बात की, उसमें एक-दो ऐसे प्रावधान हैं, जिसको लेकर हम लोगों को भी चिन्ता है। हम लोगों ने बात की। उन्होंने पूरे तरीके से उसको स्पष्ट किया। उन्होंने तो यहाँ तक भी बोला कि उसके बाद भी अगर किसी को इस बात की शंका होती है कि भईया कोई डाउटफुलनैस बन रही है, तो हम लोग फॉर्म के नीचे लिखने को भी तैयार है कि कोई ऐसा कॉलम, जो कि नहीं भरा गया है या उसमें जानकारी नहीं दी गई है, तो इसकी वजह से आपको किसी डाउटफुलनैस में नहीं डाला जाएगा। मैं तो विपक्ष के साथियों से आग्रह करूँगा। आप अपना प्रतिनिधिमंडल बना लीजिए। चलिए, होम मिनिस्टर के पास। वहाँ पर जाइये, उनसे बातचीत कीजिए। जितने आपके प्रश्न हैं, उनका हल लीजिए। सड़क पर आप राजनीति कर रहे हैं, संसद आप चलने नहीं देते। यहाँ पर आप हंगामा करते हैं, चलिए ना होम मिनिस्टर के पास। मैं लेकर चलूँगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। चलिए होम मिनिस्टिर के पास, चलकर हम लोग बात करते हैं, जितने आपके प्रश्न हैं, उनका जवाब आप उनसे ले लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो कीजिए हंगामा। एनआरसी को लेकर आपने बिना मतलब के हो-हल्ला मचाया हुआ है। हमारे प्रधान मंत्री बोल चुके हैं। भईया, हैड ऑफ द गवर्नमेंट है- हमारे प्रधान मंत्री। मुझे विश्वास है, हमारे प्रधान मंत्री पर। जब एनआरसी

आएगा, अगर आपको कोई दिक्कत है, तो उस वक्त आप विरोध कीजिएगा। बट इन एन्टीसिपेशन, कि एनआरसी आएगा तो ऐसा हो जाएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी, इन एन्टीसिपेशन आज आप देश को जलाने में लगे हुए हैं, क्यों?...(व्यवधान) Sir, I am not yielding. ...(*Interruptions*) You have spoken enough. ...(*Interruptions*) Let me speak now. ...(*Interruptions*) I am not yielding to anyone. ...(*Interruptions*)

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी): चिराग जी, आप यहाँ एड्रेस कीजिए।

श्री चिराग पासवान (जमुई) : जब एनआरसी आएगा, तो उस वक्त आप इन बातों को उठाइएगा। पर इन एन्टीसिपेशन, अभी से आप देश को जलाने का काम कर रहे हैं, देश में अराजकता का माहौल फैलाने का काम कर रहे हैं। आप एक अविश्वास पैदा कर रहे हैं, जो कि किसी भी सभ्य समाज के लिए और भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको मैं कतई जायज नहीं ठहरा सकता और जैसा मैंने कहा कि आने वाला समय अपने आप दर्शाएगा कि कौन सही था, कौन गलत था?

सर, इस अभिभाषण में कई तरह के विकासकारी मुद्दों का जिक्र हुआ। उनको मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। हकीकत है कि जहाँ एक तरफ हमारी सरकार ने हर एक क्षेत्र, हर एक वर्ग पर ध्यान दिया है, जहाँ एक तरफ घर में हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य की चिन्ता करते हुए उज्ज्वला योजना का जिक्र हुआ, तो सरहद पर हमारी सीमाएँ कैसे सुरक्षित रहें, उसका भी इसमें जिक्र हुआ। आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, हर तरीके से जहाँ देश के इनफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का पिछले पाँच-छ: सालों में हम लोगों ने काम किया, तो वहीं अंतरिक्ष के माध्यम से भी कैसे हम लोग देश को सुरक्षित रखें, उस दिशा में भी इस सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, कई कार्य किए हैं, जिसका प्रमुखता से जिक्र मेरे तमाम साथी सदस्यों ने किया है। मैं उन आँकड़ों में नहीं जाऊँगा, गिनाऊँगा नहीं, कि कितने करोड़ उज्ज्वला मिले, कितने करोड़ आवास मिले, वे तमाम आँकड़े जनता के समक्ष हैं, जनता जानती है और इसीलिए पिछली बार से बड़ा मेनडेट इस बार हमारी सरकार को मिला।

सर, मेरी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे विषय हैं, जिनको मैं सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ। मेरी अपनी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसी माँगे हैं, जो मैं सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि सरकार उन पर भी उतनी ही गम्भीरता से अपना ध्यान दे, जिसमें सबसे प्रमुखता से इंडियन ज्यूडिशियल सर्विसेज़ है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इंडियन ज्यूडिशियल सर्विसेज़ का गठन हो।

(1700/CS/SPR)

जिस तरीके से आई.ए.एस., आई.पी.एस. ऑफिसर्स की नियुक्ति काम्पिटिशन के माध्यम से होती है, काम्पिटिशन के माध्यम से वे चुनकर आते हैं, मैं चाहता हूँ कि जूडिशियल सर्विस में जजों की नियुक्ति भी उसी माध्यम से हो। अभी जिस तरीके से एक कॉलेजियम बना हुआ है, उस कॉलेजियम में जो गिनती के लोग, घर, परिवार हैं, उसी में से जजों की नियुक्ति होती है। मैं चाहता हूँ कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या ऊँची जाति में भी जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनकी रीच वहाँ तक नहीं है, वे काम्पिटिशन के माध्यम से आएं। जब ऐसे लोग जज बनकर वहाँ पर जाएंगे, तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि justice delayed is justice denied और इसका सबसे बड़ा उदाहरण निर्भया का केस है। वह केस 7 साल से लंबित चल रहा है। मेरी तो यह समझ से परे है और मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि जिन कानूनों में भी हम लोगों को बदलाव करने की जरूरत है, वह बदलाव हम लोगों को करना चाहिए। अभी तक हम लोग तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख सुनते आ रहे थे, अब विकल्प पे विकल्प, विकल्प पे विकल्प, विकल्प पे विकल्प सुनते आ रहे हैं। दोषियों को अपनी फांसी की सजा से दूर भागने, उससे हटने के एक के बाद एक विकल्प मिल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि जब ऐसे वंचित वर्ग के लोग जज बनकर आएंगे।...(व्यवधान)

सर, घड़ी देखकर तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करके मैं शांति से बैठ जाऊँगा। मैं तीन मिनट से ज्यादा समय नहीं लूँगा। मेरे बस दो विषय और हैं। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इंडियन जूडिशियल सर्विसेज का गठन हो, ताकि वंचित वर्ग के लोग, गरीब परिवार के लोग, जिन्होंने सही मायने में प्रताड़ना को झेला है, उसको महसूस किया है, जब वे जज बनकर वहाँ पर बैठेंगे तो वे ईमानदारी और तत्परता से ऐसे केसेज की तरफ कार्य करेंगे।

सर, अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ और जब मैं इस विषय को यहाँ उठा रहा हूँ तो यहाँ जितनी भी हमारी महिला सांसद हैं, मैं उनका संरक्षण भी चाहूँगा, सुप्रिया मैम, मैं आपका भी संरक्षण चाहूँगा। मैं सबका संरक्षण और समर्थन चाहूँगा। मैं वुमेन आरक्षण बिल की बात कर रहा हूँ। देश की आधी आबादी है।...(व्यवधान) आप सभी का धन्यवाद। देश की आधी आबादी है और आधी आबादी को अब उसका सम्मान मिलना चाहिए। आज इतनी भारी संख्या में महिला सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, यह दो चीजों को दर्शाता है। एक तो उनका सामर्थ्य कि उनमें अकेले इतनी क्षमता है कि वे इतनी बड़ी ताकत में, इतनी बड़ी तादाद में जीतकर आई हैं और दूसरा देश का विश्वास उनके ऊपर है, क्योंकि वे महिला सांसदों को चुनकर हमारी भारत की संसद में भेजते हैं। मेरा विश्वास हमारे प्रधान मंत्री जी पर है कि इन्हीं के अंदर एक ऐसी इच्छाशक्ति है, जो इस विधेयक को लाने के लिए चाहिए। यह विधेयक लंबे समय से लंबित पड़ा है। आप इस विधेयक को संसद के सामने रखिए और उस पर हम लोग गहन चर्चा करेंगे। कई बार होता है कि मौजूदा स्ट्रक्चर में कैसे उसको शामिल किया जाए, नहीं हो सकता तो एक तिहाई सीट्स बढ़ा दीजिए। उसमें भी आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर दीजिए। यह आप उसमें करवा दीजिए।

जो भी इस पर चर्चा हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह विधेयक संसद में आए और उस पर हम लोग चर्चा करें।

अब मैं अपना आखिरी विषय रखता हूँ। मैं युवा हूँ और युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूँ। अगर मैं यहाँ युवाओं की बात न करूँ तो कहीं न कहीं अपने युवा साथियों के साथ अन्याय करूँगा, जो टकटकी लगाए दिन-रात देखते रहते हैं कि भारत की संसद में उनकी आवाज कोई उठा रहा है या नहीं। मैं उनकी चिंताओं को समझ सकता हूँ। जब मैं बाहर जाता हूँ तो वे मुझसे बोलते हैं कि भइया वहाँ पर तो हर राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकता है, हमारी बात कौन करता है। जात-पात, धर्म, मजहब की तो सब बातें करते हैं, हमारा विषय कौन उठाता है।

सर, इसलिए युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के नाते मैं उन युवाओं के तमाम विषयों को उठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि युवाओं को लेकर एक गहन चर्चा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, बेहतर शिक्षा प्रणाली का मुद्दा हो, उनकी बेहतर जीवन शैली का मुद्दा हो, जो भी उनसे संबंधित मुद्दे हों, उन सभी मुद्दों पर गहन चर्चा होनी चाहिए। अब समय है, भारत एक युवा देश है, अब देश में एक राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन का समय है। एक नेशनल यूथ कमीशन बनना चाहिए। जिस तरीके से महिला आयोग है, अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, तमाम तरह के आयोग हैं, उसी की तर्ज पर एक नेशनल यूथ कमीशन बनना चाहिए। यह कमीशन युवाओं से जुड़े हुए हर विषय को देखे, एक नोडल एजेंसी हो, ताकि युवा वहाँ पर अपनी समस्या के साथ जाएं और उसका समाधान लेकर आएं। मैं अपनी ये तीन महत्वपूर्ण माँगें सरकार के समक्ष रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार इनको उतनी ही गंभीरता से लेगी।

अंत में, मैं अपने क्षेत्रवासी, जमुई लोक सभा के मेरे जितने वासी हैं, उन्होंने फोन पर, मुझसे मुलाकात कर बताया कि राष्ट्रपति महोदय के इस अभिभाषण का उन लोगों ने कितनी खूबसूरती से स्वागत किया है।

मैं अपनी तरफ से, मेरे नेता आदरणीय राम विलास पासवान जी की तरफ से, मेरी पार्टी लोक जन शक्ति पार्टी की तरफ से एक तरफ मैं हमारे प्रधान मंत्री और हमारी केन्द्र की सरकार को बधाई देता हूँ और वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए हुए धन्यवाद प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1704 बजे

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): महोदय, धन्यवाद।

1704 बजे (श्री कोडिकुन्निल सुरेश पीठासीन हुए)

महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर श्री प्रवेश वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार के नए भारत के संकल्प के बारे में बताया गया। (1705/RV/UB)

इस संकल्प को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल से ही विकास के नए अध्याय लिखने की शुरुआत कर दी थी। इसलिए इस सरकार के पिछले कार्यकाल से लेकर आज तक जितनी भी योजनाएं प्रारंभ की गईं, उन योजनाओं के जिन आँकड़ो का जिक्र इस अभिभाषण में है, वह और कुछ नहीं, बल्कि समाज के अन्तिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने वाली उपलब्धियां हैं। अगर हम उन आवासहीन लोगों की बात करें तो ऐसे दो करोड़ लोगों के सिर पर छत देने का काम हमारी सरकार ने किया। इसकी सबसे खास बात यह रही कि यह घर परिवार की महिला के नाम पर हमारी सरकार ने देने का काम किया। हमारे समाज में, आम तौर से, यह परम्परा है कि घर, मकान, खेत, गाड़ी, जो भी होगा, वह या तो पति के नाम पर होगा या बेटे के नाम पर होगा, लेकिन मोदी जी की सरकार ने समाज के अन्दर एक परिवर्तन लाने का काम किया। दो करोड़ लोगों को जो आवास दिए गए, वे घर की स्त्री के नाम पर, घर की महिला के नाम पर दिए गए, ताकि वे सिर उठाकर जीवन जी सकें।...(व्यवधान)

इसके साथ ही, हमारी गरीब महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आठ करोड़ महिलाओं को स्वच्छ ईंधन के जरिए बेहतर जीवन देने का प्रयास भी हमारी सरकार ने किया। आठ करोड़ का आँकड़ा बहुत बड़ा है और पाँच सालों में हमारी सरकार ने यह करके दिखाया है। 38 करोड़ लोगों को, जिनके पास बैंकों में खाते नहीं थे, उन्हें बैंकों में खाते दिए गए और 50 करोड़ लोगों को पाँच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया। ढाई करोड़ लोगों को बिजली के कनेक्शंस दिए गए और इसके साथ ही पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बहुत बड़ा विकास का कार्य हमारी सरकार ने किया, चाहे वह जलमार्गों का विकास हो, मेट्रो सुविधा का विकास हो, रेल मार्गों का विकास हो, ये सब कुछ मोदी सरकार ने संभव करके दिखाया।

इस सरकार ने जल जीवन मिशन के रूप में देश के सामने एक बहुत बड़ा सपना रखा। कहने को तो हमारा देश 70 वर्ष पहले आज़ाद हो चुका है, लेकिन इतने वर्षों की आज़ादी के बाद भी आज देश की लगभग आधी आबादी ऐसी है, जहां पीने का शुद्ध पानी लाने के लिए महिलाओं को, घर की औरतों को अपने सिर पर मटकी रख कर दो किलोमीटर, पाँच किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। ऐसे घर के अन्दर पीने का शुद्ध पानी आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा की, जिसमें जल संचय, बारिश के पानी का संग्रह, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, पानी बचाने के तमाम प्रयास और पानी के स्रोतों को पुनर्जीवित करने की सारी योजनाएं शामिल हैं, इसके लिए मैं सरकार की बहुत सराहना करती हूं।

बीते दिनों हमारे देश में महिलाओं के विरुद्ध एक से बढ़ कर एक जघन्य अपराधों की घटनाएं सामने आईं, चाहे वह हैदराबाद की घटना हो या उन्नाव की हो, लगभग देश के हर कोने में ऐसी घटनाएं बराबर होती रहती हैं और इन घटनाओं पर अंकुश लगाने की दृष्टि से सरकार ने, देश के अन्दर फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना का, वन-स्टॉप-क्राइसिस-सेन्टर्स की स्थापना का और इसके साथ-साथ हर पुलिस थाने के अन्दर महिला हेल्प डेस्क बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह भी अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है।

हमारे सुरक्षा बलों के सशक्तिकरण और आधुनिकीकरण पर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। पहली बार देश के अन्दर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन और इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्रीज़ अफेयर्स को, जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिफेंस रिफॉर्म्स की डिमांड थी, उसे पूरा करने का काम भी सरकार ने किया है।

रिन्युएबल एनर्जी की दिशा में सरकार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है और हमारे यहां बिजली की जो मांग है, कैसे उसे सोलर पावर के जरिए, हाइड्रो पावर के जरिए, विंड एनर्जी के जरिए, बायोमास, बायोगैस जेनरेशन के जरिए पूरा करें, इसके लिए हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है।

सभापति महोदय, जहां विकास का नए अध्याय लिखना नए भारत की कल्पना में शामिल है, वहीं सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करना भी हमारे नए भारत की कल्पना में समाहित है। पिछले कार्यकाल से लेकर इस कार्यकाल तक सरकार ने ऐसे तमाम कदम उठाए हैं, जिससे हमारे समाज के पिछड़े, वंचित, दलित और कमजोर तबकों को आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि पिछले सत्र में जो एक महत्वपूर्ण कार्य इस सरकार ने किया, वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोक सभा और विधान सभाओं में आरक्षण की अवधि को दस वर्ष बढ़ाने के लिए कानून बनाने का काम किया।

इसके साथ ही माननीय प्रधान मंत्री जी की कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हमारे जो केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय हैं, उनमें पिछड़ी जाति से आने वाले बच्चों के लिए अकादमिक सत्र 2020-21 से उनके प्रवेश-प्रक्रिया में उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। यूनिवर्सिटीज़ की नियुक्ति प्रक्रिया में जो 13-पॉइंट का रोस्टर था, उसके स्थान पर पूर्ववर्ती 200-पॉइंट रोस्टर की व्यवस्था को बहाल किया।

पिछले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का निर्णय किया और क्रीमी लेयर की जो आय सीमा थी, उसे छ: लाख रुपये से बढ़ा कर आठ लाख रुपये करने का काम भी हमारी सरकार ने किया।

(1710/MY/KMR)

मैं इन निर्णयों की सराहना करती हूं। लेकिन मैं सरकार से जरूर कहना चाहती हूं कि अभी पिछड़े, दलित और कमजोर तबकों के हक में और भी बहुत कुछ करना बाकी है। जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसका उल्लेख हमारे माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी भी कई बार कर चुके हैं। वह ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन है। न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ

है। उस न्यायपालिका में सोशल डाइवर्सिटी का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के गठन के साथ हमारे समाज के जो वंचित तबके हैं, उनको भी देश की न्यायपालिका, लोकतंत्र के इस मजबूत स्तंभ में आने का अवसर मिलेगा। मैं सरकार से यह मांग करना चाहती हूं कि आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के गठन की ओर ध्यान दें।

महोदय, मैं एक अंतिम निवेदन करते हुए, अपनी बात को समाप्त करूंगी। हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे ऊँची प्रतिमा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित की गई है, उसका उल्लेख किया गया कि कैसे उस प्रतिमा को देखने के लिए देश भर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। मैं इतना कहना चाहती हूं कि इस पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का सही स्थान देश की राजधानी दिल्ली में है। इसलिए सरकार के इस कार्य काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना दिल्ली में की जाए।

महोदय, इतना ही कहते हुए, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए और दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करने के लिए मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करती हूं।

(इति)

1712 बजे

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): माननीय सभापति जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे अपने विचारों को रखने का अवसर दिया। मैं अपने संसदीय क्षेत्र मालदा उत्तर की जनता की ओर से भी आपको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।

महोदय, इस अभिभाषण में विश्व प्रिय आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा बनी सरकार की उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। इस अवसर पर मैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के उन विचारों की ओर अवगत कराना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने अपने आपको प्रधान सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हुये विकास की नयी अवधारणा शुरू की। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने अंत्योदय को राजनैतिक दर्शन का मूल मंत्र माना है। उन्होंने प्रमुख फैसले लेते समय हमेशा वंचित, गरीब, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, मजदूर और किसानों का ध्यान रखा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 'प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना' और 'किसान सम्मान निधि योजना' है, जिसके माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग की महिलाओं और अन्नदाता किसानों को वरदान मिला है।

महोदय, 26 नवंबर, 2019 को संविधान के 70 वर्ष पूरे हुए और उस दिन देश के 12 करोड़ लोगों ने संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लिया। इसी क्रम में देश की संसद ने धारा 370 और अनुच्छेद 35-ए हटाने का विधेयक दो-तिहाई बहुमत से पारित किया। इस कार्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ। इसके लिए माननीय मोदी जी को कोटिश: धन्यवाद। यह देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था, जिसके बारे में प्रधान मंत्री जी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि हम समस्याओं का स्थायी समाधान चाहते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों की तरह मामलों को लटकाना नहीं चाहते। यह बात चाहे जी.एस.टी. हो, गरीबों का आरक्षण हो, रेप जैसे अपराधों में फांसी का फैसला हो, में परिलक्षित होता है।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी का 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का नारा उनके नेतृत्व में किए गए कार्यों से स्पष्ट होता दिख रहा है। 'आयुष्मान भारत' की योजना से देश के 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसकी प्रशंसा विश्व की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका 'लांसेट' में की गई है। किसानों के लिए जो योजनाएं लागू की गई हैं, उसका मूल मंत्र है कि 'अन्नदाता सुखी भव:' ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आगामी वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय सरकार की इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 'आयुष्मान भारत' और 'किसान सम्मान निधि' योजनाएं पश्चिम बंगाल में टी.एम.सी. सरकार द्वारा लागू नहीं की गई हैं।

(1715/CP/SNT)

भारत ने सदैव वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा में विश्वास बनाए रखा है और बाबा साहेब का संविधान इसकी आत्मा है। इसी सिद्धांत पर कार्य करते हुए नागरिकता संशोधन कानून संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति हम कितने सजग हैं, इसका पता इससे लगता है।

महोदय, विभाजन के समय की परिस्थितियों को देखते हुए स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुओं और सिखों को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे भारत आ सकें। तत्कालीन

सरकारों ने भी इस महत्व को समझा और समय-समय पर इसे आगे बढ़ाया। बापू इस बात के भी समर्थक थे कि पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना भारत का कर्तव्य है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा नागरिकता संशोधन कानून पारित किया गया। यह ऐसे लोगों को नागरिकता प्रदान करेगा, जो संशय की स्थिति में थे। यह कानून नागरिकता प्रदान करने के साथ ही सम्मानपूर्वक जीने और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। यह कानून किसी भी व्यक्ति की नागरिकता पर कोई प्रहार नहीं है, जैसा कि इस बारे में विपक्षी दलों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। जो मुस्लिम भाई भारत में रह रहे हैं, उनकी नागरिकता से इस कानून का कोई सरोकार नहीं है, पर विपक्षी दलों द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तो विधान सभा चुनावों को देखते हुए इसे टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।

महोदय, पश्चिम बंगाल में माननीय मोदी जी के व्यापक समर्थन को देखते हुए राजनीतिक दल, जो मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हैं तथा एक-दूसरे के पारंपरिक विरोधी रहे, जैसे सीपीआई (एम) और कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर इस समय भाजपा के विरूद्ध मोर्चा खोल दिया है। वास्तविकता यह है कि नागरिकता संशोधन कानून से बंगाल के उदबास्ती शरणार्थी लोगों को नागरिकता प्राप्त होगी और वे सम्मानपूर्वक जीने का हक प्राप्त करेंगे।

महोदय, मुझे आदिवासियों के बारे में कुछ बोलना है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी मेनिफेस्टो में आजादी के सत्तर साल बाद आदिवासियों के कल्याण और उत्थान की बात की गई थी। प्रधान मंत्री मोदी जी के हम आभारी हैं, जिन्होंने इस कार्य को कर दिखाया। इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को आदिवासी समाज की ओर से कोटिश: धन्यवाद।

महोदय, मैं आदिवासी समाज से आता हूं। आजादी के बाद पहली बार हमें सम्मान और स्वाभिमान से जीने लायक बनाया गया है। सरकार आदिवासी समाज द्वारा उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए ट्राइबल मार्केटिंग कोआपरेटिव फेडरेशन की स्थापना की गई। गणतंत्र दिवस के दिन "उचित दाम हक से मांग" नामक एक झांकी भी निकाली गई। सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में खनिज उत्पादों की 10 प्रतिशत रॉयल्टी विकास में खर्च की जा रही है।

एकलव्य विद्यालयों की स्थापना 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी बहुल क्षेत्रों में की जा रही है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने संथाली भाषा के विकास और आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने की घोषणा भी रांची में की है। आदिवासी सेनानियों के सम्मान में देश भर में संग्रहालय बन रहे हैं। इसमें पहला आइकोनिक ट्राइबल म्युजियम रांची में बनेगा। यह आदिवासी समाज के लिए गौरव की बात है।

महोदय, अब तक किसी भी सरकार के समय में इस समाज के उत्थान हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

(1720/NK/GM)

इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को आभार और धन्यवाद। ससंद में पुन: सीटों का आरक्षण दस साल तक बढ़ाने के लिए हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम माननीय वित्त मंत्री जी को भी

धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने इस बजट में आदिवासी कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं इस बात के लिए भी आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आजादी के बाद पहली बार देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अपटार्स की स्थापना की गई। देश की समक्ष रक्षा चुनौतियों के लिए उठाया गया ऐतिहासिक कदम है और हम किसी भी प्रकार से दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं। जो ऐसी ताकतों को प्रश्रय दे रहे हैं। एक शेर है:

हम समन्दर हैं, हमें खामोश रहने दो,
जरा मचल गया तो सारा ले डूबेंगे।।

(इति)

*DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD WEST):

---

*Laid on the Table.

1721 बजे

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मुझे अफसोस हैं कि मैं इस भाषण के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हैं, यह सरकार का भाषण था, सरकार के प्रोग्राम के ऊपर तनकीद करने का किसी को भी हक है। महामहिम हमारे सर पर हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं।

दूसरी बात है, राम विलास पासवान जी यहां बैठे हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। चिराग पासवान को मुबारकबाद देता हूं, आज आपने बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत जोरदार तकरीर की। लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना, हम भी यहां के बहुत पुराने हैं और आपके पिताजी से बहुत ताल्लुक हैं। जब भी कोई अच्छी मिनिस्ट्री बनती है तो हमने रामविलास पासवान को मिनिस्ट्री के अंदर देखा है, यह उनकी अक्लमन्दी है। वह अपनी कौम के लिए जो करना चाहते हैं, आप अपोजिशन की जितनी भी तनकीद करो, एक बात का ख्याल रखा करो, एक बुर्जुग की नसीहत के हिसाब से बीच का रास्ता लिया करो ताकि कभी जरूरत पड़े तो इधर जा सको और जरूरत पड़े तो उधर जा सको।

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Mr. Ajmal, your time is very short. You have to speak on the subject only.

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): माननीय सभापति महोदय,

मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिन्दी है हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा,
सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा।
हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर

इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। यह बहुत बड़ी दुआएं थीं, जो हमारे बड़े बुजर्ग मुल्क की आने वाले नस्लों के लिए देकर चले गए। हम लोग जब भी कोई बात करें तो इन चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है, सिर्फ स्पीच दे देना बड़ी बात नहीं है। मुल्क किस हालात से गुजर रहा है। आज जिन हालात से मुल्क गुजर रहा है, इससे पहले शायद 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। लड़ते रहे, पार्टियां बनती रहीं।

मेरा कहना है, इस मुल्क के लाखों लोगों ने हिन्दुस्तान के हिन्दू, मुसलमान और हजारों मजहब के भाइयों ने मिल कर एक साथ लड़ा है। आज अफसोस की बात है कि इस हाऊस का प्रजेंट प्रूव करता है, यहां सेक्युलरिज्म है, यहां जम्हूरियत है, इस मुल्क में डेमोक्रेसी है। यह डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में नम्बर एक की है। इसे सभी मानते हैं और इज्जत देते हैं। अगर कोई भी विरोधी बात करेगा, आपने विरोधी के लिए बेंच बनाया है इसलिए कि हम विरोध करें और संविधान हमें इसकी इजाजत देता है कि तुमको जो समझ नहीं आता है उसके खिलाफ बोलो। इसका मतलब यह नहीं है कि वह गद्दार हो गया।

(1725/SK/RK)

यह गद्दारी नहीं है, जम्हूरियत है। आज शाहीन बाग का मसला हमारे लिए माथे का कलंक बन गया है। 50 से 55 दिन हो गए, क्यों? उन्होंने सीएए का विरोध किया तो क्या वे गद्दार हो गए? जिसके मुंह में जो आ रहा है, वह कह रहा है, ऐसा नहीं है। आज सिख भाई लोग भी पूरा जत्था लेकर आ चुके हैं, दूसरे मज़हब के लोग भी आ चुके हैं, क्या सबको गद्दार कह देंगे? गद्दार को गोली मारो, एक मिनिस्टर कहता है, गोली मारो, गोली मारो, लोगों से कहलवाता है। यह मुल्क कहां जा रहा है?

सर, ये सब लैक्चर्स होते रहेंगे, हमारे अपने मसले होते रहेंगे, लेकिन हम लोगों का इस तरफ सोचना जरूरी है कि हम मुल्क को कहां ले जाना चाहते हैं। मेरे इश्यूज़ अपनी जगह हैं, सीएए की प्राब्लम अपनी जगह है। …(व्यवधान) आप बड़े मिनिस्टर है, मेरे भाई हैं, आप मुझे रोकें नहीं। आप मुझे दो मिनट ज्यादा दिला दीजिए।…(व्यवधान)

मैं असम से आता हूं, पूरा असम जल रहा है। 90 परसेंट लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हिन्दू बच्चे हैं, असमी बच्चे हैं। 10 परसेंट मुश्किल से उनके साथ बैठने वाले हैं। आप वीडियो मंगवा लीजिए, देख लीजिए। क्या इसका मतलब है कि वे भी सब गद्दार हो गए? यहां मुसलमान गद्दार हो गए, वहां हिन्दू गद्दार हो गए? पूरे मुल्क में शाहीन बाग की तरफ कई जगह मामला चल रहा है, क्या ये सब गद्दार हो गए? आपके खिलाफ जो बोलेंगे, वे गद्दार हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वे समझौते के लिए बार-बार कह रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई क्यों नहीं आता है? यहां अच्छी बातें लोगों ने बताई हैं, कल से मैं सुन रहा है, उन चीजों को ले जाकर वहां समझाएं।

आओ पास बैठो तो और फिक्र करते हैं,
कोई राह तो निकलेगी दूरियां मिटाने की।

कुछ पूछा ही नहीं, गद्दार बना दिया। आज मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने राम मंदिर के इश्यू, जो पार्लियामेंट में पास किया था, उसके ऊपर असर करने के लिए बकायदा एक कमेटी बना दी। लेकिन अफसोस की बात है कि यही प्रोग्राम अगर प्राइम मिनिस्टर तीन-चार दिन पहले करते, तो मेरे ख्याल से दिल्ली के इलैक्शन में उनको काफी फायदा होता। लेकिन अब वक्त निकल गया है, वक्त निकल गया है तो क्या करना है?

मैं असम से आता हूं, हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या फ्लड और इरोज़न की है। मैं यहां तीसरी बार चुनकर आया हूं। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि असम के मसले को हल करना है तो फ्लड एंड इरोज़न की समस्या को हल करना पड़ेगा, इसे नैचुरल कैलेमिटी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। इसी तरह से एनआरसी है, सारी चीजें लिंक्ड हैं। आप आवाम में जाइए, समझाइए, पूरे हिन्दुस्तान में एक आग लगी हुई है। आप बड़े लोगों को भेजिए।

एनआरसी की समस्या है। असम में की इंडस्ट्री नहीं है। दो ही इंडस्ट्रीज़ हैं, दो पेपर मिल्स हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हर इलैक्शन के टाइम पर बोलकर आते हैं कि हम इसे चालू करेंगे, आज वह बंद पड़ी है, उनके बच्चे स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हैं क्योंकि फीस नहीं दे सकते हैं। उनके

खाने-पीने के लाले पड़ रहे हैं। मैं दरख्वास्त करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, इसे चालू किया जाए।

मुल्क में अमन और शांति लाने की जरूरत है, सद्भावना की जरूरत है। आपस की गलतफहमियों को दूर करने की जरूरत है। इसके लिए जो बड़े हैं और मिनिस्ट्री में हैं, वे जाएं और लोगों को समझाएं, शायद यह मसला बातों से हल हो जाए। मैं यही कहना चाहता हूं। खुदा हाफ़िज़।

(इति)

جناب بدرالدین اجمل (دھبری): جناب چیرمین صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر بولنے کا موقع دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کےخلا ف بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صدرِ ہند کے خلاف ہیں، یہ سرکار کا بھاشن تھا، سرکار کے پروگرام پر تنقید کرنے کا حق کسی کو بھی ہے۔ صدریہ جمہوریہ ہمارے سر پر ہیں،سب ان کی عزّت کرتے ہیں، سمّان کرتے ہیں۔

دوسری بات ہے رام وِلاس پاسوان جی یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کی بہت عزّت کرتا ہوں۔ چِراغ پاسوان کو مبارکباد دیتا ہوں، آج آپ نے بہت اچھی تقریر کی، بہت زوردار تقریر کی۔ لیکن بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، ہم بھی یہاں کے بہت پرانے ہیں، اور آپ کے والد صاحب سے بہت اچھے تعلق ہے۔ جب بھی کوئی اچھی منسٹری بنتی ہے تو ہم نے رام ولاس پاسوان جی کو منسٹری کے اندر دیکھا ہے، یہ ان کی عقلمندی ہے۔وہ اپنی قوم کے لئے جو کرنا چاہتے ہیں، آپ اپوزیشن کی جتنی بھی تنقید کرو، ایک بات کا خیال رکھا کرو، ایک بزرگ کی نصیحت کے حساب سے بیچ کا راستہ لیا کروتاکہ کبھی ضرورت پڑے تو اِدھر آسکو اور ضرورت پڑے تو اُدھر جا سکو۔

محترم چیرمین صاحب، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں، ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ یہ بہت بڑی دُعائیں تھی، جو ہمارے بزرگ ملک کی آنے والی نسلوں کو دے کر چلے گئے۔ ہم لوگ جب بھی کبھی کوئی بات کریں تو ان چیزوں پر دھیان دینا بہت ضروری ہے، صرف تقریر کر دینا بڑی بات نہیں ہے۔ ملک کس حالات سے گزر رہا ہے۔ آج جن حالات سے ملک گُزر رہا ہے، اس سے پہلے شاید 70 سالوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لڑتے رہے، پارٹیاں بنتی رہی۔

میرا کہنا ہے، اس ملک کے لاکھوں لوگوں نے ہندوستان کے ہندو،مسلمان اور ہزاروں مذہب کے بھائیوں نے مل کر ایک ساتھ لڑا ہے۔ آج یہ افسوس کی بات ہے کہ اس ایوان کا پریزینٹ پروو کرتا ہے، یہاں سیکولرزم ہے، جمہوریت ہے، اس ملک میں ڈیموکریسی ہے۔ یہ ڈیموکریسی پوری دنیا میں نمبر ایک کی ہے۔ اسے سبھی مانتے ہیں اور عزت دیتے ہیں۔ ہم لوگ کوئی بھی اگر وِرودھی بات کریں گے آپ نے وِرودھی کے لئے بینچ بنایا ہےاس لئے کہ ہم وِرودھ کریں اور آئین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ تم کو جو سمجھ نہیں آتا ہے اس کے خلاف بولو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غدّار ہو گیا ہے۔ یہ غدّاری نہیں ہے، جمہوریت ہے۔ آج شاہین باغ کا مسئلہ ہمارے لئے ماتھے کا کلنک بن گیا۔ 55-50 دن ہو گئے، کیوں؟ انہوں نے سی۔اے۔اے۔ کی مخالفت کی تو وہ غدّار ہو گئے؟ جس کے مُنہ میں جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج ہمارے سِکھ بھائی بھی پورا جتھا لیکر آ چکے ہیں، دوسرا مذاہب کے لوگ بھی آ چکے ہیں کیا سب کو غدّار کہہ دیں گے؟ غّدار کو گولی مارو، ایک منسٹر کہتا ہے گولی مارو گولی مارو، لوگوں سے کہلواتا ہے۔ یہ ملک کہاں جا رہا ہے؟

جناب، یہ سب لیکچرس ہوتے رہیں گے، ہمارے اپنے مسئلے ہوتے رہیں گے، لیکن ہم لوگوں کا س طرف سوچنا ضروری ہے کہ ہم ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ میرے ایشیوز اپنی جگہ ہیں، سی۔اے۔اے۔ کی پروبلم اپنی جگہ ہے (مداخلت) آپ بڑے منسٹر ہیں، میرے بھائی ہیں، آپ مجھے روکے نہیں اپ مجھے دو منٹ زیادہ دلا دیجئے۔

میں آسام سے آتا ہوں، پورا آسام جل رہا ہے۔ 90 فیصد لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہندو بچے ہیں، آسامی بچے ہیں۔ 10 فیصد مشکل سے ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، آپ ویڈیو منگوا لیجیئے، دیکھ لیجئیے ۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ سب بھی غدّار ہو گئے؟ یہاں مسلمان غدّار ہو گئے وہاں ہندو غدّار ہو گئے؟ پورے

ملک میں شاہین باغ کی طرح کئی جگہ معاملہ چل رہا ہے، کیا یہ سب غدّار ہو گئے، آپ کے خلاف جو بولیں گے وہ غدّار ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہئیے۔ وہ سمجھوتے کے لئے بار بار کہہ رہے ہیں، سرکار کی طرف سے کوئی کیوں نہیں آتا ہے۔ یہاں بہت اچھی باتیں لوگوں نے بتائی ہیں، کل سے میں سُن رہا ہوں، ان چیزوں کو لے جا کر وہاں سمجھائیے۔

آؤ پاس بیٹھو تو اور فِکر کرتے ہیں
کوئی راہ تو نکلے گی دوریاں مٹانے کی

کچھ پوچھا ہی نہیں غدّار بنا دیا۔ آج میں وزیرِ اعظم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے رام مندر کے ایشیو، جو پارلیمنٹ میں پاس کیا تھا، اس کے اوپر اثر کرنے کے لئے باقائدہ ایک کمیٹی بنا دی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہی پروگرام اگر وزیرِ اعظم تین چار دن پہلے کرتے تو میرے خیال سے دہلی کے الیکشن میں ان کو کافی فائدہ ہوتا۔ لیکن اب وقت نکل گیا ہے، وقت نکل گیا ہے تو کیا کرنا ہے۔

میں آسام سے آتا ہوں، ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ باڑھ اور ایروزن کا ہے۔ میں اس ایوان میں تیسری بار چُن کر آیا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آسام کے مسئلے کو حل کرنا ہے تو سب سے پہلے فلڈ اور ایروزن کی سمسّیاں کو حل کرنا ہوگا، اسے نیچُرل کیلیمِٹی ڈِکلئر کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے این۔آر۔سی۔ ہے، ساری چیزیں لِنکڈ ہیں۔ آپ عوام کے پاس جائیے، سمجھائیے، پورے ملک میں ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ بڑے لوگوں کو بھیجئے۔

این۔آر۔سی۔ کی سمسّیاں ہے۔ آسام میں کینوڈ کی انڈسٹری نہیں ہے ۔ دو ہی انڈسٹریز ہیں، دو پیپر مِلس ہیں۔ وزیرِ اعظم مودی جی، ہر الیکشن کے وقت بول کر آتے ہیں کہ ہم اسے چالو کریں گے، آج وہ بند پڑی ہیں، ان کے بچے اسکول چھوڑنے کے لئے مجبور ہیں، کیونکہ فیس نہیں دے سکتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے کے لالے پڑ رہے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے چالو کیا جائے۔

ملک میں امن اور شانتی لانے کی ضرورت ہے، آپسی بھائی چارے کی ضرورت ہے۔ آپس کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے جو بڑے ہیں اور منسٹری میں ہیں، وہ جائیں اور لوگوں کو سمجھائیں، شاید یہ مسئلہ باتوں سے حل ہو جائے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خُدا حافظ۔

(ختم شد)

*DR. T. SUMATHY (a) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH):

---

*Laid on the Table

1728 बजे

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली): माननीय सभापति जी, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यहां महामहिम राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमने अभिभाषण का पूरा वक्तव्य देखा है और पढ़ा है, ऐसा लगता है कि इसमें नए भारत की भी घोषणा है। इस अभिभाषण में पिछड़े हुए क्षेत्र या गरीब इलाकों के लिए भी बहुत कुछ देखने को मिला है। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, खास कर माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ग्रामीण विस्तार में कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। आज हम देखते हैं कि कई योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में चल रही हैं और इसकी संख्या भी बढ़ी है।

(1730/MK/PS)

लेकिन, हम उन योजनाओं को देखें, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और प्रधान मंत्री आवास योजना को देखें तो बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं। हम ऐसा समझ सकते हैं। जैसे चिराग जी ने बताया कि जो आयुष्मान योजना लागू की गई है, उसमें पांच लाख रुपये की सुविधा, फ्री ट्रीटमेंट गरीब लोगों को देने की जो योजना है, यह बहुत बड़ा कदम और ऐतिहासिक कदम है। ऐसा मैं समझता हूं, जिसमें हम यह मान सकते हैं कि गरीब व्यक्ति यह सोच भी नहीं सकता था, जब उसको भारी बीमारी का सामना करना पड़ता था। वह यह सोच लेता था कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे अभी मरना ही पड़ेगा, इस बीच में जो पांच लाख रुपये की सुविधा आयुष्मान भारत योजना की तरफ से दी गई है, आज गरीब व्यक्ति यह मानता है कि मुझे एक नया जीवन मिला है, मैं सर्वाइव कर सकता हूं, मैं भारी बीमारी से बाहर आ सकता हूं। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अहम और सही योजना लागू की गई है।

गरीब व्यक्ति कभी नहीं सोचता था कि मेरा घर पक्का होगा। एक सपना देखता था कि मेरा घर पक्का बनेगा। आज इस प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत लाखों लोगों को पक्का घर मिल रहा है। …(व्यवधान) लाखों से करोड़ों तक भी पहुंच जाएगा। यह जो योजना है, इससे भी काफी बड़ी संख्या में लोगों को इसकी सुविधा मिली है। उज्ज्वला योजना से हमारी जो बहनें और महिलाएं हैं, उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिला है। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, उसमें पूरे भारत का समावेश किया गया है। इसलिए, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने देखा और पढ़ा कि महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में सदन की पिछली दो बैठकों में ऐसे काम हुए जिसको अभिभाषण में बताया गया कि यह कीर्तिमान है। यह रेकॉर्ड किया गया कि इतने सारे काम लोक सभा में हुए।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं यह श्रेय हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय को देना चाहता हूं। जो कीर्तिमान हुआ, इतने सारे काम हुए, इतने सारे कानून बने, इसके लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सारे हाउस का भी धन्यवाद

करना चाहता हूं। सदन के सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से ही यह पाया है। इसलिए मैं सदन के सारे सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं।

मैंने भी नागरिकता कानून का सपोर्ट किया है। मैंने वोटिंग में साथ दिया है। मैं इस बात को मानता हूं, आज पूरे देश में इस विषय पर चर्चा हो रही है, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन, जहां तक मैंने समझा है, मैं बताना चाहता हूं कि हमने जो नागरिकता कानून का समर्थन किया है, उसके पीछे एक ही वाक्य काफी है, वह वाक्य यह है कि यह कानून किसी की नागरिकता छिनता नहीं है, यह कानून नागरिकता देने का काम करता है, यही हमारे लिए काफी है। भारत सरकार ने इस बात को आश्वस्त किया है, यहां पर हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि कानून किसी की नागरिकता छिनने का काम नहीं करेगा तो फिर चिन्ता किस बात की है। हमें सपोर्ट करना चाहिए और इसलिए हमने सपोर्ट किया है। इसलिए, यह विवाद इस बात का नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, इसलिए हमने इस कानून का सपोर्ट किया है।

मैं कुछ बातें अपने क्षेत्र के बारे में भी बताना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र दादरा नगर हवेली है। भारत सरकार ने दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज करने का काम किया, हमने इसका स्वागत किया। हमने यह सोचा कि देश के प्रधान मंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे उद्देश्य के साथ यह फैसला किया है।

(1735/YSH/RC)

उस समय जब यह कानून पास हुआ था, तब मैंने यह कहा था कि प्रधान मंत्री जी ने एक अच्छी सोच के साथ ये कदम उठाए होंगे। गृह मंत्री जी ने उठाए होंगे। हम गुजरात के पड़ोसी हैं तो प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी के भी हम पड़ोसी हैं। मैं यही विषय उठाना चाहता हूं। सर, मुझे दो मिनट दीजिए। सर, मेरे दो अहम मुद्दे हैं। मैं चाहता हूं कि सभापति महोदय मुझे दो मिनट दें।

सर, जब दादर नागर हवेली और दमन द्वीव मर्ज हुए तो हमने इसका स्वागत भी किया और सपोर्ट भी किया, लेकिन साथ ही साथ हमने एक मांग भी रखी कि जो दादर नागर हवेली और दमन दीव को मर्ज किया है, उससे यह हमारा बड़ा क्षेत्र बन गया। हमारी आबादी भी बड़ी बन गई। हमारा रेवेन्यू भी बड़ा हो गया। जब दोनों प्रदेश एक हुए तो दोनों प्रदेशों के लोगों की एक ही पुरानी मांग थी और बहुत अहम मांग थी कि हम पीछे क्यों हैं? भारत का लोकतंत्र इतना बड़ा है तो दादर नागर और दमन दीव लोकतंत्र से वंचित क्यों है? हमारे प्रदेश को भी असेंबली देनी चाहिए। हमारे लोग भी लोकतंत्र के साथ जुड़ना चाहते हैं। हम इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं। हमारे यहां पर लोकतंत्र नहीं है। वहां पर लोग असेंबली के बिना इतने सालों से रह रहे हैं। हमारी जो असेंबली की मांग है, उसको सही ठहराया गया था। मेरिट के तौर पर वहां होम मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी गई थी, उन्होंने भी यह निर्णय लिया था कि दादर नागर हवेली और दमन दीव को पुड्डुचेरी की तरह असेंबली दी जाए। यह रिक्मेंडेशन हुआ है। मैं भारत सरकार से और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस पर फैसला हो।

सर, दादर नागर हवेली व दमन दीव को असेंबली दी जाए। सर, मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। सर, मैंने यहां पर दादर नागर हवेली के बारे में कई मुद्दे उठाए हैं। यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा कुपोषण का था। हमारा आदिवासी क्षेत्र है। यहां पर सबसे ज्यादा कुपोषण की बीमारी है। मैंने इस बात को पार्लियामेंट में उठाया। मैं आदरणीय रामविलास पासवान साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जब भी उनके पास गया तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि दादर नागर हवेली आदिवासी क्षेत्र है। वहां जो पीडीएस का सिस्टम है, उसको अच्छी तरह से लागू किया जाए। गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में पीडीएस के तहत जो भी अनाज दिया जा रहा है, उसी तरह से अनाज देने का काम दादर नागर हवेली का प्रशासन करे। यह भी आदेश हुआ था, लेकिन यह अभी तक लागू नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार वहां के प्रशासन को निर्देश दे कि गुजरात सरकार ने जो प्रावधान किया है, उसे यहां भी लागू करे। इसी बात के साथ मैं एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

आपने मुझे यहा पर दो शब्द बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1738 hours

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): Sir, I wish to thank you for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the Address given by hon. President. Before I speak on the Motion, I wish to express my sincere gratitude to my late mercurial leader, Puratchi Thalaivi AMMA.

We are the most fortunate to have Narendra Modi Ji as our guiding spirit to lay a strong foundation in the last five years, to make this decade India's decade, and this century India's century. He has set new standards in building the nation. Due to Government's strong commitment, several historic legislations have been enacted.

In a democracy, nothing is more sacred than the mandate given by the people. The people of the country have given this mandate to Government for the making of a new India, a new India in which adequate facilities and new opportunities for growth are available for the poor, Dalits, women, youth, tribals and minorities, a new India, where every region develops, no region is left behind, and where the benefits of modern technology reach the farthest end of society.

(1740/SRG/RPS)

I wish to thank the hon. President for including the vision and mission of this Government and its achievements in the last five years to provide a perfect platform for our country to become the world leader in the 21st century.

Our Prime Minister's success mantra is `Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas'. He is working with full commitment and sincerity. Providing free gas connections to eight crore rural poor women, houses to two crore rural and urban poor, bank accounts to about 38 crore poor, free treatment facility of up to Rs. 5 lakh to 50 crore people, and free electricity connections to over 2.5 crore is a herculean task achieved through our Prime Minister's sheer commitment and will power.

The abrogation of Article 370 and Article 35A of the Constitution by two-thirds majority in both the Houses of Parliament is not only historic, but has also paved the way for equitable development of Jammu and Kashmir and Ladakh. For this, I wish to thank the hon. Prime Minister and also hon. Home Minister.

In order to ensure the availability of sufficient quantity of potable drinking water to each rural household in the country, the Government has launched the

Jal Jeevan Mission. In the coming days, Rs. 3,60,000 crore will be spent on this scheme. This will be one of the greatest achievements of independent India. The Government has launched the Atal Bhujal Yojana with special focus on seven of the most vulnerable States of the country, where ground water level is depleting rapidly. In this regard, I wish the Government to take care of the people of Tamil Nadu and get them their per capita share of water for both drinking and irrigation.

On the special request of the Union Government, an unprecedented increase in Haj quota was made by Saudi Arabia as a result of which a record two lakh Indian Muslims performed the sacred Haj yatra. India is the first country where the entire process of Haj pilgrimage has been made digital and online. The Government is also undertaking 100 per cent digitization of Waqf properties across the country, so that these properties can be utilized for the welfare of the Muslim community. I thank the hon. President for highlighting this achievement of the Government.

Under the Prime Minister Kisan Samman Nidhi, more than Rs. 43,000 crore have been deposited in the bank accounts of more than eight crore farmer families. In January this year, the Government has created a record by transferring Rs. 12,000 crore to the bank accounts of six crore farmers simultaneously. …(*Interruptions*).

The Government of Tamil Nadu has also initiated such financial assistance to the farmers of the State and have been successfully implementing the schemes of the Union Government to prove that Tamil Nadu is second to none when it comes to follow and implement the developmental and welfare schemes of farmers. …(*Interruptions*).

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI P. RAVEENDRANATH KUMAR (THENI): I am just concluding. I am very proud to say that my state of Tamil Nadu has been chosen for the Central Government Krishi Karman Award. It may be noted that during the past eight years, under the AIADMK regime, this award has been bagged five times for which the Agriculture Department of our Union Government has congratulated the State Government under the leadership of our Chief Minister and our Deputy Chief Minister of Tamil Nadu.

Through you, I wish to thank the hon. President and hon. Prime Minister Shri Narendra Modi for giving this wonderful platform to us to come together to create a New India. Let us together make a New India and make India the world super power.

With these words, I conclude.

(ends)

*ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI):

---

*Laid on the Table.

(1745/RAJ/RU)

1745 बजे

सुश्री प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम): सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको और अपनी पार्टी को धन्यवाद देती हूं। मैं राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने अपने अभिभाषण में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास की उपलब्धियों के बारे में बताया है। पिछले पांच सालों से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, उनका जो कमिटमेंट हैं, पिछले 70 सालों में नॉर्थ-ईस्ट में जितना डेवलपमेंट हुआ है, उससे कई गुणा ज्यादा डेवलपमेंट पिछले पांच सालों में मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ-ईस्ट में हुआ है। इसका सीधा-सीधा ऐसा प्रमाण है कि थर्टीन्थ फाइनैंस कमिशन में नॉर्थ-ईस्ट के एनईसी के लिए 3,376 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद फोर्टीन्थ फाइनैंस कमिशन में उसके लिए 5,053 करोड़ रुपये का एलोकेशन किया गया था, जो डेढ़ गुणा ज्यादा फंड है। कांग्रेस की जितनी सरकारें थीं, किसी भी प्रधान मंत्री ने एनईसी की बैठक में भाग नहीं लिया। हमारे प्रधान मंत्री ने शिलाँग में जाकर एनईसी की बैठक में भाग लिया, तो उत्तर-पूर्वांचल के लोगों को मालूम हुआ कि हम भारत से बाहर नहीं हैं, हम भारत के पार्ट हैं। भारत में हमारा कोई अभिभावक है। हम लोगों को देखने वाले और सुनने वाले प्रधान मंत्री मिले हैं। 16 साल पहले मोरारजी देसाई एनईसी की बैठक में गए थे, उसके बाद एक ही प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी हैं, जो शिलाँग में एनईसी की बैठक में जा कर उत्तर-पूर्वांचल के प्रति जो प्रतिबद्धत्ता जताई है, उसके लिए उन्होंने काम किया है। उत्तर-पूर्वांचल में गुवाहाटी को छोड़ कर कोई भी स्टेट रेल के मानचित्र में नहीं था। वर्ष 2014 से वर्ष 2022 तक हर एक स्टेट की राजधानी रेलवे के मानचित्र में आ जाएगी, अगरतला बहुत पहले रेलवे के मानचित्र में आ गया है। इसीलिए मैं पूर्वोत्तर के सभी भाई-बहन की तरफ से प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

हमारी पहचान भू-राजनीतिक नहीं है। हमारी पहचान भू-सांस्कृतिक है। उत्तर-पूर्वांचल का इतिहास बहुत रिच था, लेकिन पूर्वोत्तर सरकारों ने उसको अलग-थलग कर दिया था, पूर्वोत्तर के साथ सौतेला व्यवहार किया। बोडोलैंड मणिपुर में है, वहां 365 दिनों में से 200 दिन ब्लॉकेड रहता था। त्रिपुरा में उग्रवाद की समस्या थी। बोडोलैंड में 30-40 साल से जो प्रॉब्लम था, उसको प्रधान मंत्री जी ने सुलझा दिया। पहले की सरकार का काम था कि समस्या को लटका कर रखना है, लेकिन हमारी सरकार का काम है, प्रधान मंत्री जी का काम है कि जो समस्या है, उसका समाधान करना है। त्रिपुरा की 'ब्रू' समस्या, वर्ष 1997 में मिजोरम से रियांग, भाई-बहन शरणार्थी त्रिपुरा में आए थे। बहुत सरकारें आईं और गईं, लेकिन उन्होंने त्रिपुरा के 35 हजार शरणार्थियों के दर्द को नहीं समझा, लेकिन 23 साल बाद हमारे प्रधान मंत्री जी ने उस दर्द को समझा और 35 हजार रियांग शरणार्थियों को त्रिपुरा में रहने के लिए 600 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की। मैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी और अपने प्रधान मंत्री जो को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने हमारे 'ब्रू' जनजाति के लोगों के लिए स्थायी समाधान निकाला है। बोडोलैंड की समस्या थी, सभी लोग डरते थे। 30-35 सालों में चार हजार लोगों की हत्या हुई थी, उसके बाद संपत्ति का नुकसान हुआ, लोगों को घर-बार छोड़ कर जाना पड़ा, वहां पर हमेशा बंद का आयोजन होता था, इस बड़ी समस्या का समाधान हमारे प्रधान

मंत्री जी ने कर दिया है। मैं उसके लिए पूर्वोत्तर की तरफ से, असम की तरफ से हमारे सौराष्ट्र मंत्री अमित भाई शाह और अपने प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

इसके अलावा हमारे उत्तर-पूर्व के प्राकृतिक संपदा को काम में लिया, जैसे, त्रिपुरा के पाइन एप्पल और बांबू जैसे प्राकृतिक संपदा का व्यवहार करके हमारे उत्तर-पूर्वांचल में साल में कम से कम एक लाख करोड़ रुपये का बिजनेस कर सकते हैं। प्रधान मंत्री जी ने उस प्रतिबद्धता को नॉर्थ-ईस्ट में दोहराया है। उन्होंने एनईसी को जो पैसा दिया, पहले कोई स्टेट को भी नहीं देखता था, उन्होंने गांवों को सेलेक्ट करके, जहां पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जहां रास्ता नहीं है, वहां रास्ता निर्माण करने के लिए, बिजली देने के लिए, शौचालय का निर्माण करने के लिए एनईसी का जो फंड है, वहां से 30 प्रतिशत फंड खर्च करने के लिए कहा है। जिन्होंने पहले स्टेट को नहीं देखा, वहां पर हमारे प्रधान मंत्री वहां गए और गांवों का डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए प्रतिबद्धता जताई है।

(1750/NKL/VB)

इसके अलावा, हम लोग जानते हैं कि जो सबसे बड़ा बोगीबील ब्रिज है, उसका उद्घाटन हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया है। अगले कुछ सालों में उत्तर-पूर्वांचल के आठ राज्यों में प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने के लिए उनको गैस-ग्रिड से जोड़ने के लिए नौ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उत्तर-पूर्वांचल में गैस पहुँचाने के लिए लाइन बिछाई जाएगी। इससे उत्तर-पूर्वांचल के राज्यों को फायदा होगा, ऐसी प्रतिबद्धता दोहराई गई है।

माननीय सभापति (श्री कोडिकुन्निल सुरेश): मैडम, अब समाप्त करें।

सुश्री प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम): कृपया थोड़ा टाइम और दीजिए।

HON. CHAIRPERSON: No, your time is over.

सुश्री प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम): अरुणाचल प्रदेश के लोग कभी सोचते भी नहीं थे कि यहाँ एयरपोर्ट होगा। वर्ष 2022 तक अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट का निर्माण हो जाएगा। यह बात भी उसमें है।

नॉर्थ-ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग करके रखा गया है। नॉर्थ-ईस्ट का भौगोलिक क्षेत्रफल यूपी जैसा है, जो इंडिया के क्षेत्रफल का 9 परसेंट है। यहाँ की जनसंख्या मात्र पाँच करोड़ है। इसलिए वहाँ पर बहुत-सी संभावनाएँ हैं। उन संभावनाओं को देखते हुए प्रधान मंत्री जी ने उत्तर-पूर्वांचल के लिए न्यू इंडिया की तरह काम करने की प्रतिबद्धता जताई है।

सिक्किम सहित पूरे उत्तर-पूर्वांचल के राज्यों को प्रधान मंत्री जी ने 'अष्ट लक्ष्मी' कहा है। केवल 'अष्ट लक्ष्मी' कहा ही नहीं है, बल्कि उनके लिए वे काम भी कर रहे हैं। अभी उत्तर-पूर्वांचल खुशहाल है। वहाँ उग्रवादी खत्म हो गए हैं। वे कम नहीं हुए, समाप्त हो गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उत्तर-पूर्वांचल में कुछ नहीं किया है। पिछले पाँच साल में उत्तर-पूर्वांचल में जितनी तेजी से डेवलपमेंट हुए हैं, उतनी पिछले सत्तर सालों में कई राज्यों में नहीं हुए हैं। मोदी जी ने उत्तर-पूर्वांचल को इतना डेवलप किया, हमको एयर कनेक्टिविटी दी, रोड कनेक्टिविटी दी और अभी 'भारत माला' प्रकल्प में आठ हजार करोड़ रुपये का काम त्रिपुरा में होगा। इसी तरह से रेस्ट ऑफ नॉर्थ-ईस्ट में पूरी तरह से रोड कनेक्टिविटी होगी।

माननीय सभापति: मैडम, मैंने आपको ज्यादा टाइम दे दिया, so please conclude now.

सुश्री प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम): एसईज़ेड के बारे में हम लोग सोचते भी नहीं थे। हमारे प्रधान मंत्री जी ने त्रिपुरा में एसईज़ेड दिया है। त्रिपुरा के अगरतला में उन्होंने स्मार्ट सिटी दी है। स्मार्ट सिटी की माँग के अंतर्गत हम लोग नहीं आते हैं, लेकिन उसको थोड़ा कम करके हमें स्मार्ट सिटी दिया है।

माननीय सभापति: मैडम, क्या यह आपकी मेडन स्पीच है?

सुश्री प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम): नये भारत के साथ-साथ एक नया उत्तर-पूर्वांचल का गठन करने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। हम प्रधान मंत्री जी के साथ हैं। इसके साथ ही हम प्रधान मंत्री जी के अभिभाषण का समर्थन करते हैं। आगे चलकर उत्तर-पूर्वांचल भारतवर्ष को एक नई दिशा दिखाएगा और अर्थ-नीति को स्थिर करेगा।

(इति)

1753 hours

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Hon. Chairperson Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks to the Address made by the hon. President of India in the Joint Sitting of the Parliament.

Sir, I oppose the Motion because of the following reasons. I appreciate the vision given in the Address by the hon. President that this decade will be India's decade and that this century will be India's century, but I do not know how it can be achieved. Everybody knows, and even the hon. Finance Minister in the Budget Speech accepted the fact, that we are having a slowdown economy. Our GDP is at 4.5 per cent to 5 per cent. The industrial production is coming down. Unemployment is at the highest level during the last 45 years. I am sure that this vision will remain as mission unachieved, and we cannot have a hope to be on the top of the world as far as India is concerned.

Sir, India is being divided on the basis of religion. A lot of discussion has been made in this House itself and agitation is going on all over the country. It is unfortunate that the name of the Father of the Nation was compelled to be brought in by our hon. President for implementing CAA, NRC and NPR.

(1755/KSP/PC)

Sir, I am sure that the Government would not be able to implement these changes by dividing the country on the basis of religion. We have a secular democratic system in India and that is being distorted. This should not be allowed.

The farmers of the country are in distress. I have raised this issue three times in this august House. The farmers, whether they are growing cash crops or food crops, all are facing serious problems throughout the country. They are not getting enough price for their produce. They should get a minimum of 150 per cent over the cost of production. Then only farming will be profitable and they will be able to survive. But they are not even getting the cost of production and the farmers are in distress.

We have entered into more than 14 Trade Agreements with various countries and these Agreements allow import of agricultural produce into our country due to which our farmers are not in a position to compete with the agricultural produce being imported.

We have the largest production of natural rubber in Kerala and around 95 per cent of our country's rubber production is coming from Kerala. The farmers in Kerala are not in a position to continue with rubber production and they are facing very serious problems for the last 10 years. We have been asking both the State Government as well as the Central Government to give some concessions so that they can come out of their problems. Unless they get Rs. 200 per kilogram of rubber, they cannot go ahead with production of rubber. The Government of Kerala has introduced a programme wherein a minimum of Rs. 150 per kilogram of rubber was assured to them. But that programme is not being implemented now. So, I request the Government of India to implement some programme wherein the rubber farmers will get a minimum of Rs. 200 per kilogram of rubber that they produce.

The different Trade Agreements which our Government has entered into with various countries should be reviewed. These Agreements have been entered into with many countries without being discussed in the Parliament. All these Agreements have been unilaterally entered into by the Government. So, these Trade Agreements should be discussed in the Parliament and only then, they should be allowed to be implemented.

Sir, the President's Address boasts that the National Clean Air Programme would be implemented in 102 cities. But I am sorry to say that the Government could not give clean air to the people living in the National Capital City of Delhi. When they are boasting of implementing this scheme in 102 cities, I do not know how it is possible and I do not think it is going to be implemented properly.

I have another issue which I want to mention here. Namami Ganga Mission is for cleaning the River Ganga. It is mentioned in the President's Address that Rs. 7,000 crore have already been spent on this programme and an amount of Rs. 21,000 crore are expected to be spent within a short span of time. But Kerala is having 44 rivers and most of them are polluted. We have the Vembanad Lake is a world-famous backwater lake and this is one of the best tourist spots of the world. So, I request the Government of India that some funds should be allotted for cleaning the Vembanad Lake as well as the rivers in Kerala.

As far as education is concerned, the President's Address states that the Government is giving priority to education, especially for Kendriya Vidayalayas. Unfortunately, I have to say that the fees in Kendriya Vidyalayas have been increased more than double the amount.

(1800/KKD/SPS)

Now, the parents are asked to pay five years' arrears in fees. Poor parents find it very difficult to pay back the fees, which is in arrears. I would, therefore, request the Government to waive these arrears, that is, the amount of fees increased in the Kendriya Vidayalayas.

There is one more point. Afterwards, I would conclude my speech. It is about the education loan. They are offering education loans. But there are so many conditions imposed. Last day, I got a reply from the hon. Finance Minister that the education loans are given with certain norms fixed by the IBA and RBI. If you go through the norms, it seems very easy to get this loan. But the banks are still insisting on collateral securities. Applications are not processed within the stipulated 15 days. The applicants are not communicated whether their applications have been accepted or not and the loan sanctioned or not. Hence I would request the hon. Minister to do something about it.

With these words, I conclude. Thank you.

(ends)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Hon. Members, it is 6 o'clock now. I have a list of 10 more speakers to speak on this Motion of Thanks on the President's Address. If the House agrees, the time for this Discussion may be extended by one hour.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Not by one hour, but by half an hour.

HON. CHAIRPERSON: We have 10 speakers yet to speak. One hour is all right.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: All right. So, the time of the House is extended by one hour.

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, the Minister of State is present here. I have got some urgent work. Please allow me to leave.

HON. CHAIRPERSON: Okay. The Chair has no objection.

Now, Shri Shrirang Appa Barne. Kindly conclude your speech within four minutes. So, make it fast.

***श्रीमती रक्षा निखिल खडसे (रावेर):**

---

* Laid on the Table

1803 बजे

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 वीं सदी में नए दशक के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में केन्द्र सरकार की विभिन्न सफलताओं को रेखांकित किया गया है और आंकड़ों के माध्यम से अनेक योजनाओं से कितने लोगों को लाभ मिल सकता है, इसका ब्यौरा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में है। इस भाषण में न्यू इण्डिया की स्थापना की बात की गई है। मैं सभी सांसदों से अपील करता हूं कि इस देश की जनता की आशाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति और राष्ट्रहित के लिए सब मिलकर काम करें। सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से विभिन्न आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिनमें उज्ज्वला योजना के माध्यम से 8 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है, 2 करोड़ गरीबों को घर दिया गया है, 38 करोड़ गरीबों को बैंक खाते दिए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसका जिक्र मेरे नेता आदरणीय बाला साहेब ठाकरे हमेशा करते थे, मुख्य मंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी ने उसकी पूर्ति के लिए सरकार को सपोर्ट किया है। यह पहला निर्णय है कि धारा 370 और अनुच्छेद 35A को हटाने का सरकार ने जो उल्लेखनीय कार्य किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

सरकार का दूसरा निर्णय राम मंदिर के बारे में हैं। सरकार ने राम मंदिर का जो निर्णय लिया है, यह सराहना करने योग्य है, देश के हित में है, अच्छा निर्णय है, मैं इसकी सराहना करता हूं। मेरी पार्टी हमेशा देश हित के निर्णय में, देश के लिए अच्छे निर्णय में, देश की प्रगति के निर्णय में सरकार के बाजू में रही है। सरकार ने बीते वर्षों में ऐसे कई निर्णय लिए हैं, जिनका मेरी पार्टी विरोध करती है। इनमें मुख्य रूप से नोट बंदी के बारे में मेरी पार्टी ने शुरू से विरोध किया था। नोटबंदी के कारण महंगाई और बेकारी दिन-प्रतिदिन बढ़ी। कई उद्योग बंद हुए, कई युवाओं को रोजगार नहीं मिला। सरकार ने घोषणा की थी कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज देखा जाए तो कई युवा बेकार हैं। देश में युवकों को नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे यहां पूना, बैंगलुरू और हैदराबाद में आई.टी. हब्स हैं। आई.टी. हब्स में कई युवा बेकार हुए हैं, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कृषि के लिए, खासकर किसानों के लिए बड़े पैमाने पर घोषणा की गई है। सरकार ने घोषणा की थी कि वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करेगी।

(1805/MM/RP)

इस लक्ष्य की घोषणा सरकार ने की थी। लेकिन वास्तव में आमदनी दोगुनी नहीं हुई है। किसानों की हालत अभी भी वैसी ही है। कई सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार का उस पर ध्यान नहीं है। महाराष्ट्र में बाढ़ आई थी, जिसके कारण बहुत नुकसान हुआ है। केन्द्र सरकार से महाराष्ट्र सरकार ने मांग की थी और बहुत थोड़ी रकम केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को दी है। आज भी बड़ी रकम देना बाकी है। मैं इस तरफ भी केन्द्र सरकार का ध्यान लाना चाहता हूं।

महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा आवास योजना की घोषणा की गई थी। कई सारे ग्रामीण और शहरी इलाकों में इस योजना पर अमल चल रहा है, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को फण्ड नहीं देने के कारण यह योजना रुकी हुई है। मैं दो-तीन बातें यहां कहना चाहता हूं कि आज देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 15 करोड़ घर ऐसे हैं, जहां पाइप से पानी की सप्लाई नहीं होती है। दूषित पानी पीने से कई सारे लोगों को बीमारियां हो रही हैं। खास तौर से कैंसर की बीमारी हो रही है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने नदी विकास प्रकल्प के लिए 3850 करोड़ रुपये की मांग की है। लेकिन सरकार ने उस पर आज तक ध्यान नहीं दिया है। पूरे देश की नदियों में सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जिन योजनाओं की घोषणा की है, उनको पूरा किया जाए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1807 hours

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Thank you, Chairman, Sir, for this opportunity to speak in support of the Motion to thank the hon. President for his Address to the Parliament.

The hon. President's Address lays down a very magnificent and clear roadmap for reconstruction of this great civilisation and rebuilding of a new India. One of the characteristic traits of this Government led by our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, has been its insistence on solving long-pending issues with a very decisive nature. A new India cannot be built without healing the wounds of the past, without addressing the issues that had confronted this nation for a very long time and without bringing closure to a lot of pressing national issues which had drained this country's energy. It is to the credit of the Prime Minister's vision and decisive leadership that many issues of the past have been addressed and have been given a closure.

Take for instance Article 370. This issue was pending since the time of our Independence. The Prime Minister's leadership and this Government's decisiveness has put an end to this continuous separation, phycological, constitutional, legal and most importantly emotional, that people of Jammu and Kashmir as well as the mainland of India faced for the last 70 years. Article 370 was used as a wedge by Pakistan to further its vested interests in Kashmir and further Islamic terrorism in Jammu and Kashmir. But, Sir, with the abrogation of Article 370, a 70-year old pending problem has been put to rest and we have moved on.

In the same way the issue of tripal talaq has been taken up. A long-pending issue, ensuring justice is given to a young Muslim woman, was addressed decisively by this Parliament and by this Government.

Sir, the injustice was meted out to Hindus of this country 500 years ago, when the great Ram Mandir in Ayodhya was desecrated and demolished by Babar and it had to be redone or rebuilt. People waited for 500 years and in the last so many years, people made continuous efforts legally, constitutionally, politically or through mass movements or through spiritual movements to rebuild this temple.

(1810/RCP/SJN)

But it took the Prime Minister and his decisive leadership to ensure that a great and a big issue like this, a festering wound which had created so much of conflict in the society, even that was addressed. Today, it is a great moment, a red-letter day in India's civilizational history because the Prime Minister addressed the nation and made the statement that the magnificent construction of Ram Mandir is only a few months or a few days away. A big issue is now closed.

In the same manner, whether it was the Bodoland issue, whether it was the issue of Bru or Reang, all of these issues which were pending for the last six decades, seven decades, have been given a closure.

When the country was partitioned, the issue of those people who stayed back in Pakistan and erstwhile East Pakistan was a very important issue that needed to be addressed by this country. No Government decided to take the issue head on. From Mahatma Gandhi to Jawaharlal Nehru to even Manmohan Singh when he spoke in this very house and demanded citizenship rights to Sikhs and Hindus from Pakistan, all of them, irrespective of political parties, spoke in one tone and wanted justice to those refugees who came to India unable to bear the religious persecution in Pakistan. It was our Government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and the decisive, visionary leadership of hon. Home Minister Amit Shah *ji* which passed the historic Citizenship (Amendment) Act to ensure that these persecuted religious minorities get justice.

What is extremely disappointing, what is extremely troubling is that the Opposition of this country knowing full well that these legislations especially the Citizenship (Amendment) Act has nothing whatsoever to do with taking away citizenship from anyone, has gone around the country indulging in a campaign of *… (Not recorded)*, a campaign of slander misguiding the people of this country. I want to ask all those leaders in the Opposition how they will face the next generation of this country. How will they face the young generation of this country when every single day they are on a campaign based only on untruth and *… (Not recorded)*?

What is happening today in Shaheen Bagh in Delhi is a stark reminder that if the majority of this country is not vigilant, if the patriotic Indians do not

stand up to this, the days of Mughal *raj* coming back and revisiting Delhi is not very far away. What is happening in Shaheen Bagh is fanatic *… (Not recorded)* masquerading in the garb of Constitutional secularism. Therefore, we must exercise vigilance to ensure that this country will be on a path of true secularism. …(*Interruptions*)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): We will not allow this. …(*Interruptions*) You are insulting the protesters. …(*Interruptions*)

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Sir, I will not yield. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Kanimozhi *ji*, if anything is wrong, it will be removed from the record.

… (*Interruptions*)

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Every single day, you have been engaging in a campaign…(*Interruptions*) You are misguiding the young people of this country. …(*Interruptions*)

I want to ask all of you. People say CAA is unconstitutional. My question to the Opposition is this. In 2019 the Members of the European Parliament visited Pakistan and came up with the report on the state of religious minorities in Pakistan. I want to ask the leaders in the Opposition. This is what the report says, and I am quoting from the European Parliamentarian's report because you take their word to be gospel more than the Indian leaders. …(*Interruptions*)

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): We do not take them; you take them. …(*Interruptions*)

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): I want to ask all of you. …(*Interruptions*) What did Sonia, a nine-year-old girl belonging to the Christian community have to face? …(*Interruptions*) She was abducted and she was raped …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Come to the subject.

… (*Interruptions*)

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Sir, Varsha, a 12-year-old Hindu girl was abducted, forcefully converted and she was killed. Monika, a 11-year-old girl from Sikh community was abducted, raped and issued death threats.

(1815/SMN/GG)

What the Opposition is trying to do today is to stop the eleven year old girl and a nine year old girl from getting citizenship here? You are denying them justice. What you are doing is unethical; what you are doing is unjust; what you are doing is inhuman and this country will remember, this country will remember this bigotry of this Opposition. …(*Interruptions*)

I also want to answer their argument that why is it that the CAA is not giving citizenship to the Muslims of Pakistan and Bangladesh.

Sir, how can both the persecutor and persecuted be seen on an equal footing? Article 14 not only mandates us to treat the equals equally but it also commands that the unequals must be treated unequally. You cannot equalise. You cannot equalise the perpetrator and the persecutor on the same footing. It will be a violation of Article 14 and also the fundamental principle of equality.

Sir, CAA has brought closure to the issue of refugees from these two countries and has heeled the wounds of partition. What the Opposition wants is that the Opposition does not want all of these problems to be closed. They want these wounds to continue festering so that they can continue with their vote bank politics every single day. They want their vote bank politics to continue whereas Sir, we want to build a new India and we know that a new India cannot be built unless the wounds of the past are heeled, the old chapters are closed and new chapters are opened which is why this Government is a problem-solving Government and I am proud to belong to a young generation which is a problem solving generation of India. I represent the problem-solving generation of India which does not hesitate to solve problems.

Sir, I just want to conclude by bringing two important points to the attention of this august House. Winston Churchill while speaking on defining who a fanatic is very clearly said that a fanatic is a person who does not change his mind nor change the subject. I have heard the Opposition Parliamentarians since yesterday. All of them have been speaking only on issues that are destructive to the secular fabric of this country.

Sir, I do not want to spend much time on that because under the leadership of this Prime Minister, a new India is rising and I want to bring your attention to this new India that is rising.

I just want to make two more points. In 1998, when Abdul Kalam Ji was the President of this country, we were all in school and he laid down a very grand vision of 2020: India, a superpower. In his grand vision, he focused on how India could rise to be a technological superpower to achieve the status of a global leader. Today, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, this technological vision of Shri Abdul Kalam has found implementation and execution.

Just three areas in which we will see this all pervasive technology being put into action into good governance. I would not want to take much of your time. I will conclude in two minutes. …(*Interruptions*)

Good governance is most essential to bring this country out of poverty and to build this new India. And technology is the backbone of governance of our Government.

If we look at Aadhar, DBT, Jan Dhan, mobile, Fastag, Rupay cards, all of these technological platforms today are platforms of good governance. One will realise how all pervasive good governance is based on technology today. Just on the basis of DBT – Direct Benefit Transfer – the country has saved more than one lakh seventy thousand crore rupees.

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Please conclude.

…(*Interruptions*)

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Kanimozhi Ji, I want to draw your attention to the fact that one lakh seventy thousand crore rupee was saved. Perhaps you will understand the magnitude if I say that the country lost one lakh seventy thousand crore rupees in the 2G scam. The amount of money that the country lost in the 2G scam, this country is saving just by the Direct Benefit Transfer. Not just that, 121 crore people have got an Aadhaar cards. Sixty crore people have got Ru Pay cards. More than two lakh crore rupees in December, 2019 was the transaction amount under UPIs.

(1820/VR/KN)

Sir, about 450 schemes of this Government, including important schemes like the Pradhan Mantri Awas Yojana are all based on digital technology, geotagging. You may remember the days of Indira Gandhi Awas Yojana where no beneficiary had clear idea where the money was going. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): You have covered almost all the points. Please conclude.

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): But, today, from Indira Awas Yojana to Pradhan Mantri Awas Yojana, the country has taken a big leap and has done a full circle of transparency and efficiency. ....(Interruptions)

In 1978, this country had a very big opportunity of becoming the biggest manufacturing hub, the factory of the world. But we missed that last bus of industrialization because the Government of the day was more interested in *mandal-kamandal* politics. The country's politicians of that day were in fairy tale of socialism and, therefore, in 1978, when China opened its doors for liberalization, we were sleeping and were in a deep slumber. *....(Interruptions)*

But, today, Sir, we have a Government which is pro-active. *....(Interruptions)* I must congratulate our Government for sailing with the times. *....(Interruptions)* Today, in the Budget, an amount of Rs.8000 crore has been allotted just for quantum computing research in this country. With Industry Revolution 4.0, India will not be a bystander, India will be a leader and will be watching it happen. *....(Interruptions)*

Sir, I would just want to conclude by congratulating the hon. Prime Minister for the leadership he has given to this country. I must, on behalf of young India, which is at the forefront of this innovation, which is at the forefront of this technological revolution, thank him for giving this much needed leadership to this country. *....(Interruptions)* I also thank the hon. President for the blueprint he has put before the nation. Thank you, Sir. *....(Interruptions)*

(ends)

1822 hours

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): Thank you, Sir. Once upon a time, there was an emperor who loved his clothes. He spent all his money and time showing off his fancy new clothes.

One day, two fraudsters, two tricksters came to the emperor. They promised the emperor to make the best clothes he ever had. These tricksters then pretended to stay up the entire night, of making the emperor's clothes and to sew with needles without any thread. Finally, they went to the emperor and announced that his beautiful clothes are ready.

The fraudsters then asked the emperor to remove his clothes. They pretended to dress him piece by piece with new ones. Finally, the emperor decided to show off his new clothes. When he walked on the streets, nobody dared to question the emperor because he was an emperor. But, one little child shouted out loud that the emperor is naked!

Upon hearing our President's Address, the praises he showered upon this Government's new India, and, just as the hon. Member, Shri Tejasvi Surya has mentioned about the new generation and the aspirations of New India, I want to know where is it now and where are we? I feel like that child and I wish to ask this House, is not our emperor naked? Is not our emperor naked and fooled by two fraudsters who promised to build a new India?

Our President repeated this Government's rhetoric of 'A 5 Trillion Dollar Economy for a New India'. I am flattered and so are the millions of sensible Indians waiting for some magic.

Sir, we are aware, India is having its worst economy in 42 years. For the past six quarters, the GDP growth rate has been falling. The President says that India will become a 5 trillion Dollar economy by 2024. Is it a sensible dream? One of my hon. friends here has pointed out that our economy should ideally be growing at 12 per cent for us to reach a 5 trillion Dollar economy. Look at where we are! We only had 6.1 per cent in the second quarter of the financial year, 2019-20. Will this dream ever happen, or, our emperor still wants to be naked?

(1825/SAN/CS)

Our private consumption is the lowest in seven years. Investments are at a 17-year low at one per cent. Manufacturing is at a 15-year low at two per cent. Agriculture at 2.8 per cent is the lowest in four years.

I wish to ask the Government: Why do you promise this empty dream to the millions of people in this country? And yet, our President repeats after the Government. He has said that the fundamentals of the economy are strong. We must remember that President George Bush had said the same words few weeks before the collapse of Lehman Brothers. We should also know that President Herbert Hoover had said the same line just before the great depression of 1929. I wish to ask this House: Are the fundamentals of our economy really strong? Or, is it that our emperor is naked?

Our President has said that LPG connections – Mr. Raveendranath Kumar mentioned it earlier - were given to eight crore poor Indians, but here is the stark reality that 3.18 crore beneficiaries were declined refilling consumption of 3.21 refills *per annum* and the prices of subsidised LPG cylinder have increased 13 per cent in the past six months. They do not have the capacity to buy them.

Our President spoke about farmers' welfare and that his Government deposited Rs. 43,000 crore into eight crore accounts. Here is the reality. An RTI report reveals that almost 75 per cent of farmers have not received three instalments in the first year of our Pradhan Mantri's Kisan Scheme. To receive the fourth instalment, bank accounts will have to be linked to Aadhaar. Approximately 13 million farmers in UP alone will be affected. How can the President of this great nation represent distorted facts of this Government? Is our emperor not really naked?

I want to ask what the real development in Jammu and Kashmir and Ladakh is that our President is talking about. On August 5, nearly 4,000 persons were detained without any charge – political party leaders were placed under house arrest – and some of them are still nowhere to be seen. All of this is a blatant violation of India's obligations under international human rights law. The communication blockade imposed on the people of Kashmir is the longest ever Government-imposed internet shutdown in India. The Kashmiri economy

suffered a loss of nearly Rs. 18,000 crore. This too is the stark reality of the new India under Modiji's rule.

In 2018 alone, there have been 86 instances of cow-related lynchings. The conviction rate for violent crimes against Dalits is only 23.8 per cent. The conviction rate for violent crimes against indigenous tribes is a mere 16.4 per cent.

To my horror, our President used the name of Mahatma Gandhi to glorify the wretched law – the Citizenship (Amendment) Act. How could anyone invoke the name of the Father of this Great Nation, who taught nothing but truth and non-violence, to glorify a law that has brought fear and frenzy to 200 million Muslims in India? This Government, unfortunately, is weakening the protection guaranteed to our minorities by our Constitution. And yet, our emperor likes to remain naked!

Do we have any economic agenda? Or, are we blindfolded by the fog of political nationalism? I wish our President will come out to face the reality like all of us sitting here and get himself out of his 'Modi-fied' reality and acknowledge that India is going through an economic crisis.

Sir, with more power comes more responsibility. Our President is not a rubber stamp. Our President cannot become a rubber stamp. Our President is the most powerful citizen of our great nation. He has the power to declare an emergency, suspend rights, dissolve State Assemblies and even declare the Government bankrupt.

All that I ask him is to come out. I request our President, I plead with the President of India to come out and speak the truth - speak the truth for the sake of the people of this nation and speak the truth for our future generations.

Thank you.

(ends)

(1830/RV/RBN)

1830 hours

SHRI S. VENKATESAN (MADURAI):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri S. Venkatesan, in Tamil,
please see the Supplement. (PP 434-A to 434-B)}

1833 बजे

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं।

महोदय, भारत का संविधान हम सभी देशवासियों का मार्गदर्शक है, लेकिन इसी देश में कुछ दिनों पहले भारत के संविधान को तार-तार करने और बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए इस लोकतांत्रिक देश में संविधान की प्रतियों को जन्तर-मन्तर पर सरेआम जलाया गया, लेकिन सरकार द्वारा कोई कड़ा कदम न उठाए जाने पर सरकार की मंशा और नीयत में खोट नजर आती है। मेरा मानना है कि इस तरीके के कार्य करने वाले लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और इस तरह के मुकदमों को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में चलाकर त्वरित रूप से इसका निस्तारण किया जाना चाहिए, जिससे कि देश के संविधान के प्रति लोगों की आस्था बनी रहे।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में 112 जिलों को आकांक्षी जिले का दर्जा देकर इन जिलों में रहने वाले गरीबों के विकास से जुड़ी एक-एक योजना पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है, लेकिन यह आवश्यक है कि सही मायने में जो गरीब हैं, उन्हें बिना किसी भेदभाव के चिह्नित किया जाना चाहिए। यदि इनके चिह्नीकरण में कोई त्रुटि प्राप्त होती है तो चिह्नीकरण करने वाले अधिकारी व चिह्नित व्यक्ति के ऊपर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे गरीबों के हक और हकूकों की लूट न हो सके। मेरे कहने का आशय है कि गरीबों के लिए तो कई सारी योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का लाभ कई अपात्र लोगों को मिला है, जिससे गरीब आदमी इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह गया है।

(1835/MY/SM)

सभापति महोदय, एक तरफ सरकार का कहना है कि 12 सरकारी बैंक मुनाफे में रहे हैं। सरकार का अपना पीठ थपथपना अच्छा नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि कुछ आर्थिक भगोड़े सरकार की नाक के नीचे से अपना देश छोड़ कर नहीं भाग पाते और इन सरकारी बैंकों के मुनाफे का स्तर कहीं और अधिक होता। जिन कर्मचारियों ने यह अपराध किया है, सरकार उन कर्मचारियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने यह बताया है कि इस्लामिक देश में अल्पसंख्यकों पर होने वाला अत्याचार बढ़ा है। यह सच है और हम भी इसको मानते हैं। लेकिन हम अपने देश में भी देख रहे हैं कि एक विशेष धर्म संप्रदाय के लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। अत: मुझे यह कहना है कि सरकार यदि संविधान के अनुरूप काम करे तो इस प्रकार के अत्याचारों का स्थान अपने देश में कहीं नहीं रहेगा। अत्याचार चाहे अपने देश में हो, चाहे विश्व के किसी भी स्थान में हो, मैं और हमारी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी इसकी घोर निंदा करते हैं। हम राष्ट्रपति जी से यह अनुरोध करते हैं कि सी.ए.ए. जो कि विभाजनकारी और असंवैधानिक कानून है, उस पर पुनर्विचार करें और इसे वापस लेने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1837 hours

SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri K. Subbarayan, in Tamil ,
please see the Supplement. (PP 436-A to 436-C)}

(1840/CP/AK)

माननीय अध्यक्ष : सदन का समय बदल गया है कि सीपीआई नए जमाने में नेहरू जी की बड़ाई कर रही है। देखिए समय में परिवर्तन हो गया है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य, जो बोलने के इच्छुक हैं, तीन मिनट में बोलना चाहें, तो सदन में बोलने की अनुमति है, नहीं तो मना कर दें। केवल तीन मिनट।

श्री जुगल किशोर शर्मा।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): अध्यक्ष महोदय, मेरी रिक्वैस्ट है कि जम्मू-कश्मीर से एक ही सदस्य हैं और हमारी पार्टी का टाइम भी है, इसलिए इनको थोड़ा ज्यादा समय दे दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : फिर बाकी सदस्यों का समय कट जाएगा।

…(व्यवधान)

1841 बजे

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में बोलने का मौका दिया है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में भारत में हो रहे विकास के बारे में बात की और भारत के लोगों की बेहतरी के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि भारत की उन्नति एवं तरक्की के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2014 से पहले कांग्रेस ने भारत की क्या दुर्दशा कर रखी थी। उस समय महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अफरातफरी का माहौल, असुरक्षा, नार्थ-ईस्ट के प्रदेशों में न विकास और न ही वहां की समस्याओं को सुलझाने का कोई प्रयास और भारत बर्बादी के कगार पर आकर खड़ा हो गया था। यह सारी कांग्रेस की देन थी। जैसे ही मई, 2014 में माननीय नरेन्द्र भाई मोदी देश के प्रधान मंत्री बने, तो उनके नेतृत्व में देश का चहुँमुखी विकास शुरू हो गया। मोदी सरकार ने बिना भेदभाव के देश के हर नागरिक की चिंता की और हर वर्ग को इसांफ देने काम किया। गांव, गरीब, किसान के साथ-साथ युवाओं, माताओं, बहनों के लिए, गांव-गरीब के लिए उज्ज्वला, आयुष्मान, हर घर बिजली, प्रधान मंत्री आवास योजना के माध्यम से आम आदमी और गरीब आदमी को राहत देने का प्रयास किया और उसमें वे सफल भी रहे।

अध्यक्ष महोदय, कामों के आधार पर लोगों ने मोदी जी के ऊपर विश्वास प्रकट किया और वर्ष 2019 में दोबारा बहुमत के साथ 303 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और नरेन्द्र भाई मोदी प्रधान मंत्री बने और "सबका साथ, सबका विकास" जो नारा था, वह कारगर सिद्ध हुआ।

अध्यक्ष महोदय, नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने पिछले पांच सालों में ऐतिहासिक और साहसिक कदम इस देश की बेहतरी के लिए उठाए और उसके बाद वह क्रम जारी रहा। चाहे 370 की हम बात करें, तो 370 को हटाने का कार्य ऐतिहासिक और साहसिक था, जिसे नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किया। हम बताना चाहते हैं कि 370 ने हमें दिया क्या था? आतंकवाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और दूरियां बढ़ाने का काम ही 370 और 35ए ने किया था।

सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर में हुई कि पंचायतों के इलेक्शन कराए गए। इलेक्शन के बाद पंचायतों को अपने अधिकार दिए गए। आज पंचायतों के विकास के लिए जो फंड्स केंद्र से रिलीज होते हैं, उसमें पूरा पैसा पंचायतों के खातों में जाता है। इससे पहले राजीव गांधी, जो प्रधान मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा था कि केन्द्र से 100 रुपये जाते हैं और 15 रुपये ही वहां पहुंचते हैं। वे राजीव गांधी जी थे। आज नरेन्द्र भाई मोदी जी हैं, जो कहते हैं, वह करते हैं। अगर 100

रुपये पंचायत को भेजते हैं तो 100 के 100 रुपये पंचायत के विकास के लिए पंचायत के एकाउंट में जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के द्वारा पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि इतिहास में पहली बार अगर बीडीसी के चुनाव जम्मू-कश्मीर में कराए गए, तो नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार में कराए गए। इससे पहले कभी किसी ने हिम्मत ही नहीं की थी।

(1845/NK/SPR)

आज ब्लॉक डेवलपमेंट काउन्सिल के चेयरमैन ने पदभार संभाला है और विकास कार्यों में जुटे हुए हैं। आज जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अमन और शांति है और विकास की गति तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जिक्र किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना था, सबका साथ सबका विकास। इसके साथ ही एक सपना और भी था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा करने के लिए नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने कदम बढ़ाया और वह सपना आज पूरा हो रहा है।

महाराजा जी ने जम्मू-कश्मीर का पूर्ण विलय किया था। धारा 370 की कोई शर्त नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वार्थ की राजनीति के मद्देनजर धारा 370 और 35ए लागू किया। इसे जम्मू-कश्मीर के लोग कई वर्षों तक झेलते रहें। थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेता ने कहा कि देखिए, धारा 370 की समस्याओं और दूसरी समस्याओं का समाधान करने से जम्मू-कश्मीर का भला नहीं हो सकता। मैं जम्मू-कश्मीर का रहने वाला हूं। मैं बता सकता हूं कि इसी से भला हो रहा है। आज वहां पर पर विकास के कार्यों की गति आप देखिए। कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने काम किया है और नरेन्द्र भाई मोदी जी ने देश जोड़ने का काम किया है। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों की तरफ से नरेन्द्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने जम्मू-कश्मीर की बेहतरी के लिए कदम उठाए हैं।

कुछ लोगों ने कहा, विशेष तौर से कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों ने कहा, हमारी बहन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश करते हुए जम्मू-कश्मीर का जिक्र किया तो एक सुर में अपोजिशन के लोगों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर जेल में है, फारूख अब्दुल्ला जेल में हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि फारूख अब्दुल्ला के जेल में रहने से जम्मू-कश्मीर में अमन और शांति होती है तो इसमें ऐतराज क्या है? अगर नहीं तो कोई बताए कि शेख अब्दुल्ला को कई वर्षों तक जेल में किसलिए रखा गया था? उसका भी जवाब दीजिए। वह कई वर्षों तक जेल में रहे थे। अभी फारूख अब्दुल्ला जी को पांच-छह महीने ही हुए हैं।

मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी वह बाहर आएंगे जम्मू-कश्मीर की अमन-शांति और बेहतरी के लिए बात करेंगे।

इन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर जेल में है। जम्मू-कश्मीर जेल में नहीं है, पहले जम्मू-कश्मीर जेल में था। जब से धारा 370 का ताला नरेन्द्र भाई मोदी जी ने तोड़ा है, तब जम्मू-कश्मीर जेल से बाहर आया है। जम्मू-कश्मीर में जीएसटी लागू हुआ, वन नेशन वन टैक्स ने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में पारदर्शिता व्यापार को बढ़ावा दिया है। जीएसटी से पहले दर्जनों टैक्स थे, अब एक ही टैक्स है और वह भी कम हो गया है। सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई हैं।

अंत में यही कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी जी का सपना था कि सीएए को लागू किया जाए। विभाजन के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान के हिन्दु और सिख जो वहां नहीं रहना चाहते हैं, अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं, जिन पर धर्म के आधार पर प्रड़ताड़ना होती है, वे जब भी भारत आएं, उनका मान-सम्मान है, उन्हें यहां के सिटीजनशिप राइट्स मिलने चाहिए। मैं इसका भी समर्थन करता हूं। करतारपुर कॉरीडोर और दिल्ली की कॉलोनियों के लिए जो कदम उठाए गए हैं मैं उसका भी समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ राम जन्मभूमि के फैसले पर आज प्रधान मंत्री जी ने जो वक्तव्य सदन में दिया है, मैं उसका भी समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

(1850/UB/SK)

1849 hours

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): At the outset, I am delighted to inform the House that under the dynamic and able leadership of our Leader, Shri K. Chandrasekhar Rao, the hon. Chief Minister of Telangana, Hyderabad has emerged as no. 1 dynamic city in the country as per the City Momentum Index released by JLL that comprised 129 cities across the world.

Our Government of Telangana is ushering in 2020 as the State's Year of Artificial Intelligence. Telangana has been at the forefront of emerging technologies such as Artificial Intelligence, Blockchain and drones. Hence, steps may be taken to formulate artificial intelligence-specific incentives for its overall development in the State. Earlier, ITIR was sanctioned for Telangana but could not make much progress despite repeated requests.

Telangana IT/ITES exports have gone up to 16.89 per cent during 2018-19 in comparison with expected national average of around 8 to 10 per cent. Telangana IT sector generated direct employment to 5,43,033 with 67,725 new professionals joining the workforce in the last year. KTR, our IT Minister held a series of bilateral meetings with global industry leaders at the Telangana Pavilion on the sidelines of World Economic Forum held in Davos, Switzerland, in the month of January, 2020 and got a good response from various countries for a clean, positive and a healthy environment, and all the national and international companies are preferring Hyderabad to set up and expand their projects as it has a lot of scope for further development.

Our Government of Telangana is encouraging the women entrepreneurs and workers for start-ups with the provision of incubation, incubators and innovation facilities under 'We Hub' and 'T Hub' in collaboration with Australia, Switzerland and other countries. Our Government is providing assistance or loan from Rs. 1 lakh to Rs. 1 crore to such women who contribute about 20 per cent and those men who contribute 80 per cent to make women industrialists with the corpus fund of Rs. 25 crore by giving permissions under TS-IPoS by easing the guidelines. For this purpose, funding and other concessions are needed.

Our Telangana Government has already announced the setting up of a Sanitation Hub (S-Hub), an Incubator to promote start-ups and innovation in water, sanitation, sewage water management and waste water recycling to make cities and towns liveable and healthy. For this purpose, a financial assistance of Rs. 25 crore is needed. (ends)

1853 बजे

श्री मोहम्मद अकबर लोन (बारामूला): ऑनरेबल स्पीकर साहब, देर से ही सही टाइम तो मिला। अपनी बात रखने का आपने जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं। हज़रात, मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि 5 अगस्त को दफा 370 और 35ए को रिवोक किया गया, विदड्रॉ किया गया। उसके बाद पूरे सदन को भी और पूरी कौम को कहा गया, पावर दी गई कि आपको हिन्दुस्तान और कश्मीर के लिए ऐसी राजनीति नहीं करनी है जिससे यहां के लोगों में बदएतमादी पैदा हो।

जनाब, मैं आपसे यह अर्ज़ करना चाहता हूं, आपने कहा कि यहां कोई तालीमी नहीं है, तालीमी प्रोग्राम नहीं है, इसके कारण यहां के अक्सर लोग अनपढ़ हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हमारे पास 1956 से लेकर, जब कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने हुकूमत संभाली, और उस वक्त फ्री एजुकेशन प्राइमरी क्लास से आगे तक दी। …(व्यवधान). You are talking all*… (Not recorded)*.

(1855/MK/KMR)

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): You encourage people to throw stones. …(*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD AKBAR LONE (BARAMULLA): You are talking all *… (Not recorded)*. What are you talking? …(*Interruptions*) *… (Not recorded)*. Be seated.

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): You instigate people to throw stones. You think we do not know? …(*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD AKBAR LONE (BARAMULLA): I know you. Sit down. Do not talk unnecessarily. …(*Interruptions*) बैठ जाओ, यहां *… (Not recorded)* नहीं चलती है। सवाल यह है कि यहां पर यह देखना है कि वर्ष 1956 से लेकर उन्होंने प्राइमरी क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन दे दिया। यहां के कॉलेजेज देखना चाहिए, कितने कॉलेजेज हैं, 5 अगस्त से पहले कितने कॉलेजेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? आप उन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज की तहरीर देख लीजिएगा। इसका मतलब यह है कि हम एजुकेशन में पीछे नहीं थे। इस तरह से अगर हम मानते हैं कि यहां पर तरक्की नहीं हुई, यहां पर तरक्की नहीं हुई है तो जो पुल बनें हैं और अन्य चीजें जो बनी हैं, इसमें शक नहीं है कि ये सब चीजें जो यहां बनाए गए हैं, वह इसी के आधार पर बनाए गए थे। उनको फंडिंग के लिए मरकज ने वक्त-वक्त पर हमें मदद की है और हमने वे चीजें बनाई हैं। आप देख लीजिएगा कि जो कॉलेजेज हमारे पास हैं, जो यूनिवर्सिटीज हमारे पास हैं, उससे पता लगता है कि हमारे पास एजुकेशन में कितनी चीजें मौजूद हैं।

इसी प्रकार मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन और फाइनेंशिएल कमीशन हैं, ये कमीशन्स कहां से कहां आ गए। ये आज से नहीं हैं। ये बहुत जमाने से चले आ रहे हैं। जब से हमारी आजादी हुई, जब हम 1947 में हिन्दुस्तान का हिस्सा बनकर यहां आ गए, हमने ये

कॉलेजेज देख लिए, हमने ये कमीशन्स देख लिए। ये कमीशन्स जो हम आज देख रहे हैं, ये उन्हीं की देन है, उसी वक्त की देन है, उस समय कश्मीर में शेख अब्दुल्ला का क्या रोल रहा है, देख लीजिएगा।

आपके पास एम्स हैं। पूरे हिन्दुस्तान के अंदर एम्स की बढ़ोतरी हुई है। उसके मुकाबले हमारे पास शेर-ए-कश्मीर मेडिकल इंस्टिट्यूट है। उस इंस्टिट्यूट में बहुत सारे बीमार लोग लाए जाते हैं और उनका इलाज किया जाता है। मैं यह नहीं कहूंगा वह एम्स के पैरलेल है, लेकिन एम्स से कुछ कम भी नहीं है। मेरा एक प्वाइंट यह है कि ये झूठ बोलकर …(व्यवधान)

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Sir, he cannot use the word … *(Not recorded)*. It is unparliamentary. He should withdraw it.

SHRI MOHAMMAD AKBAR LONE (BARAMULLA): I withdraw. खुश हो गए ! इसी प्रकार मैं टूरिज्म की बात करना चाहता हूं। टूरिज्म के लिए जम्मू-कश्मीर का टूरिज्म बहुत ही मशहूर है। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? स्पीकर साहब, आप मुतालका टूरिज्म मिनिस्टर साहब से कह दीजिएगा कि वहां पर तीन बड़े झील हैं- वूलर झील, मानसबल झील और डल झील है। इन तीनों झीलों को आप टूरिज्म में शामिल कीजिए। एक और बहुत अहम चीज यह है कि वहां पर जो कमीशन्स हैं, उनको अपने आधार पर चलने दीजिए और साथ-साथ जो उनसे बाबस्ता हैं, उनको और एनकरेजमेंट दी जाए।

(इति)

1859 बजे

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (सम्भल): बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सबसे आखिर में समय दिया है। मैं तीन दिन से इंतजार कर रहा था। ये हिन्दुस्तान सबका है। सब हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं। चाहे वे किसी धर्म के हों, मजहब के हों, बिरादरी के हों, सबको यही रहना है और हमें इस बात पर फख्र है कि हम हिन्दुस्तानी हैं।

(1900/YSH/SNT)

लिहाजा हम हिन्दुस्तान में रहकर बेहैसियत मुसलमान की जिंदगी गुजारते हैं। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह हमारे साथ इंसाफ करे। जब तक देश के अन्दर इंसाफ और हमदर्दी नहीं होगी, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। इस वक्त देश में हालात बहुत खराब हैं और लोग शाहीन बाग में, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में और जेएनयू में धरने पर बैठे हैं। वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं सीएए, एनसीआर और एनपीआर की मुख़ालफत करता हूं। इस बात की मांग भी करता हूं कि सरकार इसे वापस ले। हमारी माँ-बहनें, बेटियां, बच्चियां और बूढ़ी औरतें, बूढे लोग धरने पर बैठे हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह एनसीआर का विरोध है या एनआरसी का विरोध है? आपने कहा कि यह एनसीआर का विरोध है।

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (सम्भल): मैंने यह कहा है कि इस सिलसिले में कोई बात नहीं की गई है। आपने मेरा सारा समय तो ले ही लिया है।

"मेरी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों,
गुजरनी एक दिन सिर से तुम्हारे भी कयामत है। "

आप यह समझ लीजिए। इसलिए ज्यादा जुल्म करना अच्छा नहीं होता है। हिन्दुस्तान के अन्दर भाईचारा पैदा कीजिए। इत्तेहाद पैदा कीजिए। अगर मुल्क को नया देश बनाना है, अच्छा मुल्क बनाना है, तरक्की याफता मुल्क बनाना है तो हमें एक-दूसरे से मोहब्बत करनी होगी। हमें एक दूसरे की इज्ज़त करनी होगी। हमारा देश तब ही आगे बढ़ सकता है। आखिरी में, मैं एक शेर पढ़कर अपनी बात खत्म करता हूं।

"अभी क्या है कल एक-एक बूंद को तरसेगा मयखाना,
जो एहलेज़र्फ के हाथों में पैमाने नहीं आए। "

हर मुल्क के अन्दर पार्टियां बदलती रहती हैं। हुकूमत बदलती रहती हैं। यहां पर भी एक दिन हुकूमत बदल जाएगी। महामहिम राष्ट्रपति ने यहां पर जो खुतबा पढ़ा और जो पॉलिसी पेश की है, उस पॉलिसी से मुझे इत्तेफाक नहीं है। यहां पर आवाम के लिए बिल नहीं लाया गया है। आवाम के लिए गरीबों के लिए, किसानों के लिए उसमें कुछ नहीं है। इस देश में महंगाई बढ़ गई है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। हमारी जीडीपी आज कहां पर पहुंच चुकी है।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन का समय सात बजे तक था। तीन सदस्य 15 मिनट के अन्दर अपनी बात को समाप्त कर दें।

1904 hours

SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakkam, Speaker Sir! Thank you for giving me an opportunity. I rise to oppose the Motion of Thanks on the President's Address.

Sir, it seems to be a basket of empty promises. Agriculture is the backbone of our Indian economy but nothing has been done to address the agriculture sector. The long-standing demand of agricultural loan waiver has not been addressed. Lots of improvements in modern techniques in agriculture like low usage of land with less amount of water to produce more agricultural products, etc. are not being implemented. The schemes are not being given any importance.

There are a lot of PSUs. There has been a downward trend in economy. There is no proper roadmap to put the economy on road. The PSUs which have been brought up by the federal States with a lot of Government efforts, with a lot of struggles, with lot of protests, and with s lot of legal backing have now gone into disinvestment.

(1905/GM/RPS)

There are no signs of investment at all. The disinvestment of Salem Steel Plant, BHEL, BPCL, followed by disinvestment of Air India and soon to be followed by BSNL, shows that the economy is not in place. State federalism is not being given due importance. The Resolution of the State Assembly demanding exemption from NEET has not been taken into consideration by the Government. Besides, the State Cabinet's recommendation for release of seven persons including that of Perarivalan has not been accepted yet. This Government has a brutal majority, but it is not magnanimous enough to include social justice, empowerment of women and children, down-trodden, and the marginalized. So, I expect the Government to have more inclusive growth in its policy towards State federalism.

This is not only a Government of those who have voted for it. Our State of Tamil Nadu has not voted for this Government, but it represents us also. That is the beauty of the democracy. The long failure of the Government is being seen in curfew being imposed in Kashmir, a lot of leaders being taken into custody, and the ban of internet. The failure of the Government has been seen in the fear of the protest being held at Shaheen Bagh, at the universities, and in use of

police force and tear gas at Jamia Milia University and Aligarh Muslim University. The very utterance at the JNU sends shivers down the spine of the Government. The failure of the Government is represented in taking an 11-year old into interrogation. The fear of the Government is also seen in taking a 9-year old in Bidar, who stood against CAA, for investigation. These types of policies are what we are seeing. What we see is *sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas* which translates into Tamil as *ellorukkumana valarchi* and *ellorukkumana oru nambikkai aanaal adhu oru ematramagathan irukkiradhu.* It is generally seen as the Government of *sabka … (Not recorded)*

.

(ends)

1907 बजे

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): महोदय, मैं सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने सरकार की उपलब्धि भी बताई, साथ ही 2020 भारत का दशक होगा, इसके लिए उन्होंने मार्गदर्शन भी किया है। नरेन्द्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी की लीडरशिप में देश में जो बहुत सारे पुराने इश्यूज चल रहे थे, वे सब एक-एक करके हल हुए है, चाहे वह अनुच्छेद 370 हो, अनुच्छेद 35ए हो, ट्रिपल तलाक हो, बोड़ो इश्यू, ब्रू-रियांग की समस्या हो या फिर श्रीराम मन्दिर हो। नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, दीदी ने विस्तार से नॉर्थ ईस्ट की उपलब्धियां बताई हैं। 72 साल तक नॉर्थ ईस्ट अनदेखा था, लेकिन पिछले पांच सालों से वहां तेजी से विकास हो रहा है।

टीएमसी की हमारी एक साथी ने कहा कि वे वहां के गार्जियन हैं और देश में डेमोक्रेसी के रक्षक हैं। मेरे दो-चार प्रश्न उनके लिए हैं। देखिए, आज बंगाल में रोज डेमोक्रेसी की हत्या होती है। वहां महामहिम गवर्नर साहब का रोज अपमान होता है। महिलाओं के ऊपर रोज अत्याचार हो रहे हैं, पुलिस की एट्रोसिटीज हो रही हैं, पोलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं, 25 हजार लोग घर से बाहर रहने को मजबूर हैं। केवल दार्जिलिंग पहाड़ में 5,000 से ज्यादा युवा आज घर से बाहर हैं। एमपी और एमएलएज पर आए दिन हमले होते हैं। पीएमजीएसवाई, आरआईडीएफ और मनरेगा में घोटाले हो रहे हैं। चिटफण्ड घोटाला हुआ है। फॉरेस्ट्स राइट्स एक्ट, 2006 अभी तक बंगाल में लागू नहीं हुआ है। दार्जिलिंग हिल के अन्दर वर्ष 2005 से लेकर आज 2020 तक कोई पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं। मुझे मंत्री जी के एक जवाब से पता चला कि वर्ष 2016 से 2020 के बीच में करीब 500 करोड़ रुपये का नुकसान उस क्षेत्र को हुआ है। म्युनिसिपैलिटी और कारपोरेशन ब्यूरोक्रैट्स के थ्रू चलाए जा रहे हैं। चाय बागान और सिंकोना बागान में काम करने वाले मजदूरों को आज तक लैण्ड राइट्स और पट्टे नहीं मिले हैं। सीएए के बारे में लगातार निगेटिव प्रचार वहां पर हो रहा है और आए दिन हमें सेकुलरिज्म के बारे में पाठ पढ़ाया जाता है। मुझे ध्यान है कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी से देश के प्रधान मंत्री होते थे, वे स्वयं, कांग्रेस के मुख्य मंत्री और टीएमसी के बहुत सारे नेता कहते थे कि जो हिन्दू बांग्लादेश से या पाकिस्तान से आए, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए।

(1910/RAJ/RK)

हमारी सरकार ने एक स्टेप आगे जा कर, उन तीन देशों में जितने माइनॉरिटीज थे, सभी को नागरिकता देने का काम किया है। मैं अपने क्षेत्र के कुछ बिन्दु आपके सामने रखना चाहूंगा।

सर, ऐसा हो रहा है कि लगातार जाने-अनजाने आए दिन गोरखाओं के बारे में गलत बातें बोली जाती हैं और बार-बार उनका अपमान होता है। गोरखाओं के बारे में यह कहा जाता है कि 1950 इंडिया-नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी के कारण वे यहां पर सेफ हैं, उनको एनआरसी या सीएए से कोई खतरा नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि गोरखा का इतिहास हिन्दुस्तान में इंडो-नेपाल ट्रीटी के कारण नहीं है। हमारा इतिहास अलग है। दार्जिलिंग तराई और डुआर्स का इतिहास अलग है, नॉर्थ-ईस्ट का इतिहास अलग है, उत्तराखंड का इतिहास अलग है, जैसे तमिल बोलने वाले श्रीलंकन नहीं होते हैं और बंगाली बोलने वाले बांग्लादेशी नहीं होते हैं, इसी तरह नेपाली बोलने वाले सभी नेपाल के नागरिक नहीं है, वे हिन्दुस्तान के ही डेढ़ करोड़ नागरिक हैं। दुर्गामल जी की प्रतिमा पार्लियामेंट के

सामने लगी हुई है, उन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है। हरि बहादुर डम्बर सिंह गुरुंग इस कॉंस्टीटुएंट असेम्बली के मेम्बर रह चुके हैं। राम सिंह जी ने 'कदम-कदम बढ़ाए जा', गीत की धुन दी। ऐसे हजारों लोग इस देश के लिए आज तक बलिदान देते आए हैं।

अत: मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि 1941 तक गोरखा हिल ट्राइब के नाते जाने जाते थे, आज वह अधिकार छिना गया है। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से उनको पुन: ट्राइबल स्टेटस का दर्जा मिले। अंत में, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे पूरे क्षेत्र में जैसा कि अभी एक माननीय सांसद जी भी कह रहे थे कि बार-बार गोरखालैंड को लेकर आंदोलन होते रहे हैं। वर्ष 2017 में भी बड़ा आंदोलन हुआ था। आज देश की बहुत सारी समस्या सॉल्व हो गई है। हमारी पार्टी ने वर्ष 2019 में इस बात का जिक्र किया है कि उस क्षेत्र के लिए हम परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन करेंगे। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि जिस तरह से देश के अनेक इश्यूज रिजॉल्व हुए, इसका भी समाधान जल्द से जल्द ढूंढ़ा जाए। इस प्रक्रिया के लिए काम जल्द से जल्द चालू कर दिए जाएं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1912 बजे

श्री अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): माननीय अध्यक्ष जी मैं आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है।

मान्यवर, 2014 से पूर्व देश की स्थिति पर गौर करेंगे, तो पूरा परिदृश्य आँखों के सामने आयेगा। देश में कुहासा था, हर आदमी टूटा था, क्योंकि रोज एक घोटाला और एक मंत्री हर महीने जेल जाता था। देश की जनता को लगता था कि देश के भविष्य का क्या होगा, कौन बचाएगा और भष्ट्राचार की कतार में हम सबसे आगे आने लगे थे। सीमाएं असुरक्षित थीं, माताओं-बहिनों की सुरक्षा तार-2 हो रही थी, हमसे वैर रखने वाले देश हमें आँखें दिखाते थे। वे हमारी सीमाओं का उल्लंघन करते रहते थे। बेरोजगारी मुंह फाड़े खड़ी थी। चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था चरमरा गई थी। कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, माओवाद अपना पैर पसार रहा था। ऐसे में जब माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने बागडोर सभाली तो पूरे देश में उत्साह का वातावरण आ गया। सभी बातों को कहने के लिए समय नहीं है, लेकिन मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं।

देश का हर नागरिक उत्साहित हुआ उसके आत्म सम्मान में वृद्धि हुई, आत्म सम्मान से लबालब भर गया। देश को लगा कि अब कोई हमारा रखवाला आ गया, कोई सिरमौर आ गया है। आतंकवाद पर एवं माओवाद पर शिकंजा कस दिया, भष्ट्राचार पर लगाम लगी।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुर्सी संभालते ही भष्ट्राचार पर लगाम लगाने वाले फाइल पर साइन किए। सेना में महिला पायलट की नियुक्ति हुई। सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिला जज आईं। मातृ शक्ति की सुरक्षा के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया। मोदी जी ने तुरंत SIT का गठन किया, विदेशों से बैक खातों की तलाश हुई, स्विट्जरलैण्ड से करार हुआ, इसके लिए कानून पास किया। सीमाओं की चौकसी बढी, डोकलाम में चीन को पीछे धकेल दिया। चीन की सीमा तक सड़क पहुंचा दी। सेना के बीच में प्रधानमंत्री जी ने दीवाली मनाई। सेना को अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकार दिया, जिससे आतंकवादियों के कैम्प एक के बाद एक ध्वस्त हुए। पाकिस्तान को जबरदस्त झटका लगा। उरी की घटना के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक कर पूरे विश्व में भारत की सैन्य शक्ति का डंका बजा। पुलवामा की घटना के बाद, एयर स्ट्राइक का पूरे विश्व में हमारी "एयरफोर्स' की क्षमता एवं दक्षता के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ, C.D.S. की नियुक्ति की गई। बेरोजगारी पर लगाम लगाई गई, स्टार्ट अप, मेक इन इंडिया तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाएं बनाईं। कौशल विकास योजना से आज हजारों युवक रोजगार पा रहे हैं। किसानों की फसल के नुकसान होने पर कड़े कानून को शिथिल किया।

(1915/VB/PS)

किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि सीधे दी गई, जन-धन खाते खोलकर आम आदमी को सम्मान दिलाया गया, बिचौलियों की व्यवस्था को समाप्त करके सीधे लाभार्थियों के खातों में धनराशि जा रही है।

अंतरीक्ष में सबसे अधिक उपग्रह छोड़कर विश्व में प्रथम पायदान पर खड़े हुए, दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनकर फ्रांस को पीछे कर दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, देश की अस्थिर राजनीति को स्थिर किया।

एक देश, एक टैक्स को लागू करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है, का सन्देश दिया। नोटबन्दी करके कालाधन जब्त किया, जिसके कारण तिजोरियों और तहखानों में रखे धन आज कागज़ के टुकड़े हो गए हैं। वर्ष 2009 से 2014 के बीच विदेश मुद्रा के रूप में आए 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ाकर वर्ष 2014 से 2019 के दौरान 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा दिया, जिससे विदेशी मुद्रा का भंडार 450 बिलियन डॉलर हो गया।

माननीय अध्यक्ष: आपकी लिस्ट पूरी हो गई।

श्री अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): मान्यवर, यह लिस्ट लम्बी है। इसलिए मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त करूँगा।

मान्यवर, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होते हैं। इसके बिना काम चल भी नहीं सकता है। विपक्ष का काम ट्रेजरी बेंच को राह दिखाना है। लेकिन जब विपक्ष गैर-जिम्मेदाराना होता है, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र को खतरा होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रभु लोकतंत्र को पुख्ता करने के लिए विपक्ष को सद्भावना दें और जो भी मोदी जी के विपरीत जा रहे हैं....

(इति)

***श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर):**

---

* Laid on the Table

***श्री राम शिरोमणि (श्रावस्ती):**

---

* Laid on the Table

***श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत):**

---

* Laid on the Table

***डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर):**

---

* Laid on the Table

***श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा):**

---

* Laid on the Table

***श्री रामचरण बोहरा (जयपुर):**

---

* Laid on the Table

*श्रीमती रीती पाठक (सीधी):

---

* Laid on the Table

***श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद):**

---

* Laid on the Table

***श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी):**

---

* Laid on the Table

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 6 फरवरी, 2020 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1916 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, दिनांक 06 फरवरी, 2020/17 माघ, 1941 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।